सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 39, नई दिल्ली । शनिवार, 19 अप्रैल 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में भारी बारिश
06 शिक्षा और रोजगार को पाटना
08 झारखंड के मुख्यमंत्री ने योजनाओं का लिया जायजा, तय समय में जनता को समर्पित

22 अप्रैल से दिल्ली के लोगों को मिलेगी 'देवी' बस सेवा, जान लीजिए किराया से लेकर पूरा रूट

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली के लोगों की सहूलियत के लिए सरकार जल्द ही एक सेवा शुरू करने वाली है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि सरकार 22 अप्रैल को दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरचेंज (देवी) के बैनर तले अपनी मोहल्ला इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में नौ मीटर लंबी 255 बसें सर्विस में लगाई जाएंगी। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा पहले मोहल्ला बस सेवा के नाम से जानी जाने वाली इस सेवा से राजधानी में अंतिम मील की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

बस का रूट तय

परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "आज ज्यादातर रूट तय कर दिए गए हैं और शुरुआती प्रतिक्रिया की समीक्षा के बाद मांग के अनुसार और रूट जोड़े जाएंगे। इसके पीछे आइडिया यह है कि आंतरिक सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ने वाले छोटे रूटों को शामिल किया जाए, ताकि ये बसें उन इलाकों में सर्विस दे सकें जहां बड़ी बसों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।" आप सरकार के सिग्नेचर "मोहल्ला क्लीनिक" को "आरोग्य मंदिर" के नाम से रीब्रांड किया जा रहा है, और "मोहल्ला बसों" को "देवी बसों" के नाम से लॉन्च किया जाएगा।

फीडर के तौर पर भी करेंगी काम

अधिकारियों ने बताया कि बसों का पहला जत्था गाजीपुर, नांगलोई और ईस्ट विनोद नगर डिपो से संचालित होगा। ये बसें दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के प्रमुख बस मार्गों और मेट्रो स्टेशनों के लिए फीडर के तौर पर काम करेंगी। उन्होंने कहा कि हर बस से 12 किलोमीटर का रूट तय करने की उम्मीद है और प्रत्येक डिपो में ऐसी 100 बसें खड़ी की जा सकती हैं। देवी सर्विस दिल्ली सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन को उन्नत करने और इसे अधिक टिकाऊ बनाने की व्यापक कोशिश का हिस्सा है।

कितने रुपए की होंगी टिकट

अधिकारियों ने कहा कि मोहल्ला बस योजना के तहत प्रस्तावित किराए में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसमें 10, 15, 20 और 25 रुपए के टिकट प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं पिंक टिकट का उपयोग करके मुफ्त सफर का लाभ उठा सकती हैं। प्रत्येक देवी बस में 23 सीटें होंगी, जिनमें से छह महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, और 13 खड़े यात्रियों के लिए जगह होगी। अधिकारियों ने कहा कि वे 196 किलोवाट की कुल क्षमता वाले छह बैटरी पैक से लैस हैं, और 45 मिनट का चार्ज 200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा को सुविधाजनक बना सकता है।

परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने हाल ही में सतत गतिशीलता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। पिछले महीने, उन्होंने 2025 के अंत तक बसों के बेड़े को 10,000 से अधिक बसों तक बढ़ाने की घोषणा की, जिसमें 80 फीसदी इलेक्ट्रिक होंगी।

अति विशेष सूचना

"परिवहन विशेष" हिन्दी दैनिक समाचार पत्र आर.एन.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त करने के बाद से आपके द्वारा प्राप्त भरपूर सहयोग से मार्च में अपने 2 साल पूरे कर चुका है। इन दो सालों में समाचार पत्र को निष्पक्ष रूप से चलाने में आप सभी का भरपूर सहयोग रहा हैं जिसके लिए प्रशासनिक विभाग परिवहन विशेष आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता है और आशा करता है की भविष्य में भी आपका सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। इन दो सालों में समाचार पत्र को राष्ट्रीय स्तर पर सभी शहरों और जिलों तक पहुंचाने और वहां की सही और सच्ची खबरें हम तक पहुंचाने वाले रिपोर्टर्स का दिल से धन्यवाद।

आप सभी को यह जान कर खुशी होगी की "परिवहन विशेष हिन्दी दैनिक समाचार पत्र" का द्वितीय वार्षिकी समारोह अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में सम्पन्न किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सड़को को जाम और दुर्घटनाओं से मुक्त करवाने के साथ दिल्ली को प्रदूषण मुक्त राज्य का उद्देश्य रखा गया है। इस समारोह में निम्नलिखित मुद्दों पर वाद- विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा

1. लेन ड्राइविंग कितनी अनिवार्य?"
2. "सड़क दुर्घटना से कैसे हो सकता हैं बचाव ?"
3. "दिल्ली को कैसे प्रदूषण मुक्त राज्य बनाया जा सकता है?"

वाद- विवाद प्रतियोगिता में हिस्सेदारी लेने वाले वक्ताओं के वक्तव्य के साथ परामर्शदाताओं से चर्चा भी इस समारोह में रखी जा रही है। इसके साथ इस आयोजन में भारत देश में निर्मित ई वाहनो, वींएलटीडी संयंत्र, एवम् अन्य उपयोगी स्टाल भी सब को आकृषित करने के लिए उपलब्ध होंगे। इस समारोह में

1. सबसे अच्छा विचार / तर्क और समाधान प्रदान करने वाले वक्ता को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
2. परिवहन क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले संगठनों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
3. सड़क सुरक्षा के प्रति कार्य करने वाले संगठनों के पदाधिकारियों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
4. परिवहन विशेषज्ञों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
5. समाचार पत्र से अलग अलग राज्यों से जुड़े एंकर, वीडियो ग्राफर, रिपोर्टर्स, लेखक, ज्योताचार्य, कवि एवम् सहायकों को सम्मानित किया जाएगा।

संजय कुमार बाटला
संपादक

ये है देश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे जानें किस गाड़ी पर कितना है टोल ?

भारत में अगर कोई वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो उसे टोल चुकाना पड़ता है। एक्सप्रेसवे के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा करना आसान हो जाता है। इससे समय बच जाता है। जब भी आप एक्सप्रेसवे पर जाएंगे तो आपको कई टोल प्लाजा मिलेंगे जहां आपको टोल देना होगा।

नई दिल्ली। एनएचएआई भारत के सभी एक्सप्रेसवे की देखभाल करती है। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत के सभी टोल की कीमत भी तय करता है। आज हम आपको देश के सबसे महंगे एक्सप्रेसवे के बारे में बताने जा रहे हैं। यहां आपको सबसे ज्यादा टोल चुकाना पड़ता है।

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे

क्या आपको देश के सबसे ज्यादा टोल टैक्स कहां देना पड़ता है। अगर आप मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे से यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको ज्यादा टोल टैक्स चुकाना होगा। मुंबई-पुणे एक्सप्रेस देश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेस-वे की कुल दूरी 94 KM है।

जानें कितना देना होता है टोल

अगर आप भी मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 4 व्हीलर्स लेकर जा रहे हैं तो आपको 320 रुपये का टोल टैक्स देना होगा। यह भारत में दूरी से हिसाब से ज्यादा है। अगर आप मिनी बस या टैम्पो से जाते हैं तो आपको 495 रुपये चुकाने होंगे। वहीं बस से जाने पर आपको 940 रुपये टोल देना होगा। इस एक्सप्रेसवे पर प्रति KM 3.40 रुपये है। यह भारत के बाकी एक्सप्रेसवे से 1 रुपये ज्यादा है। मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे के टोल प्लाजा पर हर साल 6 प्रतिशत की छूट मिलती है।

साल 2002 में बना

यह एक्सप्रेसवे साल 2002 में लगभग 1630 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ था। यह देश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे होने के साथ -साथ सबसे व्यस्त एक्सप्रेस-वे भी है।

दिल्ली से मसूरी आ रही बस कमानी टूटने से रोड पर पलटी

देहरादून। कश्मीरी गेट से 27 सवारियों को लेकर बस रात 11 बजे चली थी। सुबह मसूरी पानी वाला बैंड पर पहुंचने पर बस की कमानी टूट गई, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। पानी वाला बैंड के पास सुबह एक बस रोड पर पलट गई। सूचना पर थाना कोतवाली मसूरी से प्रभारी निरीक्षक, चौकी प्रभारी बालूगंज थाने से पर्याप्त पुलिस बल आपदा उपकरण सहित तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुए। मौके पर जाकर देखा तो एक बस रोड पर पलटी हुई थी। जिसमें कुल 27 लोग सवार थे।

जानकारी मिली बस रात्रि 11:00 बजे कश्मीरी गेट दिल्ली से मसूरी के लिए चली थी। जैसे ही बस पानी वाला बैंड के पास पहुंची तभी अचानक कामनी टूटने के कारण अनियंत्रित होकर रोड पर ही पलट गई। बस काफी धीमी रफ्तार से चल रही थी। कुल 27 लोग सवार थे, जो दिल्ली से मसूरी आ रहे थे।

बस पलटने के कारण बस में बैठे एक यात्री अर्चित शुक्ला पुत्र गिरीश चंद शुक्ला निवासी दिल्ली को मामूली चोटें आई हैं, जिसे 108 के माध्यम से अस्पताल भेजा गया है। शेष सभी लोग सुरक्षित हैं। उन्हें प्राइवेट वाहनों से मसूरी भेजा गया है। बस को चालक जसवंत (25) निवासी विजय पार्क मौजपुर दिल्ली चला रहा था।

आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन प्री-क्लियरेंस सुविधा शुरू करने की तैयारी

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर अमेरिका की कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन प्री-क्लियरेंस सुविधा शुरू करने की तैयारी है। इससे अमेरिका जाने वाले यात्रियों की कस्टम्स और इमिग्रेशन जांच दिल्ली में ही हो जाएगी। यात्री अमेरिका पहुंचने पर सीधे अपना सामान लेकर बाहर निकल सकेंगे। इस सुविधा से आईजीआई एयरपोर्ट एक ग्लोबल हब बन सकेगा और उड़ानों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। कल्पना कीजिए कि आप आईजीआई एयरपोर्ट से न्यूयार्क की उड़ान ली और वहां लैंडिंग के बाद आप बिना किसी तामझाम के बिल्कुल घरेलू यात्री के जैसे एयरपोर्ट से सीधे बाहर निकल गए।

आपको न तो इमिग्रेशन और न ही कस्टम क्लियरेंस का सामना करना पड़ा। अभी यह बात आपको भले ही अटपटी लग रही हो लेकिन आने वाले समय में ऐसा संभव हो सकता है।

फिलहाल असंभव सी लगने वाली यह बात संभव हो सके इसकी कवायद शुरू की जा चुकी है। आईजीआई एयरपोर्ट संचालन एजेंसी डायल ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि आईजीआई एयरपोर्ट पर अमेरिका की कस्टम्स एंड बार्डर प्रोटेक्शन प्री-क्लियरेंस सुविधा शुरू की जाए।

इस सुविधा में अमेरिका जाने वाले यात्रियों की कस्टम्स और इमिग्रेशन जांच दिल्ली में ही हो जाएगी। इससे यात्री अमेरिका पहुंचने पर सीधे अपना सामान लेकर बाहर निकल सकेंगे।

क्यों पड़ी इसकी जरूरत

डायल की कोशिश है कि आईजीआई एयरपोर्ट को ग्लोबल हब बनाया जाए। ऐसा तभी संभव है जब यात्रियों को यहां ऐसी सुविधाएं मिलें, जिसके आधार पर उनकी यात्रा के पूरे प्लान में आईजीआई एयरपोर्ट शामिल हो। खासकर विदेश यात्रा से जुड़े प्लान में तो हो ही।

अभी भारत से यदि कोई यात्री अमेरिका की यात्रा करता है तो वहां के एयरपोर्ट पर उसे सामान्य सुरक्षा प्रोटोकाल की प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसमें इमिग्रेशन व कस्टम से जुड़ी जांच शामिल है। लेकिन कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनका अमेरिका की कस्टम्स एंड बार्डर प्रोटेक्शन एजेंसी से समझौता है।

एयरपोर्ट पर प्री-क्लियरेंस सुविधा उपलब्ध

समझौते के तहत सीबीपी एजेंसी संबंधित एयरपोर्ट पर प्री-क्लियरेंस सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके तहत जांच की जो प्रक्रिया अमेरिका में उतरने के बाद होनी होती है, वह यात्रा के आरंभ बिंदू पर ही हो जाता है।

इससे यात्रियों को अमेरिका की एयरपोर्ट पर लगने वाली लंबी कतार से मुक्ति मिल जाती है। यात्री विमान से उतरने के बाद आसानी से एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है।

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कई यात्री अमेरिका की यात्रा के लिए विदेश के उस एयरपोर्ट को चुनते हैं जहां सीबीपी प्री-क्लियरेंस सुविधा उपलब्ध करा रही है।

यदि आईजीआई एयरपोर्ट पर यह सुविधा शुरू हो जाए तो न केवल घरेलू बल्कि विदेशी यात्री भी आईजीआई एयरपोर्ट से अमेरिका की उड़ान लेना पसंद करेंगे।

बढ़ जाएंगी उड़ानों की संख्या

डायल का मानना है कि यदि ऐसा हुआ तो संभव है कि एयरलाइंस अमेरिका की उड़ानों की संख्या बढ़ा दें। अभी एअर इंडिया दिल्ली से अमेरिका के लिए हर हफ्ते 33 से ज्यादा सीधी उड़ानें संचालित करती हैं। इसके अलावा, यूनाइटेड एयरलाइंस और अमेरिकन एयरलाइंस भी अमेरिका के लिए उड़ानें संचालित करती हैं।

बिहार-यूपी के यात्रियों के लिए खुशखबरी ! दिल्ली से मिलेगी अब कन्फर्म टिकट...

गर्मी में बिहार और यूपी जानेनाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में रेलवे को विशेष ट्रेनें चलानी पड़ती है। इसी बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली से सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर दरभंगा जोगबनी और अयोध्या के लिए गर्मी विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें अप्रैल से जुलाई तक चलेंगी जिससे यात्रियों को इन मार्गों पर सुविधा होगी।

नई दिल्ली। ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए रेलवे ने गर्मी विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा शुरू कर दी है। उत्तर रेलवे ने सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जोगबनी और अयोध्या कैंट के लिए गर्मी विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इनमें से अधिकांश ट्रेनें जुलाई तक चलेंगी।

आनंद विहार टर्मिनल-सीतामढ़ी विशेष (04098/04097)

आनंद विहार टर्मिनल से 22 अप्रैल से 11 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को सुबह पांच बजे चलेगी और अगले दिन मध्य तड़के ढाई बजे सीतामढ़ी पहुंचेगी। वापसी में 23 अप्रैल से 12 जुलाई तक प्रत्येक बुधवार व शनिवार को सीतामढ़ी से सुबह पौने चार बजे चलकर अगले दिन मध्य रात्रि डेढ़ बजे आनंद विहार टर्मिलन पहुंचेगी।

आनंद विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर विशेष (04030/04029)

आनंद विहार टर्मिनल से 22 अप्रैल से 17 मई तक मंगलवार व शनिवार को सुबह नौ बजे चलेगी और अगले दिन सुबह साढ़े चार बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। वापसी 23 अप्रैल से 18 मई तक बुधवार व रविवार को सुबह सवा छह बजे चलकर अगले दिन सुबह 3.10 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।

पुरानी दिल्ली-दरभंगा विशेष (04012/04011)

22 अप्रैल से 11 जुलाई तक पुरानी दिल्ली से प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को शाम साढ़े सात बजे रवाना होकर अगले दिन देर शाम साढ़े आठ बजे दरभंगा पहुंचेगी। वापसी में 23 अप्रैल से 12 जुलाई तक प्रत्येक बुधवार और शनिवार को दरभंगा से रात 10 बजे चलकर अगले दिन रात 10.40 बजे पुरानी दिल्ली पहुंचेगी।

आनंद विहार टर्मिनल-जोगबनी टर्मिनल विशेष (04094/04093)

24 अप्रैल से 10 जुलाई तक आनंद विहार टर्मिनल से प्रत्येक बृहस्पतिवार को रात 11.55 बजे चलेगी और तीसरे दिन सुबह साढ़े सात बजे जोगबनी पहुंचेगी। वापसी में 26 अप्रैल से 12 जुलाई तक प्रत्येक शनिवार को जोगबनी से सुबह साढ़े नौ बजे चलकर अगले दिन शाम चार बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचगी।

अयोध्या कैंट-आनंद विहार टर्मिनल विशेष (04213/04214)

20 अप्रैल से 10 जुलाई तक रविवार, मंगलवार व बृहस्पतिवार को शाम 6.20 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह छह बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वापसी में 21 अप्रैल से 11 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को आनंद विहार टर्मिनल से सुबह नौ बजे चलकर रात 10 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी।

कन्यादान एक महादान!

एक ब्राह्मण ने कहा- भगवन् ! यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो अब कन्यादान के फल का वर्णन कीजिये साथ ही उसकी यथार्थ विधि भी बतलाइये। मैने सुना है कि जिसके यहाँ पुत्री का जन्म हो जाता है उस पिता के लिए स्वर्ग के द्वार सहज ही खुल जाते हैं। हे प्रभु ! एक संन्यासी तपस्या व त्याग से जो फल प्राप्त करता है उसका आधा तो मात्र दो प्रकार की संस्कारित और सुशील कन्याओं का कन्यादान करने पर प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान्‌-बोले- हे ब्राह्मण ! तुमने जनहित के संदर्भ में यह उत्तम वचन कहे। परंतु महाफल के लिए मात्र दो घड़ी की कन्यादान प्रक्रिया ही पर्याप्त नहीं होती। इसके लिए वर भी गुणवान होना चाहिए। यदि मदिरा सेवी, परस्त्री गामी अथवा चोर, रोगी और अंगहीन, निर्धन और नास्तिक को अपनी कन्या का दान किया तो ऐसा कन्यादान वैसा ही दण्ड का कारण बनता है जैसा कि शालग्राम से तुलसी पत्र हटाने का दण्ड विधान है। हे ब्राह्मण! रूपवान्, गुणवान्, कुलीन, तरुण, समृद्धिशाली सात्तविक और धन-धान्य से सम्पन्न वर को कन्यादान करने का जो फल होता है ; उसी फल को सम्यक फल माना जाए। अतः उसे ही श्रवण करो। जो मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार आभूषणों से युक्त कन्या का दान वर को करता है, उसके द्वारा पर्वत, वन और काननों सहित सम्पूर्ण पृथ्वी का दान हो जाता है ऐसे पिता को अन्य दान महादान की आवश्यकता नहीं। वह अपनी संपत्ति का अंश कन्या को व वर को दान करने से ही सभी प्रकार के भय से मुक्त होकर सभी प्रकार के दानों व यज्ञ तीर्थ आदि के महान फलों का अधिकारी हो जाता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में कन्या की प्राप्ति नवनिधि की प्राप्ति के समान ही फलदायक होती है अतः उस निधि की सुरक्षा करना ही पिता, माता, पितामह, अग्रज आदि का कर्तव्य है। परंतु कुछ लोभी पिता कन्या का विक्रय भी करते हैं यह घोर पाप है। जो पिता कन्या का शुल्क लेकर कन्यादान करके उस धन को खाता है, वह नरक में पड़ता है। जो मूर्ख अपनी पुत्री को बेच देता है अथवा कन्या को धन का साधन बनाकर उसके देह से धनार्जन करता है अथवा कन्या को माध्यम बनाकर कन्या के वर पक्ष में अशान्ति (विद्रोह, फूटन, लड़ाई, झगड़े) उत्पन्न करता है। उस पिता का अथवा उस कन्या की माता का कभी नरक से उद्धार नहीं होता।

1. जो पापी पिता धन के लोभ से अयोग्य पुरुष को , वृद्ध अथवा रोगी पुरुष को अपनी कन्या का कन्यादान कर देता है, वह रौरव नरक में पड़कर अन्त में चाण्डाल होता है। (इसी से विद्वान्-पुरुष दामाद से शुल्क लेने का कभी विचार भी मन में नहीं लाते। वह कन्या का स्वामी आजीवन उस कन्या की रक्षा करता है इस भाव से स्वयं ही वर को स्वेच्छा पूर्वक धन धान्य देना चाहिए पर लोभी वर को कन्या देने का विचार त्याग देना चाहिए),

2. अपनी ओर से पिता द्वारा उस वर को जो कुछ दिया जाता है, वह सब मन्वादि तिथियों की भांति अक्षय हो जाता है।

3. पृथ्वी, गौ, सोना, धन-धान्य और वस्त्र आदि जो कुछ भी वर (दामाद) को दहेज के रूप में दिया जाता है, सब अक्षय फल का देने वाला होता है।

4. जैसे कटी हुई डोर घड़े के साथ स्वयं भी कुएँ में डूब जाती है, उसी प्रकार दाता पिता यदि संकल्प किये हुए दान को भूल जाता है और दान लेने वाला पुरुष फिर उसे याद दिलाकर माँगता नहीं तो वे दोनों नरक में पड़ते हैं।

5. सात्त्विक पुरुष को उचित है कि वह जामाता को दहेज में देने के लिये निश्चित की हुई सभी वस्तुएँ अवश्य दे डाले। (अथवा देने का संकल्प न करें) न देने पर पहले तो वह नरक में पड़ता है; फिर प्रतिग्रह लेने वाले के दास के रूप में जन्म ग्रहण करता है।

पद्म पुराण के अनुसार ऐसे वर को कन्या न दें-

1. जो बहुत खाता हो और अभक्ष्य भी भक्ष्य समझता हो (जिसे देह की निरोगता की परवाह न हो)

2. अधिक दूर रहता हो (ऐसे में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं)

3. अत्यधिक धनवान्हो (और कन्या का पिता मध्यमवर्ग का हो या निर्धन),

4. जो भले ही धनवान हो पर जिसमें अधिक दुष्टता हो या जो द्विज हो तो संध्या हीन होने पर भी उस वर को कन्या न दें , संध्या हीन द्विज (वर) कुलीन कन्या के योग्य नही

5. जिसका कुल उत्तम न हो तथा जिस वर के माता पिता दुष्ट स्वभाव के हों; ऐसे परिवार मे जाने वाली कन्या भी अत्यधिक भयभीत होकर कष्ट भोगती है अथवा वर उस गौ सम कन्या का पक्ष ले तो वर को भी अत्यधिक पीड़ा सहन करना पड़ता है। (जिन लोगों को ऐसे वर पर दया आये वे अपनी कन्या उस परिवार के पुत्र को दान कर सकते हैं पर परिणाम निश्चित ही कष्टदायक होता है अथवा सुख के साथ दुख की भी प्रबल संभावना होती है) तथा

6. जो मूर्ख हो (अनपढ़ , अशिक्षित और विवेकहीन हो)

इन छःमनुष्यों को कन्या नहीं देनी चाहिये और इसी प्रकार .

1. अतिवृद्ध,
2. अत्यन्त दीन,
3. महा रोगी,
4. अति निकट रहने वाले,
5. अत्यन्त क्रोधी और
6. असन्तुष्ट -

इन छः व्यक्तियों को भी कन्यादान नहीं करना चाहिये। इन्हें कन्या देकर मनुष्य नरक में पड़ता है। ऐसे अयोग्य वर को कन्या देने वाला पिता नाश को प्राप्त होता है न कि सुख समृद्धि को। ऐसी गुणी पुत्री और ऐसे गुणी वर का विवाह जब संपन्न होता है तब देवता भी पुष्प वर्षा करते हैं। और विवाह के समय इनके दर्शन से महा युगल (श्री गौरीशंकर और श्री सीताराम जी) के दर्शन का फल भी प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार दस (10) पुत्रों को जन्म देकर उनकी शिक्षा दीक्षा पालन पोषण और विवाह आदि के लिए जितना खर्च किया जाता है और उससे जिस प्रकार के फल का विधान है उतना ही फल मात्र एक पुत्री को जन्म देकर उसे संस्कारी बनाने मात्र से प्राप्त होता है। धन के लोभ से या सम्मान मिलने की आशा से जो कन्या देता या एक कन्या दिखाकर दूसरी का विवाह कर देता है, वह भी नरक गामी होता है। हे ब्राह्मण ! जो इस परम उत्तम पुण्य मय उपाख्यान का श्रवण करता है, उसके भी जन्म-जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जिसके प्रारब्ध में कन्या न हो वह किसी दरिद्र पुरुष की सुशील पुत्री का कन्यादान कराकर भी संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है तथा वह पुरुष इस फल से भी 100 गुना अधिक फल प्राप्त कर लेता है जो अपनी स्वयं की कन्याओं के विवाह के बाद एक अन्य दरिद्र पुरुष की गुणवती कन्या का दान (कृपणता छोड़कर) प्रसन्न मन से करता है।

नोट - जिस पिता की कन्या विवाह से पूर्व परपुरुष को अपनी योनी दान कर चुकी (अर्थात परपुरुष गामी हो चुकी) ऐसी कन्यादान का कोई भी फल नहीं क्योंकि वह बालिका कन्या की संज्ञा से रहित हो चुकी। जो युवती या कन्या विवाह से पूर्व किसी पुरुष से गमन करती है वह पिता भी नरक का मुख अवश्य देखता है और जिसकी कन्या पतिव्रता हो वह पिता वैकुण्ठ का अधिकार भी पा लेता है। (कन्यादान से समस्त दानों का फल तो सुलभ हो ही गया अब दीर्घकाल तक परमधाम भी प्राप्त कर लेता है सदा के लिए वैकुण्ठ के लिए तो साधन चतुष्ट्य संपन्न होना ही अनिवार्य है)। संस्कारी पुत्री व भक्त पुत्र को जन्म देने की विधि ही ऋतुकाल विधि कहलाती है। अतः ऋतुकाल नियम के अनुसार ही आदर्श कन्या को जन्म देना चाहिए, इस विधि से उत्पन्न करके परम धाम प्राप्त करना चाहिए अन्यथा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ही उत्तम है।

वैदिक काल या वैदिक सभ्यता

वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक काल खंड है. उस दौरान वेदों की रचना हुई थी।

1. ऋग्वैदिक कालीन देवता

इंद्र- युद्ध का नेता और वर्षा का देवता

अग्नि- देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ

वरुण- पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन-रात का कर्ता

द्यौ- आकाश का देवता (सबसे प्राचीन)

उषा- प्रगति एवं उत्थान देवता

आश्विन- विपत्तियों को हरने वाले देवता

2. विष्णु- विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता

3. मरुत- आंधी-तूफान का देवता

4. आर्यों की भाषा संस्कृत थी.

5. आर्यों की प्रशासनिक इकाई इन पांच भागों में बंटी थीः (i) कुल (ii) ग्राम (iii) विश (iv) जन (iv) राष्ट्र.

6. वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी.

7. ग्राम के मुखिया ग्रामीणी और विश का प्रधान विशपति कहलाता था. जन के शासक को राजन कहा जाता था. राज्याधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे.

8. शासन का प्रमुख राजा होता था. राजा वंशानुगत तो होता था लेकिन जनता उसे हटा सकती थी. वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था.

9. राजा युद्ध का नेतृत्वकर्ता था. उसे कर वसूलने का अधिकार नहीं था. जनता अपनी इच्छा से जो देती थी, राजा उसी से खर्च चलाता था.

10. राजा का प्रशासनिक सहयोग पुरोहित और सेनानी 12 रत्निन करते थे. चारागाह के प्रधान को वाजपति और लड़ाकू दलों के प्रधान को ग्रामिणी कहा जाता था.

11. 12 रत्निन इस प्रकार थेः पुरोहित- राजा का प्रमुख परामर्शदाता, सेनानी- सेना का प्रमुख, ग्रामीण- ग्राम का सैनिक पदाधिकारी, महिषी- राजा की पत्नी, सूत- राजा का सारथी, क्षत्रि- प्रतिहार, संग्रहित- कोषाध्यक्ष, भागदुध- कर एकत्र करने वाला अधिकारी, अक्षवाप- लेखाधिकारी, गोविकृत- वन का अधिकारी, पालागल- राजा का मित्र.

12. पुरूप, दुर्गपति और स्पर्श, जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे.

13. वाजपति-गोचर भूमि का अधिकारी होता था.

14. उग्र-अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था.

15. सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी.

16. सभा श्रेष्ठ और संभ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी और विदथ सबसे प्राचीन संस्था थी. ऋग्वेद में सबसे ज्यादा विदथ का 122 बार जिक्र हुआ है.

17. विदथ में स्त्री और पुरूष दोनों सम्मलित होते थे. नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान जैसे सामाजिक कार्य विदथ में होते थे.

18. अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है. समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था. समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था.

19. अलग-अलग क्षेत्रों के अलग-अलग विशेषज्ञ थे. होत्री- ऋग्वेद का पाठ करने वाला, उदगात्री- सामवेद की रिचाओं का गान करने वाला, अध्वर्यु- यजुर्वेद का पाठ करने वाला और रिवींध- संपूर्ण यज्ञों की देख-रेख करने वाला.

20. युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था, युद्ध के गविष्ठ शब्द का इस्तेमाल किया जाता था जिसका अर्थ होता है गायों की खोज.

21. दसराज्ञ युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के सातवें मंडल में है, यह युद्ध रावी नदी के तट पर सुदास और दस जनों के बीच लड़ा गया था. जिसमें सुदास जीते थे.

22. ऋग्वैदिक समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र में विभाजित था. यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था. ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शुद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं.

प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक

23. एक और वर्ग 'पणियों' का था जो धनि थे और व्यापार करते थे.

24. भिखारियों और कृषि दासों का अस्तित्व नहीं था. संपत्ति की इकाई गाय थी जो विनिमय का माध्यम भी थी. सारथी और बढ़ई समुदाय को विशेष सम्मान प्राप्त था.

25. आर्यों का समाज पितृप्रधान था. समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी जिसका मुखिया पिता होता था जिसे कुलप कहते थे.

26. महिलाएं इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं.

27. बाल विवाह और पर्दाप्रथा का प्रचलन इस काल में नहीं था.

28. विधवा अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी. विधवा विवाह, महिलाओं का उपनयन संस्कार, नियोग गन्धर्व और अंतर्जातीय विवाह प्रचलित था.

29. महिलाएं पढ़ाई कर सकती थीं. ऋग्वेद में घोषा, अपाला, विश्वास जैसी विदुषी महिलाओं को वर्णन है.

30. जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था.

31. आर्यों का मुख्य पेय सोमरस था. जो वनस्पति से बनाया जाता था.

32. आर्य तीन तरह के कपड़ों का इस्तेमाल करते थे. (i) वास (ii) अधिवास (iii) उष्णीय (iv) अंदर पहनने वाले कपड़ों को निवि कहा जाता था. संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ आर्यों के मनोरंजन के साधन थे.

33. आर्यों का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन था.

34. गाय को न मारे जाने पशु की श्रेणी में रखा गया था.

35. गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के खिलाफ मृत्युदंड या देश निकाला की सजा थी.

ऋग्वैदिक कालीन नदियां

36. आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे.

37. आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी.

38. व्यापार के दूर-दूर जाने वाले व्यक्ति को पणि कहा जाता था.

39. लेन-देन में वस्तु-विनिमय प्रणाली मौजूद थी.

40. ऋण देकर ब्याज देने वाले को सूदखोर कहा जाता था.

41. सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती थी.

42. उत्तरवैदिक काल में प्रजापति प्रिय देवता बन गए थे.

43. उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होते थे.

44. उत्तरवैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था.

45. उत्तरवैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थीं.

46. सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे पुराना था. इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें पहला तत्व प्रकृति है.

47. सत्यमेव जयते, मुण्डकोपनिषद् से लिया गया है.

48. गायत्री मंत्र सविता नामक देवता को संबोधित है जिसका संबंध ऋग्वेद से है.

49. उत्तर वैदिक काल में कौशांबी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था.

50. महाकाव्य दो हैं- महाभारत और रामायण.

51. महाभारत का पुराना नाम जयसंहिता है यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है.

52. सर्वप्रथम 'जाबालोपनिषद ' में चारों आश्रम ब्रम्हचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का उल्लेख मिलता है.

53. गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ.

54. ऋग्वेद में धातुओं में सबसे पहले तांबे या कांसे का जिक्र किया गया है. वे सोना और चांदी से भी परिचित थे. लेकिन ऋग्वेद में लोहे का जिक्र नहीं है.

दिशा

विश्व लिवर दिवस आज

लिवर (यकृत) हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। यह शरीर के खून को फिल्टर करता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। यहीं नहीं लिवर का काम पाचन से लेकर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने तक का है। हालांकि आज के समय में सबसे अधिक लोग लिवर से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसलिए इसके प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है।

क्यों मनाया जाता है विश्व लिवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लिवर हमारे शरीर का एक खास अंग है। इसका स्वस्थ और मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। यह हमें कई गंभीर बीमारियों से बचाएं रखता है। हालांकि लिवर से संबंधिक कई सारी गंभीर बीमारियां हो रही हैं। जिसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 19 अप्रैल को अलग-अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज के समय में दुनिया भर में लिवर की बीमारियां फैल रही है। इसलिए इकके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है।

विश्व लिवर दिवस का महत्व क्या है? विश्व लिवर दिवस का महत्व बहुत ही खास है। इस दिन को सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, विश्व स्तर पर 4% मौतें लीवर रोगों के कारण होती हैं। इसके अलावा WHO द्वारा जारी 2024 की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार, हेपेटाइटिस से हर साल 1.3 मिलियन मौत होती है।

लिवर संबंधी समस्याओं से कैसे बचें हेल्दी फूड और जीवनशैली से आप लिवर से संबंधित मौतों से बच सकते हैं. आइए जानते हैं।

लिवर कैंसर और अन्य घातक बीमारियों से बचने के लिए शराब का सेवन न करें।

हरी पत्तेदार साग और साबुत अनाज का सेवन करें। क्योंकि इसमें कई पोषक तत्व पे जाते हैं जो हमारे शरीर के टॉक्सिंस क बाहर निकालता है। इसके साथ ही लिवर में फैट को जमा नहीं होने देता है।

लिवर को हेल्दी रखना है तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को नियंत्रण में रखें।

संतुलित जीवन बनाए रखने के लिए विभिन्न गतिविधियों जैसे खेल, योग या कसरत को अपने जीवन में शामिल करें।

लिवर को हेल्दी रखन है तो सेब, गाजर और चुकंदर आदि का सेवन करें. क्योंकि इसमें कई सारे विटामिन्स, कैरोटीनॉयड, -ऑक्सीडेंट, एंथोसायनिन जैसे तत्व पाए जाते हैं. जो लिवर को हेल्दी रखता है।

जानिए आपका कौन सा चक्र बिगडा हुआ है।

1. मूलाधार चक्र - गुदा और लिंग के बीच चार पंखुरियों वाला 'आधार चक्र' है। आधार चक्र का ही एक दूसरा नाम मूलाधार चक्र भी है। इसके बिगड़ने से वीरता, धन, समृधि, आत्मबल, शारीरिक बल, रोजगार, कर्मशीलता, घाटा, असफलता रक्त एवं हड्डी के रोग, कमर व पीठ में दर्द, आत्महत्या के विचार, डिप्रेशन, केंसर आदि होता है।

2. स्वाधिष्ठान चक्र - इसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र लिंग मूल में है उसकी छः पंखुरियाँ हैं, इसके बिगड़ने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, नपुंसकता, बाँझपन, मंद्बुधिता, मूत्राशय और गर्भाशय के रोग अध्यात्मिक सिद्धी में बाधा बैभव के आनंद में कमी अदि होता है।

3. मणिपूर चक्र - नाभि में दस दल वाला मणिचूर चक्र है । इसके इसके बिगड़ने पर तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह, अधूरी सफलता, गुस्सा, चिड़चिड़ापन नशाखोरी, तनाव, शंकलु प्रबिती, कई तरह की बिमारिया, दवावो का काम न करना, अज्ञात भय, चहरे का तेज गायब, धोखाधड़ी, डिप्रेशन, उग्रता, हिंसा, दुश्मनी, अपयश, अपमान, आलोचना, बदले की भावना, एसिडिटी, ब्लडप्रेशर, शुगर, थाईरायेड, सिर एवं शरीर के दर्द, किडनी, लीवर, केलोस्ट्राल, खून का रोग आदि बिगड़ने लगते हैं। इनके बिगड़ने का मतलब जिंदगी का बिगड़ जाना ।

4. अनाहत चक्र - हृदय स्थान में अनाहत चक्र है । यह बारह पंखरियों वाला है । इसके बिगड़ने पर लिप्सा, कपट, तोड़ -फोड़, कुतर्क, चिन्ता, नफरत, प्रेम में असफलता, प्यार में धोखा, अकेलापन, अपमान, मोह, दम्भ, अपनेपन में कमी, मन में उदासी, जीवन में बिरानगी, सब कुछ होते हुए भी बेचनी, छाती में दर्द, साँस लेने में दिक्कत, सुख का अभाव, हृदय व फेफड़े के रोग, केलोस्ट्राल में बढ़ोतरी अदि।

5. विशुद्धख्य चक्र - कण्ठ में विशुद्धख्य चक्र यह सरस्वती का स्थान है। यह सोलह पंखुरियों वाला है। यहाँ सोलह कलाएँ सोलह विभूतियाँ विद्यमान है, इसके बिगड़ने पर वाणी दोष, अभिब्यक्ति में कमी, गले, नाक, कान, दात, थाईरायेड, आत्मजागरण में बाधा आती है।

6. आज्ञाचक्र - भूरमध्य में आज्ञा चक्र है, यहाँ उद्गीय, हूँ, फट, विषद, स्वधा, स्वहा, सप्त स्वर आदि का निवास है। इसके बिगड़ने पर एकाग्रता ,जीने की चाह, निर्णय की शक्ति, मानसिक शक्ति, सफलता की राह आदि बिगड़ जाते हैं। इसके बिगड़ने का मतलब सब कुछ बिगड़ जाने का खतरा ।

7. सहस्रार चक्र - सहस्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है। शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथियों से सम्बन्ध रैटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का अस्तित्व है। वहाँ से जैवीय विद्युत का स्वयंभू प्रवाह उभरता है। इसके बिगड़ने पर मानसिक बीमारी, अध्यात्मिकता का आभाव, भाग्य का साथ न देना अदि ।

महिलाएं चूड़ियाँ क्यों पहनती हैं?

विवाहित स्त्रियों के लिए चूड़ियों का क्या महत्व है? भारत में चूड़ियों पहनने की परंपरा प्राचीन काल से शुरू हुई। आज भी, महिलाएं अपनी स्त्रीत्व की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए चूड़ियाँ पहनती हैं, जो विभिन्न रूपों में उपलब्ध हैं। ₹चूड़ी₹ शब्द हिंदी शब्द ₹बंगरी₹ या ₹बंगली₹ से लिया गया है, जिसका संस्कृत में अर्थ है बाहों को सजाने वाला आभूषण।

विवाहित महिलाओं के लिए चूड़ियों का महत्व भारत में विवाहित महिलाओं के लिए चूड़ियाँ पहनना अनिवार्य माना जाता है और यह भारतीय दुल्हन के आभूषणों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ समुदायों में यह परंपरा है कि विवाहित महिलाएं सिर्फ सोने की चूड़ियाँ अकेले नहीं पहन सकतीं और उन्हें कांच की चूड़ियों, जिन्हें 'कांच की चूड़ियाँ' कहा जाता है, के साथ पहनना चाहिए, क्योंकि यह पति और पुत्रों के कल्याण का प्रतीक है।

महिलाएं चूड़ियाँ क्यों पहनती हैं? भारतीय महिलाएं पारंपरिक और सांस्कृतिक कारणों से चूड़ियाँ पहनती हैं, जिसमें सौंदर्य, शुभता और विवाहित स्थिति का प्रतीकात्मक प्रदर्शन शामिल है।

विभिन्न रंगों के अर्थ

लालः ऊर्जा और जोश का प्रतीक। इसे शक्ति और प्रेम को दर्शाने वाला माना जाता है।

नीलाः शांति और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है। यह रंग मानसिक स्पष्टता और आराम को बढ़ावा देता है।

बैंगनीः स्वतंत्रता और रचनात्मकता का प्रतीक। यह रंग आध्यात्मिक जागृति और स्व-अभिव्यक्ति के लिए उत्साहित करता है।

हराः भाग्य और विवाहित जीवन की समृद्धि को दर्शाता है। यह प्रकृति और नवीनीकरण का भी प्रतीक है।

पीलाः खुशी और ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। यह रंग उत्साह और नवीनता के लिए जाना जाता है।

नारंगीः सफलता और उत्साह का संकेत। यह रंग साहस और संभावनाओं को आकर्षित करता है।

सफेदः नई शुरुआत और शुद्धता का प्रतीक। यह शांति और सच्चाई को भी दर्शाता है।

कालाः शक्ति और रहस्य को प्रतिबिंबित करता है। यह रंग सुरक्षा और गहनता का भी संकेत देता है।

चांदीः ताकत और स्थायित्व का प्रतीक। इसे शांति और चमक को प्रदर्शित करने वाला माना जाता है।

सोनाः सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक। यह धन और वैभव को आकर्षित करने के लिए पहना जाता है।

पश्चिम बंगाल में चूड़ियों की परंपरा जबकि भारत की अधिकांश विवाहित महिलाएं सोने की चूड़ियाँ पहनती हैं, पूर्वी राज्य बंगाल की विवाहित महिलाएं विवाह के प्रतीक के रूप में सफेद रंग की शंख (शक्हा) और लाल मूंगा (पौला) की चूड़ियाँ पहनती हैं।

पंजाब में चूड़ियों की परंपरा

पंजाब राज्य में, दुल्हन विवाह के बाद 21 दिन या एक साल तक, प्रत्येक हाथ पर हाथीदांत की चूड़ियों का सेट, जिसे ₹चूड़ा₹ कहा जाता है, पहनती है, जो परिवार की परंपरा पर निर्भर करता है।

राजस्थान में चूड़ियों की परंपरा

राजस्थानी महिलाएं अपनी बाहों से ऊपरी भुजा तक हाथीदांत की चूड़ियाँ पहनती हैं, जो उनके पति के जीवन काल तक या उनके जीवन भर के लिए सोने के आभूषण के रूप में पहनी जाती हैं। यह परंपरा आज के समय में लुप्त हो चुकी है।

आधुनिक समय में चूड़ियों की परंपरा आधुनिक समय में, महिलाएं अपने वैवाहिक स्थिति के बावजूद विभिन्न प्रकार और शैलियों की चूड़ियों से अपनी बाहों को सजाती हैं, क्योंकि वे मानती हैं कि विवाह के बाद या पहले आभूषण पहनने से उनके पति की उम्र से कोई संबंध नहीं है। इसलिए, आजकल चूड़ियाँ या कंगन फैशन-चेतन लड़कियों द्वारा उतनी ही शैली से पहनी जाती हैं जितना कि उनकी माताओं और दादियों ने परंपरा के रूप में पहनी थीं। चूड़ियाँ केवल शादियों के दौरान ही नहीं, बल्कि बच्चे के जन्म से पहले के समारोह, जिसे भारतीय संदर्भ में ₹चूड़ी संस्कार₹ कहा जाता है, में भी महत्वपूर्ण हैं। यह माना जाता है कि यह एक ऐसा अवसर है जो गर्भवती माँ या गर्भ में पल रहे बच्चे के आसपास घूम रहे बुरे शक्तियों को दूर करने के लिए आयोजित किया जाता है। स्वस्थ और चमकदार गर्भवती माँ, अपनी चमकीली चूड़ियों (कांच, चांदी, शंख, या शेल की चूड़ियाँ, जो क्षेत्र और समुदाय पर निर्भर करता है) से बुरी आत्माओं का ध्यान अपनी ओर करती है, जिससे खतरा उस या बच्चे को नहीं पहुंचता। विवाहित महिला केवल तभी अपनी चूड़ियाँ उतारती है जब वह बच्चे को जन्म देने के लिए प्रसव के दौरान होती है या जब वह विधवा हो जाती है। जबकि पहला आसान प्रसव का प्रतीक है, दूसरे में दुखद अर्थ है। इसलिए, जब कांच की चूड़ियाँ टूटती हैं, तो इसे बदशगुन का प्रतीक माना जाता है।

संस्कारशाला: क्यों ज़रूरी है बच्चों को मंदिर ले जाना और उन्हें भारतीय परंपरा से जोड़ना : डॉ. अंकुर शरण के साथ एक सांस्कृतिक यात्रा

आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में हम अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा, तकनीक और प्रतिस्पर्धा में तो ढाल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें हमारी जड़ों, हमारी संस्कृति और हमारी सनातन परंपराओं से दूर कर रहे हैं। संस्कारशाला के इस विशेष लेख में डॉ. अंकुर शरण हमें समझा रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है बच्चों को मंदिर लेकर जाना, उन्हें उपयुक्त वस्त्र पहनाना और हमारे धार्मिक प्रतीकों की गहराई को समझाना।

मंदिर: आत्मा की पाठशाला

मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि वह स्थान है जहाँ आत्मा को शांति मिलती है और मन को स्थिरता। जब हम बच्चों को मंदिर लेकर जाते हैं, तो हम उन्हें एक अनुशासित, पवित्र और ऊर्जावान वातावरण से परिचित कराते हैं। यहाँ उन्हें मौन, ध्यान और भक्ति का भाव सिखाया जाता है, जो उनके व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाता है।

उचित वस्त्र: परंपरा से जुड़ाव

जब बच्चे मंदिर जाते समय पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं – जैसे कि लड़के धोती या कुर्ता-पायजामा और लड़कियाँ सलवार-कुर्ता या साड़ी जैसे वस्त्र – तो उनमें श्रद्धा और गंभीरता का भाव स्वतः विकसित होता है। यह न केवल सम्मान का प्रतीक है बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति की सुंदरता और गरिमा से भी परिचित कराता है।

शंख और घंटा: ध्वनि की ऊर्जा

शंख बजाना केवल धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं, बल्कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। शंख से निकलने वाली ध्वनि वायुमंडल को शुद्ध करती है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर या मंदिर के वातावरण में सकारात्मकता भर देती है।

घंटा बजाना मन को एकाग्र करने में सहायक होता है। जब हम मंदिर में प्रवेश करते समय घंटा बजाते हैं, तो वह ध्वनि हमारे मस्तिष्क को वर्तमान क्षण में लाने का कार्य करती है, जिससे हम पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर की आराधना कर सकें।

सनातन धर्म की कला को समझना

सनातन धर्म केवल पूजा-पाठ की प्रणाली नहीं, बल्कि एक सम्पूर्ण जीवन पद्धति है। इसमें हर क्रिया का एक गूढ़ अर्थ छिपा है – चाहे वह तुलसी के पौधे की पूजा हो, दीपक जलाना हो, या हाथ जोड़कर नमस्कार करना।

बच्चों को यह समझाना ज़रूरी है कि ये सब केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब वे इस कला को सीखते हैं, तो वे आत्मविश्वासी, संतुलित और संस्कारी नागरिक बनते हैं।

डॉ. अंकुर शरण, जिन्होंने समाज में शिक्षा, पर्यावरण और संस्कृति को लेकर कई अनूठी पहल की हैं, आज बच्चों और युवाओं को यह सिखा रहे हैं कि कैसे हमारी जड़ें हमें भविष्य में मज़बूती देती हैं। ₹संस्कारशाला₹ केवल एक अभियान नहीं, यह एक आंदोलन है – जहाँ हर बच्चा आत्मज्ञान, मर्यादा और धर्म को समझ कर एक बेहतर इंसान बन सकता है।

अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे केवल सफल ही नहीं, बल्कि संवेदनशील, संस्कारी और संतुलित बनें – तो उन्हें मंदिर ले जाएँ, उन्हें परंपरा से जोड़ें और उन्हें यह सिखाएँ कि हमारी सनातन संस्कृति केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि वर्तमान की आवश्यकता है।

संस्कारशाला के साथ जुड़ें, और बच्चों को दें भारतीयता की सबसे सुंदर भेंट।

दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में भारी बारिश; गर्मी से मिली राहत

दिल्ली-NCR में शुक्रवार शाम को मौसम ने अचानक करवट ली। दोपहर में तेज गर्मी के बाद शाम को कई इलाकों में भारी बारिश हुई। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार के लिए हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया था। दिल्ली के मथुरा रोड कनॉट प्लेस और इंडिया गेट के पास भारी बारिश देखी गई।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट लिया और शाम को कई इलाकों में भारी बारिश होने लगी। इससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। इससे पहले, मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार के लिए हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया था। दिल्ली के मथुरा रोड, कनॉट प्लेस और इंडिया गेट के पास भारी बारिश देखी गई।

दिल्ली के कुछ हिस्सों जैसे मध्य, दक्षिण और पश्चिम दिल्ली में शाम को बारिश हुई। मौसम विभाग के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटा) चलने की संभावना है।

इन इलाकों में हुई बारिश

इनमें बुरारी, रोहिणी, बादली, मॉडल टाउन, करावल नगर, आजादपुर, पीतमपुरा, दिल्ली विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस, दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, मुंडका, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग, कश्मीरी गेट, सीलमपुर, शाहदरा, विवेक विहार, राजौरी गार्डन, पटेल नगर, लाल किला, प्रीत विहार, बुद्ध जयंती पार्क, राष्ट्रपति भवन, राजीव चौक और आईटीओ, साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के कुछ हिस्से शामिल हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, शहर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से चार डिग्री अधिक है। आर्द्रता का स्तर 57 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के बीच रहा।

शनिवार को भी बारिश का पूर्वानुमान

आईएमडी के शनिवार के पूर्वानुमान के अनुसार, आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और शाम तक हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। इसके साथ ही तूफान, बिजली और धूल भरी आंधी के साथ 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 38 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। इस बीच, शुक्रवार को शाम 4 बजे वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई, जिसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 219 था।

तमिलनाडु की स्वायत्तता की मांग : संघीय ढांचे की परीक्षा

डॉ ब्रजेश कुमार मिश्र

लोकतन्त्र वर्तमान शासन प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय स्वरूप है। इसकी आत्मा संविधान में निहित है। संविधान किसी भी देश की राजनीति का मार्गदर्शक है। राजनीति के उद्देश्यों का साधन राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दल सत्ता लोलुप होते हैं और इसकी प्राप्ति के लिए निरन्तर उपक्रम करते रहते हैं। इसके निमित्त कई बार ये संविधान के परित: जाकर कार्य करते हैं। यह परम्परा भारत जैसे देश में भी याद-कदा देखने को मिलती है। हाल ही में तमिलनाडु में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे भारतीय राजनीति में भूचाल आ सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री एम.के. स्टालिन द्वारा 15 अप्रैल को अपने राज्य को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। वस्तुत: इस घटना से एक बार पुन: केंद्र और राज्य के मध्य टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यह कहता है कि 'भारत राज्यों का संघ (यूनियन) होगा'। अर्थात भारत नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है, जिसमें राज्य तो विभाज्य हो सकते हैं परन्तु संघ का विभाजन नही हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री का यह निर्णय संवैधानिक है ? क्या कोई इकाई भारतीय संघ से अलग हो सकती है ? इन प्रश्नों की पड़ताल करना संविधान और राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए स्वाभाविक है। इन प्रश्नों का विश्लेषण करने के पूर्व यह जानना जरूरी है कि इस विवाद के पीछे असल वजह क्या है ?

विगत 15 अप्रैल को एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में एक तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है जो यह बताएगी कि कैसे तमिलनाडु को एक स्वायत राज्य बनाया जा सकता है। ऐसा उन्होंने विधानसभा के नियम संख्या 110 के अंतर्गत स्वप्रेरणा से की। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ करेंगे। इसके अन्य सदस्य सेवानिवृत आईएएस अधिकारी के. अशोक वर्धन शेट्टी और राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष एम. नागनाथन होंगे। इन तीनों का सम्बन्ध स्टालिन के राजनीतिक दल से है। यह समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उसके बाद इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। तमिलनाडु में अगले वर्ष चुनाव है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह निर्णय पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। बहरहाल इस समिति का उद्देश्य संविधान, कानूनों और नीतियों में निहित केंद्र-राज्य संबंधों के प्रावधानों की समीक्षा करना, राज्यों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना तथा राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले गए विषयों को पुन: राज्यों को सौंपने हेतु सुझाव देना है। समिति उन प्रशासनिक चुनौतियों पर भी विचार करेगी, जिनका सामना राज्य सरकारें कर रही हैं। इसका अर्थ यह है कि स्टालिन केवल तमिलनाडु तक स्वयं को सीमित नही कर रहे हैं बल्कि वे तमिलनाडु को अन्य राज्यों के मॉडल के रूप में पेश करने की जुगत में हैं। स्टालिन ने अपने पक्ष में कई तरह के तर्क प्रस्तुत किए मसलन वितीय स्वायत्तता, राज्यों के अधिकारों में अनवरत कटौती, परिसीमन, त्रिभाषा और शिक्षा नीति इत्यादि।

हाल ही में ए.आई.डी.एम.के. और भा.ज.पा. के मध्य गठजोड़ (एन.डी.ए) होने के बाद तमिलनाडु में राजनीति गरम हो गई है। डी.एम.के. का उत्तर भारत से सदैव से छतीस का आकड़ा रहा है। अब भा.ज.पा. वहाँ मुख्य विपक्ष के तौर पर है तो तमिलनाडु सरकार को भा.ज.पा. का प्रतिकार करने का स्वर्णिम अवसर मिल गया है। भाषा इसमें बड़ा मुद्दा है। वहाँ की जनता को यह कहकर आसानी से गुमराह किया जा सकता है कि भा.ज.पा. जबरन हम पर हिन्दी थोप रही है, जब अंग्रेज इसे लागू नही कर सके तो ये कैसे करेंगें। वस्तुत: २०२४ के चुनाव के लोकसभा चुनाव में भा.ज.पा. का मतदान प्रतिशत तमिलनाडु बढा है जो लगभग 18 प्रतिशत हो गया है। स्टालिन को हो सकता है कि यह डर सता रहा हो कि अगले चुनाव में एन.डी.ए कहीं उनसे सत्ता न छीन ले। कदाचित यही कारण है कि वे तमिल जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। इसी वजह से डी.एम.के. प्रमुख कभी हिन्दी को लेकर तो कभी भारतीय मुद्रा के चिह्न को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए हैं। परिसीमन को लेकर भी डी.एम.के.मुखर है। नई लोकसभा के उद्घाटन के बाद से ही अनवरत यह मुद्दा उठता रहा है कि नए परिसीमन के बाद दक्षिण की सीटें कम ना हो जाएं क्योंकि परिसीमन का आधार आबादी है और 1971 के बाद दक्षिण ने तो अपनी जनसंख्या को जहां नियंत्रित रखा है वहीं उत्तर भारत की जनसंख्या में इजाफा हुआ है। इस नजरिए से दक्षिण की तुलना में उत्तर को अधिक सीटें मिलेगी। हालांकि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने अपनी सफाई दी है कि फिलहाल परिसीमन कराने का कोई इरादा नही है। भले ही केंद्र ने स्पष्टीकरण दिया हों लेकिन डी.एम.के. द्वारा उठाए जा रहे इस मुद्दे में दम है।

स्टालिन ने वित्तीय आधार पर भी केंद्र का प्रतिकार किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद तमिलनाडु को राजस्व में भारी नुकसान हुआ है। उसे उसके योगदान के बदले केवल २९ पैसे प्रति रुपये मिलते हैं, जो अन्यायपूर्ण है जबकि भारत में तमिलनाडु सकल घरेलू उत्पाद में दूसरे स्थान का राज्य है। उन्होंने डॉ. अंबेडकर का हवाला देते हुए केंद्र और राज्य के बीच समन्वयपूर्ण कार्य की आवश्यकता पर बल दिया। स्टालिन ने मेडिकल प्रवेश हेतु एनईईटी परीक्षा को राज्य की शिक्षा नीति के विरुद्ध बताया है। उनकी यह धारणा है कि यह परीक्षा ग्रामीण तथा आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के हितों के विरुद्ध है और कोचिंग संस्थानों को बढ़ावा देती है। अत: तमिलनाडु के छात्रों को मेडिकल में प्रवेश उनके ही राज्य में १२ वीं के अंक के आधार पर मिले। वे अब यह भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि शिक्षा को पुन: राज्य सूची का विषय बना दिया जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि स्टालिन केंद्र से अन्तिम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और सौभाग्य से यह अवसर उन्हे विगत 8 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडु के राज्यपाल के विरुद्ध दिए गए फैसले से मिल गया है। हो सकता है इससे स्टालिन का मनोबल बढ़ा हो और कदाचित इसी कारण उन्होंने इस विशेष कमेटी का गठन किया है।

इस प्रकार उक्त टकराव के पीछे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जो भी तर्क दिए हैं उनमें से अधिकांश तर्क राजनीति से प्रेरित प्रतीत होते हैं। परिसीमन और राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद २०० के दुरुपयोग को छोड़ दिया जाय तो उनके किसी भी तर्क में दम नही दिखता है। जहां तक राज्यपाल का प्रश्न है तो यह एक ऐसा संवैधानिक पद है जिसको लेकर 1950 के दशक के आखिरी वर्षों से लेकर अब तक केंद्र और राज्य के बीच विवाद बना हुआ है। अब इस मूल विषय पर आते हैं कि क्या स्टालिन तमिलनाडु को भारतीय संघ से अलग कर पाएंगे, जवाब है नही क्योंकि केंद्र के पास रक्षा, संचार और विदेशी संबंध का असीमित अधिकार है और इसके होते हुए तमिलनाडु कुछ नही कर सकता। भविष्य में इस प्रकार की स्थिति ना बने इस हेतु सर्वोच्च न्यायालय को तत्काल न्यायिक -सक्रियता का परिचय देना चाहिए। साथ ही भारत में सहकारी संघवाद की स्थिति को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। इस हेतु केंद्र सरकार को अपने द्वारा नियुक्त राज्यपालों को राज्यों से टकराव से बचने की सलाह देनी चाहिए। वस्तुत: अगर प्रत्येक दल अपने व्यक्तिगत हित को त्याग कर आगे बढ़े तो नि:संदेह लोकतंत्र मजबूत होगा और सहकारी सघवाद को मजबूती मिलेगी। केंद्र के साथ ही राज्यों को मजबूती मिलेगी और आपसी सहयोग बढ़ेगा।

शादी के बंधन में बंधी अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता, जमकर नाचे पूर्व सीएम; जानें कौन है दूल्हा

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता केजरीवाल ने संभत जैन से शादी कर ली है। दोनों आईआईटी दिल्ली के बैचमेट हैं और एक साथ एक स्टार्टअप भी चलाते हैं। शादी समारोह कपूरथला हाउस में आयोजित किया गया जिसमें पूर्व सीएम केजरीवाल ने जमकर डांस किया। संगीत सेरेमनी 17 अप्रैल को शांगरीला होटल में हुई थी जबकि रिसेप्शन 20 अप्रैल को होगा।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता केजरीवाल शुक्रवार को शादी के बंधन में बंध गई। यह कार्यक्रम कपूरथला हाउस में आयोजित किया गया। इससे पहले 17 अप्रैल को संगीत सेरेमनी शांगरीला होटल में हुआ था। वहीं 20 अप्रैल को रिसेप्शन होगा। उनकी शादी संभव जैन से हुई, जो आईआईटी दिल्ली में हर्षिता के बैचमेट रहे हैं। दोनों ने एक स्टार्टअप भी शुरू किया है, जिसके दोनों हिस्सेदार हैं।

पंजाब के सीएम भगवंत मान जमकर थिरके

हर्षिता केजरीवाल 29 साल की हैं और आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की है। उनका छोटा भाई पुलकित केजरीवाल भी जेईई में सफलता हासिल की है। उनकी शादी के कार्यक्रम में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए। उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वह जमकर थिरक रहे हैं। वहीं एक अन्य वायरल वीडियो में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी डांस करते दिख रहे हैं। दोनों पुष्पा फिल्म के गाने पर थिरक रहे हैं।

खूब बरसेगा मानसून, जल-नियोजन जरूरी !

हाल ही में आईएमडी (भारतीय मौसम विभाग) ने यह जानकारी दी है कि इस बार देश में जमकर बारिश होगी। आईएमडी का अनुमान है कि इस बार मानसून में औसत से 105% अधिक बारिश होगी।मौसम विभाग की ओर से ये भविष्यवाणी ऐसे समय में आई है जब देश के कई हिस्से भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं।हालांकि, लद्दाख, पूर्वोत्तर और तमिलनाडु में कम बारिश की संभावना बताई गई है। दरअसल, अल-नीनो और इंडियन ओशियन डाइपोल स्थितियां सामान्य रहने की उम्मीद जताई गई है, जिससे अच्छी बारिश होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो मानसून के दौरान अल नीनो की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि जून-सितम्बर के दौरान 105% बरसात हो सकती है। यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि अल नीनो, भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र के पानी का गर्म होना है। वास्तव में यह एक प्राकृतिक घटना है, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में मौसम का पैटर्न बदल जाता है। यहअल नीनो ही होता है जिसकी वजह से धरती पर गर्म तापमान, सूखा, और तूफ़ान जैसी समस्याएं आती हैं। अल-नीनो के कारण मौसम संबंधी आपदाओं में तीव्रता आ सकती है। वहीं पर यदि हम इंडियन ओशियन डाइपोल स्थितियों यानी कि हिंद महासागर द्विध्रुव(आईओडी) की बात करें तो यह एक जलवायु पैटर्न है, जिसमें हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच समुद्र के तापमान में उतार-चढ़ाव होता है। वास्तव में,इस घटना में, हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से में गर्म पानी और पूर्वी हिस्से में ठंडा पानी होता है। पाठकों को बताता चलूं कि इसे इंडियन नीनो भी कहा जाता है। वास्तव में, भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य से कम मानसूनी बारिश से जुड़ी अल-नीनो की स्थितियां इस बार विकसित होने की संभावना नहीं हैं। पाठकों को बताता चलूं कि देश के विभिन्न हिस्से फिलहाल भीषण गरमी से जूझ रहे हैं, और उत्तर भारत में तो तापमान अभी से ही यानी कि अप्रैल माह में ही 42 से 45 तक पहुंच गया है। इसी बीच, अप्रैल अंत से जून-2025 के दौरान भीषण गरमी पड़ने का अनुमान जताया गया है, जिससे बिजली ग्रिडों पर अच्छा-खासा दबाव पड़ सकता है और पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि भारत विश्व का एक बड़ा कृषि प्रधान देश है और यहां की कृषि को 'मानसून का जुआ' कहा जाता है।गौरतलब है कि भारत में मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरल के दक्षिणी सिरे पर आता है। यह मध्य सितंबर में वापस चला जाता है। बहरहाल, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है, क्योंकि मानसून की अनिश्चितता के कारण यहां की फ़सलें खराब हो जाती हैं। इससे उत्पादन कम हो जाता है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ता है। मानसून जल निकायों को भी काफी हद तक प्रभावित करता है। मानसून से जुड़े खतरों की यदि हम यहां बात करें तो इससे ओलावृष्टि, चक्रवात, सुखांड, लू, अनावृष्टि, अतिवृष्टि और शीतलहर जैसे प्रचंड मौसम के कारण फसल उत्पादन में हर साल काफी क्षति होती है। वास्तव में, हमारे देश में कृषि क्षेत्र के लिए मानसून बहुत महत्त्वपूर्ण है, जो देश की लगभग 42.3% आबादी

की जीविका का आधार है। गौरतलब है कि देश की जीडीपी(सकल घरेलू उत्पाद) में कृषि का योगदान 18.2% होता है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि जीडीपी किसी देश में किसी निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है तथा यह किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार और स्वास्थ्य का एक माप है। बहरहाल, हमारे देश में कुल खेती योग्य क्षेत्र का आधे से ज्यादा यानी कि लगभग 52% हिस्सा वर्षा आधारित प्रणाली पर निर्भर है। यह देशभर में पीने के पानी और बिजली उत्पादन के लिए जलाशयों को भरने के लिए भी महत्वपूर्ण है। बहरहाल, इस बार मानसून किसानों के लिए राहत और उम्मीदें लेकर आ रहा है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि इस वर्ष जून से सितंबर के बीच देश में औसत से तीन फीसदी ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। गौरतलब है कि भारत में औसत बारिश 868.6 मिमी होती है और इस साल यानी कि वर्ष 2025 में करीब 895 मिमी बारिश हो सकती है। आईएमडी के अनुसार 2025 में 105 फीसदी यानी 87 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है।अनुमान लगाया गया है कि इस बार उत्तर भारत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी(उत्तर प्रदेश) में मानसून समय पर पहुंचेगा। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र व मध्य भारत में मराठवाड़ा, विदर्भ में भी अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। गौरतलब है कि साल 2023 में अल-नीनो की वजह से बारिश में कमी देखने को मिली थी, लेकिन इस साल(वर्ष 2025) वैश्विक जलवायु संकेतकों में सुधार देखने को मिल रहा है। यदि इस साल भारत में अच्छी बारिश का यह अनुमान सटीक निकलता है तो कहना ग़लत नहीं होगा कि इससे भारतीय किसानों को खेती में अभूतपूर्व लाभ मिल सकेंगे। मसलन, वे समय पर बुवाई कर सकेंगे तथा इसके साथ ही किसानों की सिंचाई पर निर्भरता भी घटेगी और खेती की लागत में भी कमी आएगी। खरीफ फसलों विशेषकर धान, मक्का, सोयाबीन, कपास आदि की पैदावार बेहतर होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, खेतों में नमी रहने से रबी(गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, अलसी, मसूर, आलू आदि)की भी अच्छी फसल होगी जिससे महंगाई घटने की उम्मीद है। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि बारिश के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। मसलन बारिश के फायदों की अगर बात करें तो बारिश से नदियों, झीलों, और जलभृतों का जलस्तर बढ़ता है और पेड़-पौधों और वनस्पतियों को फायदा पहुंचता है।बारिश से हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के लिए पानी की कमी पूरी होती है। बारिश का नुक़सान यह है कि यदि थोड़े समय में जबरदस्त बारिश हो जाती है, तो इससे बाढ़ जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। हालांकि, यह मानसून खरीफ की फसल के मुनाफिक होता है। अत्यधिक वर्षा के कारण आने वाली विपदाओं से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। महानगरों में निचले स्थानों पर जलभराव की समस्याएं पैदा हो जातीं हैं, क्यों कि नगर नियोजन ठीक नहीं है। अधिक बारिश के कारण बहुत बार कच्चे घर/झोपड़े और जानवर बह जाते हैं। पक्षियों को भी खास परेशानी होती है और खेतों में खड़ी फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचता है।बहरहाल, पाठकों को बताता चलूं कि बीते साल यानी कि वर्ष 2024 में जून-सितम्बर के दौरान रिकॉर्ड औसतन 8% अधिक बारिश हुई थी। यहां पाठकों को बताता चलूं कि एक शोध में पाया गया कि पिछले कुछ समय में मानसून की तीव्रता में अच्छी-खासी दीर्घकालिक वृद्धि हुई है, जो पश्चिमी घाट और आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा की घटनाओं को बढ़ाने में योगदान दे रही है। उदाहरण के लिए, 2018 और 2019 में वायनाड और कोडागु में आए विनाशकारी भूस्खलन व बाढ़ को इसी का परिणाम बताया गया है। अध्ययन बताते हैं कि पिछले 800 वर्षों में पश्चिमी घाट में मानसून की तीव्रता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वास्तव में, इसकी वजह जलवायु परिवर्तन माना जा रहा है।बहरहाल, यहां पाठकों को यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस साल हीटवेव के दिन बढ़ेंगे। यानी 40 फीसदी से ज्यादा तापमान वाले दिनों की संख्या पहले से ज्यादा होगी। ध्यातव्य है कि इस साल अप्रैल के महीने में ही हीटवेव शुरू हो चुकी है। अंत में यही कहूंगा कि मौसम विभाग की भविष्यवाणियों में केवल 4% की त्रुटि होती है, इसलिए अधिक बारिश से सतर्क रहने की भी आवश्यकता महत्ती है। इससे पहले कि देश में अधिक बारिश की परिस्थितियां बनें, हमें यह चाहिए कि हम बरसाती जल का उचित संरक्षण और भंडारण करने की ओर अभी से पर्याप्त ध्यान दें और इसके लिए पूर्व-प्लानिंग करें। हमें यह बात अपने जेहन में रखनी चाहिए कि वर्षा जल संचयन से पानी की आपूर्ति पर पड़ने वाला बोझ कम होता है तथा इससे जहां एक ओर बिजली बिल व मृदा अपरदन में कमी आती है, वहीं जल-संचयन से पीने योग्य पानी, सिंचाई आदि की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

तैयार रखें ये दस्तावेज, बिजली निगम की टीम अब पहुंचेगी आपके घर; दूर होगी यूजर्स की परेशानी

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद के मुरादनगर में विद्युत निगम उपभोक्ताओं के लिए केवाईसी अपडेट अभियान चला रहा है। टीम घर-घर जाकर नाम पता और कनेक्शन क्षमता जैसी जानकारी अपडेट करेगी। ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध है। यह कदम फोन नंबर बदलने से होने वाली परेशानी को दूर करेगा और उपभोक्ताओं को दफ्तर जाने से बचाएगा। उपभोक्ता हेल्पलाइन 1912 पर भी जानकारी अपडेट कर सकते हैं।

मुरादनगर। उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में जानकारी को अपडेट करने के विद्युत निगम की टीम घर घर जाकर केवाईसी कराएगी। इसके लिए मीटर रीडिंग लेने वाले रीडर के साथ के अतिरिक्त कर्मचारी उपभोक्ताओं के घर जाएंगे।

केवाईसी में उपभोक्ताओं के नाम, पता, कनेक्शन की क्षमता, आदि जानकारी को एकत्र करके अपडेट किया जाएगा। विद्युत निगम के अभियान का लाभ क्षेत्र के हजारों उपभोक्ताओं को होगा। केवाईसी सम्बन्धी जानकारी को अपडेट करने के लिए उपभोक्ताओं को ऑनलाइन का विकल्प भी दिया है।

विद्युत निगम घर जाकर उपभोक्ताओं की केवाईसी कराएगा

फोन नंबर बदले जाने और दूसरे कारणों के चलते उपभोक्ताओं ने अपने नंबरों को अपडेट नहीं कराया गया। इस परेशानी को देखते हुए विद्युत निगम घर जाकर उपभोक्ताओं की केवाईसी कराएगा। अभियान के विद्युत निगम की टीम उपभोक्ताओं के नाम, पता, फोन, कनेक्शन की क्षमता, वर्तमान लोड व दूसरी जानकारियां जमा करगी।

अधिकारियों की टीम की जिम्मेदारी तय की गई

इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र के मीटर रीडर के साथ के उपकेंद्र के अधिकारियों की टीम की जिम्मेदारी तय की गई है।टीम बिल देने के साथ ही उपभोक्ताओं को केवाईसी भी कर रही है। अभियान के तहत मीटर एसडीओ लेकर मीटर रीडर को अलग अलग स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। उपभोक्ताओं से मिली जानकारी को बहुत जल्द विद्युत निगम के मैन सर्वर में अपडेट किया जाएगा।

उपभोक्ताओं को परेशानी से बचाने के लिए उठाया गया कदम

अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं को निगम के दफ्तर आने की परेशानी से बचाने के लिए निगम ने अभियान चलाया जाएगा। रावली रोड उपकेंद्र के एसडीओ एससी यादव का कहना है कि केवाईसी के संबंध में अगले माह से कार्रवाई की जाएगी। केवाईसी के लिए आनलाइन की सुविधा भी दी गई है।

उपभोक्ता आनलाइन खुद भी कर सकते हैं केवाईसी

इंटरनेट की जानकारी रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए विद्युत निगम ने खुद से आनलाइन केवाईसी करने के की सुविधा भी दी है। जिसके माध्यम से उपभोक्ता कुछ ही देर में अपने फोन नंबर आदि को अपलोड कर सकता है। इसके अलावा वे उपभोक्ता जिनको इंटरनेट की जानकारी नहीं है वे हेल्पलाइन 1912 पर फोन करके अपना नंबर आदि अपलोड कर सकते हैं।

आपीसी धारा 289: लापरवाही से जानवर पालना पड़ सकता है भारी, कानून क्या कहता है?- डॉ. अंकुर शरण

परिवहन विशेष न्यूज

किसी भी सोसायटी या समुदाय में रहना सिर्फ सुविधा नहीं, जिम्मेदारी भी है। एक अच्छा पड़ोसी वही है जो आसपास की सुरक्षा, स्वच्छता और शांत वातावरण के प्रति सजग रहता है। अपने पालतू जानवरों, वाहनों या व्यवहार से किसी को असुविधा पहुँचाना न केवल सामाजिक अपराध है, बल्कि कानूनी कार्यवाही और भारी जुर्माने का कारण भी बन सकता है। आपकी लापरवाही या ₹मुझे क्या₹ वाला रवैया, पूरे समाज के लिए खतरा बन सकता है। अच्छे पड़ोसी बनें, जागरूक नागरिक बनें। अगर आप पालतू कुत्ता या अन्य जानवर पालते हैं और उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर बिना नियंत्रण के छोड़ते हैं, तो यह महज लापरवाही नहीं, बल्कि अपराध हो सकता है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 289 के तहत ऐसे मामलों में कड़ा प्रावधान है।

क्या कहती है IPC की धारा 289?

इस धारा के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो किसी जानवर का मालिक है या उसका नियंत्रणकर्ता है, यदि वह आवश्यक सावधानी या सुरक्षा उपाय नहीं करता और उस कारण से वह जानवर किसी व्यक्ति को घायल कर देता है या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालता है, तो उस व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

क्यों जरूरी है यह प्रावधान?

आजकल शहरी क्षेत्रों में पालतू कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कई बार लोग अपने कुत्तों को बिना पट्टे के टहलाते हैं या खुला छोड़ देते हैं, जिससे राहगीरों को खतरा हो सकता है। इसी के चलते यह कानून बनाया गया है ताकि लोग जिम्मेदारी के साथ जानवर पालें।

हाल के मामले और चेतावनी

हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए जहां पालतू कुत्तों द्वारा लोगों पर हमला करने की खबरें आईं। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर IPC धारा 289 के तहत केस दर्ज किए हैं और पशु मालिकों को चेतावनी दी गई है कि यदि वे आगे से सावधानी नहीं बरतते तो उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है।

क्या करें पालतू जानवर पालने वाले?

हमेशा पालतू जानवरों को सार्वजनिक स्थलों पर पट्टे के साथ रखें

ट्रेन्ड या प्रशिक्षित जानवर ही सार्वजनिक जगहों पर ले जाएं

गार्डन, स्कूल और अस्पताल जैसी जगहों पर विशेष सतर्कता बरतें

किसी पर हमला होने की स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सा और पुलिस को सूचित करें

पशु प्रेम जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है सार्वजनिक सुरक्षा और जिम्मेदारी। IPC की धारा 289 हमें यह सिखाती है कि अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। वरना एक छोटी सी लापरवाही कानूनी परेशानी में डाल सकती है।

राकेश टिकैत और बागपत के BJP विधायक समेत 24 नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, चलेगा मुकदमा; क्या है मामला?

भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत और बागपत के भाजपा विधायक योगेश धामा समेत 24 नेताओं पर मुकदमा चलेगा। मुरादनगर में गंगनहर स्थित रेगुलेटर से दिल्ली का पानी वर्ष 2014 में रोकने के मामले में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।

गाजियाबाद। बागपत विधायक योगेश धामा, भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत और तीन पूर्व विधायकों समेत 25 लोगों पर विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं।

कोर्ट ने साफ किया है कि अब इस मामले में बकायदा मुकदमा चलेगा। मामला मुरादनगर में गंगनहर स्थित रेगुलेटर से दिल्ली का पानी वर्ष 2014 में रोकने से जुड़ा है।

तत्कालीन रालोद प्रमुख अजित सिंह के दिल्ली आवास को खाली कराने के विरोध में नेताओं ने हंगामा किया था। मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।

मुरादनगर में की थी दिल्ली का पानी सप्लाई रोकने की कोशिश

मुरादनगर में 18 सितंबर 2014 को प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली की जल आपूर्ति रोकने की कोशिश की थी। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया था।

घटना के बाद पुलिस ने 36 नामजद और लगभग पांच हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला, आगजनी, बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, बंधक बनाने और संपत्ति नुकसान जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

विवेचना के बाद 36 नेताओं के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इनमें राकेश टिकैत, बागपत से भाजपा विधायक योगेश धामा, पूर्व मंत्री दलवीर सिंह, पूर्व विधायक सुदेश शर्मा, वीरपाल राठी और भगवती प्रसाद, अमरजीत सिंह, अजय प्रमुख समेत 25 आरोपित हैं।

30 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

शुक्रवार को सभी आरोपित कोर्ट पहुंचे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजयवीर सिंह ने दलील दी कि नेताओं पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और पुलिस कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी है।

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश निशांत मान ने सभी आरोपितों पर आरोप तय करते हुए कहा कि मामले में ट्रायल चलेगा और मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।

गर्मी बढ़ते ही फरीदाबाद पुलिस अलर्ट, डेथ वैली समेत इन झीलों में नहाने को लेकर जारी की एडवाइजरी

परिवहन विशेष न्यूज

फरीदाबाद। अरावली पहाड़ी के अंदर झील में न नहाने को लेकर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, देखने में आ रहा है कि सूरजकुंड पहाड़ी क्षेत्र में बनी सिरोही झील, बड़खल झील व डेथ वैली झील में नहाने के दौरान पानी में डूबने से कई युवाओं की मौत हो चुकी है।

जुटती है दिल्ली और गुरुग्राम के लोगों की भी भीड़

पुलिस उपायुक्त एनआईटी कुलदीप सिंह द्वारा इन झील में नहाने वाले लोगों को सावधान किया है। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम मे झीलों का पानी साफ व ठंडा होने की वजह से स्थानीय लोगों के साथ ही दिल्ली और गुरुग्राम के युवा पानी में नहाने उतर जाते हैं।

झील की सतह चिकनी होने के कारण नहाने वाले झील के गहरे पानी में चला जाता है और डूब जाता है। झीलों में पानी में डूबने से मृत्यु होने के कई हादसे हो चुके हैं।

झीलों के पानी में देखे गए हैं मगरमच्छ

इन स्थानों पर स्थानीय पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, लेकिन लोग दाएं-बाएं से निकलकर पानी में नहाने उतर जाते हैं। स्थानीय लोगों से पता चला है कि इन झीलों में मगरमच्छ भी देखे गए हैं।

इन कामों को करने से बचें

पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अनुसार स्टंट या बार-बार कूदना जानलेवा है। मस्ती के चक्कर में किसी की जान भी जा सकती है।

बच्चों और किशोर पर विशेष ध्यान दें। वे अक्सर साथियों के उकसाने पर खतरनाक कदम उठा सकते हैं। उन्हें समझाएं और रोकें।

सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और पुलिस पेट्रोलिंग झीलों के आस-पास की जा रही है। यदि कोई व्यक्ति चेतावनी के बावजूद जल स्रोतों में उतरता है, तो वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

डूबते हुए व्यक्ति को देखें तो तुरंत सहायता के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 या स्थानीय थाना प्रबंधक पर काल करें।

रेलवे नहीं, सी एस ए ग्राउंड में होगी पीएम मोदी की सभा : अंतिम चरण में तैयारियां

सुनील बाजपेई कानपुर

अपने प्रस्तावित दौरे के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां अपनी सभा रेलवे ग्राउंड निराला नगर के बजाय अब सीएसए ग्राउंड में करेंगे ,जिसके लिए सारी तैयारियों को अंतिम रूप देना भी शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा यहां 24 अप्रैल को प्रस्तावित है ,जिसको लेकर युद्धस्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 20 को मुख्यमंत्री कानपुर दौरे पर आ सकते हैं।कुल मिलाकर कानपुर में पीएम की जनसभा स्थल अब चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार के निरीक्षण के बाद सीएसए ग्राउंड में फाइनल कर दिया गया है।रेलवे ग्राउंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया सभा सी एस ए ग्राउंड में कराने के पीछे सबसे बड़ी वजह पीएम की सिक्योरिटी, दूसरी बड़ी वजह रेलवे ग्राउंड में भीड़ जुटाना थी।अभी बताया गया कि तीसरी कि अगर रेलवे ग्राउंड में जनसभा होती तो बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन करना पड़ता। इसके साथ ही तमाम सारी मशक्कत से अफसरों को राहत मिल गई है।अवगत कराते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कानपुर दौरे के दौरान 19 हजार करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वह अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार कानपुर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी जिले की तीन बड़ी योजनाओं अंडरग्राउंड मेट्रो (सेंट्रल स्टेशन से चुन्नीगंज स्टेशन), नेयवेली पावर प्लांट और पनकी पावर हाउस का शुभारंभ करने के साथ लगभग 19,000 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे।

धरती को बेपानी करती 'साठा धान' की फसल पर हो कठोर कार्रवाई?

साठ दिनों में तैयार होने वाली 'साठा धान' की फसल पर कई राज्यों में प्रतिबंध लगने के बाद भी देश के हिस्सों में चोरी-छिपे फसलें लगाई जा रही हैं। ये फसल जमीन के पानी को बेहिसाब सोखती है। फसल के पीछे लोगों का लालच मात्र इतना है, ये फसल दूसरी फसलों के मुकाबले आधे समय में तैयार हो जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार व पंजाब की सरकार ने पहले ही रोक लगाई हुई है, अब उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित हो गई है। प्रतिबंध के बावजूद भी तराई इलाकों में किसान चोरीछुपे साठा धान लगाते हैं। उन्हें रोकने के लिए सरकार ने बकायदा एक 'टृस्क फोर्स' का गठन भी किया है, जो बकायदा संवेदनशील इलाकों में नजर बनाए हुए हैं। फसल लगाने पर हर्जाने का भी प्रावधान हैं। साठा धान को 'चैनी धान' भी कहते हैं। फसल को प्रतिबंधित करने के पीछे की मंशा गिरते भूजल स्तर को रोकना है।

साठा धान भूजल को कितना नुकसान पहुंचाता है, जिसको लेकर विगत वर्षों में कुछ राज्य की सरकारों ने केंद्र सरकार के जरिए केंद्रीय वैज्ञानिकों से रायशुमारी की। उसके बाद वैज्ञानिकों की टीमों ने साठा धान का सैंपल लेकर जांच-पड़तालें की, जिसमें पाया कि वास्तव में ये फसल जमीन के पानी के लिए बहुत नुकसानदायक है। नेपाल सीमा से जितना क्षेत्र सटा है, उसे तराई कहते हैं, वहां ये फसल अभी भी बड़े स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत की जाती हैं। ऐसी हरकतों को सरकार ने स्वंय पकड़ा है। जाहिर है प्रतिबंध में बिना प्रशासनिक सहयोग के किसान साठा धान नहीं उगा सकते। दरअसल, ये फसल मात्र 60 दिनों में तैयार हो जाती है, तभी इसे 'साठा' हैं। जबकि, सामान्य धान की फसल 5 माह से अधिक में तैयार होती हैं। साठा धान की जब वैज्ञानिकों ने कृषि प्रयोगशालाओं में जांच कराई, तो पता चला कि फसल जमीन की नमीं को कितना सोखती हैं। यूं कहें कि ये फसल धरती की कोख को सुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। रिपोर्ट के बाद ही राज्य सरकारों ने आनन-फानन में प्रतिबंध का निर्णय लिया।

एक वक्त था जब पंजाब में चैनी की फसल बड़े स्तर पर की जाती थी, अब रोक है। लेकिन, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में साठा धान की फसल अभी उगती है। तराई क्षेत्र नमी युक्त फसलों के लिए उपजाऊ भूमि मानी जाती है। भूमिगत जलस्तर अच्छा होने से धान के पैदावार वहां अच्छी होती है। ऐसा भी नहीं है कि किसान दुष्प्रमाणों से अंजान और बेखबर हां? अच्छे से जानते हैं कि धरती की कोख को सूखाने में साठा धान कितनी महती भूमिका निभा रहा है, लेकिन मुनाफे की लालच में किसान धरा के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं। तराई क्षेत्र इस समय साठा धान के लिए कुख्यात है। सख्ती के बाद भी वहां रोक नहीं लग पा रही। फसल अधिकांश इन्हीं गर्मी के दिनों में अप्रैल मई-जून माह में उगाई जाती है। इस फसल ने कई जगहों को बंजर बना डाला है।

प्राकृतिक वातावरण व पर्यावरण रक्षा को ध्यान में रखकर उठाए गए सरकार के निर्णय को पर्यावरणविद् सराहा रहे हैं। क्योंकि वह खुद कई वर्षों से रोक की मांग बुलंद किए हुए थे। तराई क्षेत्र को चावल का कटोरा कहते हैं। लेकिन फसल की चाह में लोग मानवीय हिमाकते कर प्रकृति के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। केंद्र सरकार का जल संरक्षण दिशा में तमाम प्रयासों पर भी ये फसल कालिख पोतती है। जल संचय मानव जीवन का आधार है, जब पानी ही नहीं होगा, मानव जीवन कैसे संभव होगा? साठ दिनी इस फसल को किसान जमीन के गर्भ में मौजूद जल को पंपसेट जैसे तकनीकों से निकालकर धान लगाते हैं, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है। फसल उगाने में लोग दिलचस्पी इसलिए दिखाते हैं कि परंपरागत फसलों के मुकाबले इसमें आमदनी दोगुनी होती है। लेकिन लालच में वह जल का कितना दोहन कर रहे हैं, जिसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं? अमूमन अप्रैल से जून तक जमीन खाली होती हैं। किसान सोचते हैं क्यों न साठा धान ही लगा दिया जाए। फसल 60 दिन तैयार होगी और बाजार भाव भी अच्छा मिलेगा।

कनाड़ा में साठा धान कभी उगाया जाता था। लेकिन अब वहां प्रतिबंधित है। नेपाल से सटे तराई क्षेत्र का भूजल स्तर पूरे देश से ज्यादा है। मात्र पंद्रह फीट नीचे पानी निकल आता है। उस पानी का दोहन भी युद्धस्तर पर जारी है। धरती की नमी का फायदा फसल माफिया उठा रहे है। तराई का क्षेत्रफल हजारों हेक्टर में फैला है, कुछ हिस्सा उत्तराखंड में है, वहां भी साठा धान लगता है। जबकि, उत्तराखंड भी गर्मियों में पानी के लिए तरसने लगा है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक तराई का पानी पहले के मुकाबले काफी सूख चुका है। चैनी धान की फसल के चलते वहां कि मिट्टी और पानी का संतुलन बिगड़ा है। अंजाने में ही सही मगर भूजल का दोहन करके देश को मुसिबत में डालने की समस्या को तुरंत रोका जाना चाहिए। साठा धान लगाने से जो नुकसान जमीन को पहुंच रहा है शायद उसका आंकलन कृषि वैज्ञानिक ही ठीक से समझ पाते हों?

अत्यधिक कीटनाशक व उर्वरक के प्रयोग से जहां जमीन बंजर हो रही है। वहीं, धरती की कोख भी सूख रही है। जल संचयन के स्रोत कुएं, तालाब, नदियां, बांध आदि विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। बारिश के दौरान भूजल की पूर्ति करने वाले थे अनगिनत बोरबिल अब सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। बस ध्यान इतना सा रहे है अगर समय रहते भूजल का संरक्षण नहीं किया गया तो निश्चित रूप से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इन्हीं दिनों में साठा धान लगाया जाता है। इस बार भी किसानों ने तैयारी की हुई है। लेकिन प्रतिबंध के फरमान के बाद उनके अरमानों पर पानी फिरा हुआ है। पर्यावरण रक्षा के लिए जनमानस को भी आगे आना चाहिए।

डॉ. रमेश ठाकुर

संगठित करके ओडिशा में सरकार बनाने का प्रयास करेगी : अखिलेश यादव

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वरः उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ओडिशा के दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने भुवनेश्वर में समाजवादी पार्टी के राज्य कार्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ओडिशा में पिछड़ा वर्ग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार ने पीडीएस (पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक) के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रम लागू किए हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चार बार सरकार बनाई है। इस बीच, ओडिशा में डबल इंजन की सरकार में डबल भ्रष्टाचार, डबल केलेनकारी और डबल बाजार मूल्य है, जिससे जनता त्रस्त है। इसलिए आने वाले दिनों में ओडिशा में समाजवादी पार्टी तृणमूल स्तर पर जाकर पिछड़े वर्गों, आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए संघर्ष जारी रखेगी और पिछड़े वर्गों को संगठित करके ओडिशा में सरकार बनाने का प्रयास करेगी। अन्य दलों के नेता जो समाजवादी विचारों से प्रेरित हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, उनका स्वागत किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ओडिशा में जाति जनगणना और सामाजिक न्याय के लिए अपना राज्यव्यापी संघर्ष जारी रखेगी। इस अवसर पर श्री यादव ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से आये पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक की परिचालन प्रदेश अध्यक्ष शिव हाथी यादव ने की। इस समारोह में खोर्दा जिला अध्यक्ष शुभकांत खाडीरत्न, अध्यक्ष पृथ्वी मोहन साहू, भुवनेश्वर तीन निर्वाचन क्षेत्रों के अध्यक्ष प्रवीण नायक, जाजपुर निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष दीपक कुमार साहू, रनपुर निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष हुकलास बारिक, भुवनेश्वर निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष डॉ. अक्षय कुमार बारिक, नुआपड़ा जिला अध्यक्ष बेनुधर गहिर, कलाहांडी जिला अध्यक्ष जगदीश यादव, वरिष्ठ समाजवादी नेता मोहम्मद अख्तर, किसान नेता विजय बेहरा, सज्जित दास, राज्य प्रभारी दीपक मिश्र और राज्य सचिव प्रताप बारिक प्रमुख ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मानित किया। इस अवसर पर अखिलेश यादव की कार्यशैली से प्रभावित होकर पूर्व बीजद कॉरपोरेटर पुष्पांजलि दास समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं।

वोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई चार बेहतरीन कलर के साथ होगी लॉन्च, मिलेगें कई प्रीमियम और एडवांस फीचर्स

परिवहन विशेष न्यूज

वोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई भारत में अलगे महीने मई 2025 में लॉन्च होने जा रही है। कंपनी इसे चार कलर ऑप्शन में लॉन्च करने वाली है। इसे पूरी तरह से निर्मित इकाई (CBU) के रूप में भारत में बेचा जाएगा। इसे इसे सीमित संख्या में लाया जाएगा और इसे केवल ऑनलाइन माध्यम के जरिए ही भारत में बेचा जाएगा। आइए इसके बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में Volkswagen Golf GTI मई 2025 में लॉन्च होने जा रही है। कंपनी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। इसे सीमित संख्या में लाया जाएगा और इसे केवल ऑनलाइन माध्यम के जरिए ही भारत में बेचा जाएगा। Volkswagen की यह हॉट हैचबैक को पूरी तरह से निर्मित इकाई (CBU) के रूप में भारत में बेची जाएगी। कंपनी ने अब इसके कलर ऑप्शन के बारे में खुलासा किया है। आइए जानते हैं कि Volkswagen Golf GTI को किन कलर ऑप्शन के साथ आने वाली है।

कलर ऑप्शन

Volkswagen Golf GTI को कुल चार कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा, जो किंग्स रेड प्रीमियम मेटैलिक ब्लैक, ग्रेनेडिला ब्लैक मेटालिक, ओरिक्स व्हाइट प्रीमियम मदर-ऑफ-पर्ल ब्लैक और मूनस्टोन ग्रे ब्लैक है।

कीमत

भारतीय बाजार में Volkswagen Golf GTI को 50 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। वैसे तो भारत में इसका सीधा मुकाबला बहुत कम है। इसका मुख्य प्रतिद्वंद्वी मिनी कूपर एस है।

इंजन

Volkswagen Golf GTI में 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड गैसोलीन इंजन दिया गया है, जो सात-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसका इंजन 245 bhp की पावर और 370 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह महज 5.9 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा है।

इंटीरियर और फीचर्स

Volkswagen Golf GTI में ऑल-ब्लैक इंटीरियर देखने के लिए मिल सकता है। इसमें स्पोर्ट बकेट सीटें, तीन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा, जो इसकी स्पोर्टी लुक को और भी बेहतर बनाएगी।

इसमें 12.9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो स्मार्टफोन इंट्रीग्रेशन कंट्रोल और वायरलेस फोन चार्जिंग ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा।

एक्सटीरियर

Volkswagen Golf GTI को स्पोर्टी और बोल्ड लुक दिया गया है। इसमें मैट्रिक्स-एलईडी हेडलाइट्स दी गई है, जो इसके स्पोर्टी लुक को और बढ़ा देता है। इसके सामने के बम्पर को काफी अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ पेश किया जाएगा।

इसके पीछे की तरफ स्पोर्टी डिफ्यूज़र और दोहरे एग्जॉस्ट दिए गए हैं, जो इसके लुक को और भी बढ़ा देते हैं। इसमें 18-इंच के डायमंड-कट एलॉय व्हील मिलेंगे।

2025 कावासाकी एलिमिनेटर भारत में हुई लॉन्च, पहले से ज्यादा हुई महंगी

परिवहन विशेष न्यूज

कावासाकी ने भारतीय बाजार में 2025 Kawasaki Eliminator को लॉन्च कर दिया है। इसमें लो-स्लंग और क्रूजर डिजाइन मिलता है। इसे पहले की तरह ही एक कलर ऑप्शन टालिक फ्लेट स्पार्क ब्लैक में पेश किया गया है। इसमें पहले की तरह ही 451cc लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। नई Eliminator की पहले से 14000 रुपये ज्यादा महंगी हो गई है।

नई दिल्ली। सुपर बाइक बनाने के लिए पॉपुलर जापानी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी कावासाकी ने भारत में अपनी 2025 Kawasaki Eliminator क्रूजर बाइक को लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत में 14,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5,76,000 रुपये हो गई है। इसकी पहले एक्स-शोरूम कीमत 5.62 लाख रुपये थी। आइए जानते हैं कि 2025 Kawasaki Eliminator किन बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है?

डिजाइन

2025 Kawasaki Eliminator अपने पहले के मॉडल की तरह ही इसके लो-स्लंग, क्रूजर डिजाइन को बरकरार रखा गया है, इसमें किसी तरह का अपडेट नहीं किया गया है। इसे पहले की तरह ही केवल एक ही कलर ऑप्शन मेटालिक फ्लैट स्पार्क ब्लैक में ऑफर किया जा रहा है। इसका पूरा डिजाइन काफी सिंपल और अट्रैक्टिव है। इसकी साइड प्रोफाइल पहली की तरह ही काफी बेहतरीन दिखने में लगती है।

इंजन

2025 Kawasaki Eliminator में पहले की तरह ही 451cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 45PS की पावर और 42.6Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच के साथ छह-स्पीड गियरबॉक्स का साथ जोड़ा गया है।

अंडरपिनिंग

2025 Kawasaki Eliminator में 120 मिमी व्हील ट्रैवल के साथ एक टेलीस्कोपिक फोर्क और 90 मिमी ट्रैवल के साथ दोहरे रियर शॉक के जरिए सस्पेंड किया गया है। इसकी सीट की ऊंचाई 735 मिमी, ग्राउंड क्लीयरेंस 150 मिमी और कर्ब का वजन 176 किलोग्राम है। इसमें 18 इंच के पहिये दिए गए हैं, जो आगे की तरफ 130-सेक्शन का टायर और पीछे की तरफ 16-इंच है। इसमें 310 मिमी का फ्रंट और 240 मिमी का रियर डिस्क दिया गया है। इसके दोनों तरफ डुअल-पिस्टन कैलिपर्स और डुअल-चैनल ABS भी दिया गया है।

फीचर्स

2025 Kawasaki Eliminator में गोल और डिजिटल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जिसमें ओडोमीटर, टैकोमीटर, गियर पोजिशन इंडिकेटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर और एक घड़ी जैसी जानकारी मिलती है। इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी दी गई है, जो 'राइडोलॉजी' मोबाइल ऐप जरिए कनेक्ट होता है। इसमें नेविगेशन नहीं मिलता है। इसमें कोई राइडिंग मोड या ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर भी नहीं मिलता है। इसमें आपको एनालॉग राइडिंग अनुभव मिलता है और इसकी सीट की ऊंचाई कम है और आरामदायक राइडिंग पोजिशन मिलती है।

टीवीएस ने लॉन्च की नई 2025 अपाचे RR 310, जानें क्या है खास

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। टीवीएस के लिए ₹अपाचे ब्रांड बहुत अहमियत रखता है। पिछले करीब दो दशकों में अपाचे नाम ने टीवीएस की पहचान बना दी है, चाहे बात स्पोर्टी कम्यूटर बाइक्स की हो या फिर स्पोर्ट्स बाइक्स की। इस पूरे लाइनअप के सबसे ऊपर बैठती है Apache RR 310 (टीवीएस अपाचे RR 310)।

बुकिंग

अब टीवीएस ने अपने इस फ्लैगशिप मॉडल को फिर से अपडेट किया है। दिलचस्प बात ये है कि पिछले साल सितंबर में भी इस स्पोर्ट्स टूरर को बड़े लेवल पर अपग्रेड किया गया था। इस बार के अपडेट में कुछ और शानदार फीचर्स जोड़े गए हैं जो इसे ट्रैक पर और भी दमदार मशीन बना देंगे। नई 2025 टीवीएस अपाचे RR310 की बुकिंग अब शुरू हो गई है।

लुक और डिजाइन

नया 2025 मॉडल टीवीएस की एशिया रोड रेसिंग चैंपियनशिप (ARRC) में हासिल की गई शानदार जीत से प्रेरित है। वहां टीवीएस की रेस-स्पेक बाइक ने 1:49.742 सेकंड का जबरदस्त लैप टाइम दर्ज किया था और 215.9 किमी प्रति घंटा की टॉप स्पीड हासिल की थी। इसी जीत से जोश लेकर अब नए मॉडल को डिजाइन और फीचर्स के मामले में और भी रेस-फोकस्ड बनाया गया है।

2025 TVS Apache RR 310: क्या-क्या नया मिला है?

टीवीएस ने इस बार अपने सेगमेंट में पहली बार कुछ यूनिक फीचर्स जोड़े हैं। अब सीक्वेंशियल टर्न सिग्नल लैम्प्स (TSL) और ड्रैग टॉर्क कंट्रोल जैसे फीचर्स भी इसमें मिलेंगे। इसके अलावा, लॉन्च कंट्रोल, नई जनरेशन-2 रेस कंप्यूटर और नई 8-स्पोक एलॉय व्हील्स भी जोड़े गए हैं।

बाइक को नए कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। जो सेपांग ब्लू रेस रेप्लिका स्कीम, जो टीवीएस एशिया OMC रेस बाइक से इंस्पायर्ड है। अब यह बाइक रेड और बॉम्बर ग्रे जैसे पुराने कलर ऑप्शन के साथ मिलकर तीन स्टैंडर्ड वेरिएंट्स और दो बिल्ट टू ऑर्डर (बीटीओ) कस्टमाइजेशन ऑप्शन में उपलब्ध होगी।

2025 TVS Apache RR 310: इंजन पावर और परफॉर्मेंस

नई अपाचे RR 310 में वही भरोसेमंद 312cc का रिवर्स-इंक्लाइन्ड DOHC सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 9,800 RPM पर 37 बीएचपी और 7,900 RPM पर 29 एनएम टॉर्क पैदा करता है। साथ में 6-स्पीड गियरबॉक्स भी मिलेगा।

राइड मोड्स

खास बात ये है कि अब यह इंजन OBD2B नॉर्म्स के अनुरूप बनाया गया है, जो इसे ज्यादा एडवांस और ईको-फ्रेंडली बनाता है। राइडिंग का मजा बढ़ाने के लिए इसमें चार राइड मोड्स मिलते हैं - ट्रैक, स्पोर्ट, अर्बन और रेन।

ऐसे चेक करें ऑनलाइन ट्रैफिक चालान, ये हैं दो सबसे आसान तरीके

परिवहन विशेष न्यूज

ऑनलाइन ट्रैफिक चालान बाइक स्कूटर या कार कोई भी व्हीकल ड्राइव करने के दौरान कहीं कोई चालान तो नहीं कट गया? कई बार यह सवाल जेहन में रहता है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको ट्रैफिक चालान को ऑनलाइन तरीके से चेक करने के बारे में बता रहे हैं। साथ ही बता रहे हैं कि आप ऑनलाइन ट्रैफिक चालान की पेमेंट कैसे कर सकते हैं?

नई दिल्ली। मोटरसाइकिल या कार ड्राइविंग के दौरान बहुत से लोग गलती से या फिर अनजाने में Traffic Rules का उल्लंघन कर बैठते हैं। उनकी इस गलती की वजह से उनका ट्रैफिक चालान कट जाता है। वहीं, कई बार ट्रैफिक पुलिस या CCTV कैमरे से गलती से भी चालान कट जाता है। ट्रैफिक चालान कटने का मैसेज रजिस्टर मोबाइल नंबर जाता है। इस मैसेज को कई लोग देख नहीं पाते हैं या उनसे मिस हो जाता है। जिसकी वजह से बहुत से लोग अनजान रहते हैं कि उनका ट्रैफिक चालान कटा है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको घर पर ही ऑनलाइन ट्रैफिक चालान को चेक करने के आसान तरीके के बारे में बता रहे हैं।

1. ट्रैफिक चालान चेक करने का ऑनलाइन तरीका

स्टेप 1 : सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in पर जाना पड़ेगा।

स्टेप 2 : यहां पर चेक चालान स्टेटस (Check Challan Status) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3 : अब आपको आपको चालान नंबर, व्हीकल नंबर और DL नंबर तीन ऑप्शन दिखाई देंगे।

स्टेप 4 : ऊपर दिए ऑप्शन में से आपको व्हीकल नंबर ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना होगा।

स्टेप 5 : अब आपको व्हीकल नंबर की जगह आपको गाड़ी का नंबर भरना होगा।

स्टेप 6 : गाड़ी का चैसिस नंबर या इंजन नंबर के साथ कैप्चा कोड को दर्ज करके Get Detail पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 7 : अब अगले पेज पर आपको गाड़ी पर कोई चालान है, तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा।

2. ऐप से ट्रैफिक चालान चेक करने का तरीका

स्टेप 1 : आपको अपने मोबाइल फोन पर NextGen mParivahan ऐप को डाउनलोड करना होगा।

स्टेप 2 : ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ जरूरी जानकारी शेयर करके रजिस्टर करना होगा।

स्टेप 3 : इसके बाद आपको होम पेज पर ऊपर दिखाई दे रहे सर्च ऑप्शन पर अपनी गाड़ी नंबर डालना होगा।

स्टेप 4 : गाड़ी नंबर डालने के बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपके वाहन की डिटेल दिखाई देगी।

स्टेप 5 : इसी पेज पर आपको नीचे की तरफ डिटेल के नीचे व्यू चालान के ऑप्शन पर टैप करना होगा।

स्टेप 6 : अगर आपके गाड़ी पर चालान है तो उसकी जानकारी दिखेगी। अगर नहीं है तो "नो चालान फाउंड" लिखा दिखाई देगा।

3. वेबसाइट से ट्रैफिक चालान भुगतान का तरीका

स्टेप 1 : आपको आधिकारिक वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाना होगा।

स्टेप 2 : यहां पर आपको चालान नंबर/डीएल नंबर/वाहन नंबर में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना होगा।

स्टेप 3 : इसके बाद आपको मांगी गई सभी जानकारी को भरने के बाद कैप्चा दर्ज करना होगा।

स्टेप 4 : यहां पर आपको गेट डिटेल्स के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना होगा।

स्टेप 5 : फिर आपको दिखाई दे रहे Pay Now के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 6 : अब आपको चालान भुगतान के लिए पेमेंट मोड का चुनाव करना होगा।

स्टेप 7 : पेमेंट करने के बाद आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी, जिसे आप संभाल कर रख सकते हैं।

मारुति ईविटारा टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट, जल्द लॉन्च होगी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार

परिवहन विशेष न्यूज

हाल ही में Maruti eVitara को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। जिसे देखते के बाद इसके जल्द लॉन्च होने की उम्मीद बढ़ गई है। इसे मई 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। यह कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आने वाली है। इसमें कई बेहतरीन फीचर्स मिलेंगे। इसे दो बैटरी पैक के साथ पेश किया जाएगा जो चार्ज होने के बाद 500 किमी से ज्यादा की रेंज देंगे।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Maruti eVitara लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इसकी टेस्टिंग भी भारत में शुरू कर दी है। वहीं, यह टेस्टिंग के आखिरी पड़ाव पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे हाल ही में हरियाणा के गुड़गांव में टेस्टिंग के दौरान पूरे कैमोफ्लॉग के साथ स्पॉट किया गया है। आइए जानते हैं कि Maruti eVitara में क्या कुछ खास फीचर्स देखने के लिए मिलेगा।

स्टाइलिंग और स्पेसिफिकेसन

मारुति अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में लेकर आने वाली है। इसमें स्पोर्टी एलईडी हेडलैंप, मजबूत बम्पर देखने के लिए मिलेगा। इसके साइड प्रोफाइल में फेंडर पर मोटी क्लैडिंग, हैवी डोर मोल्डिंग और R18 एयरोडायनामिक अलॉय देखने के लिए मिलेंगे। इसमें रियर डोर हैंडल C-पिलर पर रखे गए हैं। पीछे की तरफ टेल लैंप को हेडलैंप के साथ दिया गया है।

इसमें डुअल-टोन इंटीरियर और डैशबोर्ड, वर्टिकल-ओरिएंटेड एयर वेंट, फ्लोटिंग सेंटर कंसोल और मल्टी-कलर इल्यूमिनेशन के साथ एम्बिएंट लाइटिंग मिलेगी। Maruti eVitara में फिक्स्ड ग्लास सनरूफ, 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे।

Maruti eVitara में 7-एयरबैग, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, टीपीएमएस और ब्रेक होल्ड फंक्शन के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। इसमें फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और 360 डिग्री व्यू कैमरा भी मिलेगा। साथ ही ADAS लेवल 2 फीचर, लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और हाई बीम सिस्टम भी मिलेगा।

बैटरी पैक और रेंज

इसमें दो बैटरी पैक 49-kWh और 61-kWh के साथ पेश किया जाएगा। इसे 2WD और AWD दोनों फॉर्मेट के साथ पेश किया जाएगा। इसकी बैटरी एक बार फुल चार्ज होने के बाद 500 किमी तक की रेंज देगी। इसकी अधिकतम गति 150-160 किमी/घंटा होगी।

भारत में कब होगी लॉन्च

Maruti eVitara की टेस्टिंग आखिरी चरण में चल रही है। इसे भारत में मई 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। भारतीय बाजार में इसकी कीमत 17 लाख रुपये से 30 लाख रुपये के रेंज में हो सकती है। भारत में इसका मुकाबला, हुंडई क्रेटा ईवी, टाटा कर्व ईवी, एमजी जेडएस ईवी और महिंद्रा बीई 6 से देखने के लिए मिलेगा।

पुरानी से कितनी अलग है नई होंडा डियो 125

परिवहन विशेष न्यूज

हाल ही में 2025 Honda Dio 125 को लॉन्च किया गया है। नई Dio 125 को कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही इसकी कीमत में भी बढ़ोतरी की गई है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको नई Dio 125 और पुराने मॉडल में कितना अंतर है। वहीं दोनों में किसमें ज्यादा बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं।

नई दिल्ली। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने हाल ही में भारत में 2025 Dio 125 को लॉन्च किया है। कंपनी ने इस स्पोर्टी स्कूटर के डिजाइन से लेकर उसकी अंडरपिनिंग को बरकरार रखा है, लेकिन इसे कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। इसे नया इंजन भी दिया गया है, जो OBD-2B उत्सर्जन मानदंड-अनुपालन करता है। आइए जानते हैं कि Honda Dio 125 के नए और पुराने मॉडल के बीच कितना अंतर है।

कीमत

2025 Honda Dio 125 को नए फीचर्स और इंजन के साथ लॉन्च किया गया है, जिसकी वजह से इसकी कीमत में बढ़ोतरी भी देखने के लिए मिली है। इसके बेस मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 96,749 रुपये और टॉप-एंड H-Smart वैरिएंट की कीमत 1,02,144 रुपये (1.02 लाख रुपये) है। नए मॉडल की तुलना में पुरानी Dio 125 की एक्स-शोरूम कीमत 87,851 रुपये से 93,750 रुपये थी। इसे बेस और टॉप वेरिएंट की कीमत में 8,898 रुपये और 8,394 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

वेरिएंट

2025 Honda Dio 125 को केवल दो वेरिएंट में पेश किया गया है, जो Standard और H-smart, है। वहीं, इसका पुराना मॉडल चार वैरिएंट में आता था, जो Standard, Standard 3D emblem, Smart और Smart 3D Emblem था। Standard और Standard 3D emblem के बीच केवल एक अंतर कलर स्कीम और लोगो का था।

इंजन

2025 Honda Dio 125 में 123.92cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो अब OBD-2B अनुरूप है। नया मॉडल 8.3PS की पावर और 10.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसका पहले की तुलना में 0.02PS और 0.1Nm ज्यादा है। इसका इंजन आइडल स्टार्ट-स्टॉप फीचर्स पैकेज का एक हिस्सा बनी हुई है। यह माइलेज को बढ़ाने में मदद करते हैं, जो भारी स्टॉप-एंड-गो ट्रैफिक में इस्तेमाल किया जाता है। नए मॉडल में पुराने मॉडल की तरह ही साइलेंट स्टार्टर भी दिया गया है।

फीचर्स

2025 Honda Dio 125 में 4.2-इंच TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और मैसेज अलर्ट जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है। इसमें USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। इसके टॉप-स्पेक H-Smart वैरिएंट में कीलेस सिस्टम को पहले की तरह ही दिया गया है। नए Dio 125 की तुलना में पुराने स्कूटर में फुल LCD कंसोल दिया गया था, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी फीचर के साथ नहीं आता था। इसमें स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, रियल टाइम माइलेज, औसत माइलेज, खाली होने की दूरी और साइड-स्टैंड डाउन इंजन कट-ऑफ फीचर जैसी जानकारी मिलती थी।

शिक्षा और रोजगार को पाटना

विजय गर्ग

शिक्षा और रोजगार को पाटना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली के व्यापक परिवर्तन का वादा करती है। इसकी सफलता न केवल दृष्टि पर, बल्कि 21 वीं शताब्दी के लिए शिक्षा को फिर से शुरू करने के लिए कार्रवाई, निवेश और एक एकीकृत राष्ट्रीय प्रतिबद्धता पर टिका है

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारत के शैक्षिक परिदृश्य को फिर से आकार देने के लिए एक ऐतिहासिक पहल है, विशेष रूप से मुख्यधारा की शिक्षा में व्यावसायिक प्रशिक्षण को एकीकृत करके। यह एकीकरण कौशल विकास और रोजगार को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, और यह 'समग्र शिक्षा' और कौशल भारत मिशन जैसी पहल को पूरक करता है।

पीएम श्री स्कूलों की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की दृष्टि का प्रतीक है, जो राष्ट्रव्यापी एक समग्र शैक्षिक अनुभव को बढ़ावा देता है। हालांकि, महत्वपूर्ण चुनौतियां इस महत्वाकांक्षी दृष्टि को साकार करने के रास्ते में खड़ी हैं।

कार्यान्वयन में चुनौतियां

एनईपी 2020 का प्राथमिक उद्देश्य - यह सुनिश्चित करने के लिए कि 2025 तक, कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को व्यावसायिक जोखिम प्राप्त होता है - कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। 2023 तक, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य वित्तीय बाधाओं, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और योग्य शिक्षकों की कमी के कारण कार्यान्वयन में काफी पिछड़ गए हैं। एक चौंका देने वाला 75 प्रतिशत तकनीकी संस्थान वर्तमान में पढ़ाए जा रहे कौशल और उद्योग द्वारा मांगे गए कौशल के बीच संरेखण की कमी की रिपोर्ट करता है, एक डिस्कनेक्ट को उजागर करता है जिसे संबोधित किया जाना चाहिए।

इन चुनौतियों के मूल में एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रम की कमी है जो नौकरी के बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मजबूत है।

सरकारी धक्का के बावजूद, व्यावसायिक शिक्षा में केवल 5 प्रतिशत छात्रों को आज के नौकरी बाजार से संबंधित क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है। कई पारंपरिक शैक्षणिक संस्थान व्यावसायिक शिक्षा को उनके पाठ्यक्रम में एकीकृत करने के लिए प्रतिरोधी बने हुए हैं, जिससे डर है कि यह अकादमिक कठोरता को कम कर सकता है।

इसके परिणामस्वरूप छात्रों के लिए अपर्याप्त जोखिम होता है, जिनमें से कई प्रतिस्पर्धी श्रम बाजार में पनपने के लिए आवश्यक कौशल के बिना स्नातक होते हैं।

इसके अलावा, उभरती प्रौद्योगिकियों, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और स्वचालन में प्रशिक्षित शिक्षकों में उल्लेखनीय कमी है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि 80 प्रतिशत से अधिक संस्थानों में इन आवश्यक क्षेत्रों में संकाय प्रवीणता की कमी है, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता से समझौता करते हैं।

आगे का रास्ता

आगे के पथ को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई योग्य रणनीतियों की आवश्यकता होती है कि व्यावसायिक शिक्षा स्कूल पाठ्यक्रम का एक मुख्य घटक बन जाए। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना, छात्रों को उनके चुने हुए क्षेत्रों में जारी रखना आवश्यक है।

उदाहरण के लिए, व्यावसायिक विषय के रूप में 'इलेक्ट्रीशियन' का चयन करने वाले छात्र को कक्षा 10 और उससे आगे के माध्यम से इस विषय के साथ जुड़ना जारी रखना चाहिए, एक गहरी, व्यावहारिक समझ सुनिश्चित करना चाहिए।

भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार एक वित्तीय प्रोत्साहन मॉडल लागू कर सकती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए 500 रुपये का मासिक वजीफा प्रदान करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण किट के साथ, नामांकन को बढ़ावा दे सकता है। जो छात्र अपनी उच्च कक्षाओं के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण में जारी रखते हैं, उनके लिए प्रति माह 1,000 रुपये का वजीफा निरंतर प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करेगा। स्नातक छात्रों को चार साल के बाद प्रमाणन प्राप्त करना चाहिए, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी रोजगार क्षमता को बढ़ाना चाहिए।

कौशल गैप को पाटना

1.5 मिलियन स्कूलों में 260 मिलियन से अधिक छात्रों और उच्च शिक्षा में 40 मिलियन से अधिक छात्रों के साथ भारत, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी छात्र आबादी में से एक है।

फिर भी, सकल नामांकन अनुपात लगभग 32 प्रतिशत है, जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार की तलाश करने के लिए कई को मजबूर करता है - शोषण और अंडरपेमेंट से भरा एक डोमेन।

व्यावसायिक शिक्षा में इस अंतर को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की क्षमता है। उद्योग-प्रासंगिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करके, ये कार्यक्रम न केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ाते हैं, बल्कि भविष्य के उद्यमियों के विकास को भी बढ़ावा देते हैं।

जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देश सफल दोहरी व्यावसायिक शिक्षा प्रणालियों का उदाहरण देते हैं,

जो उद्योग के अनुभव के साथ कक्षा सीखने को सम्मिश्रण करते हैं।

भारत इसी तरह के ढांचे को अपना सकता है, जिससे छात्रों को व्यावहारिक प्रदर्शन प्राप्त होता है, जो एक विकसित नौकरी परिदृश्य में तेजी से आवश्यक है।

इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का अनुकूलन

जैसे-जैसे तकनीकी नवाचार में तेजी आती है, व्यावसायिक कार्यक्रमों में एआई, आईओटी और क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित आधुनिक कौशल शामिल होने चाहिए। कक्षा VI से X के लिए पाठ्यक्रम में एआई और आईटटी को पेश करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की पहल सही दिशा में एक कदम है। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित 20,000 से अधिक शिक्षकों के साथ, लगभग 350,000 छात्रों तक पहुंचना, पर्याप्त प्रगति स्पष्ट है।

हालांकि, 2022 के एक सर्वेक्षण ने संकेत दिया कि 31 प्रतिशत शिक्षक अभी भी डिजिटल उपकरणों के साथ कुशल नहीं हैं, जबकि 2023 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि 49 प्रतिशत शिक्षक पर एआई के प्रभाव को दूर करने के लिए तैयार नहीं हैं। इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण में निवेश करना चाहिए जो बदलते बाजार के लिए शिक्षकों को लैस करता है।

कक्षाओं में एआई-संचालित शिक्षण उपकरण लाने के लिए एड-टेक कंपनियों के साथ सहयोग इस संक्रमण का समर्थन कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि छात्रों को प्रशिक्षण प्राप्त हो जो आधुनिक और प्रासंगिक दोनों है।

क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करते हुए हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा है कि राज्य एनईपी 2020 को लागू करना शुरू कर रहे हैं, कार्यान्वयन की गति बहुत भिन्न होती है।

रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि हरियाणा ने 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को पूरी तरह से लागू करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसका उद्देश्य 2030 तक उच्च शिक्षा में लड़कियों के सकल नामांकन अनुपात को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत से अधिक करना है।

हालांकि, राज्यों में विसंगतियां - धन की कमी, प्रशिक्षित संकाय की कमी और नौकरशाही जड़ता के कारण - न केवल विसंगतियां पैदा करती हैं, बल्कि नीति की क्षमता को भी काफी कम करती हैं।

एक स्तर के खेल क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए, प्रगति को ट्रैक करने और राज्यों में समान कार्यान्वयन को लागू करने के लिए एक केंद्रीकृत निगरानी तंत्र आवश्यक है।

निष्कर्ष एनईपी 2020 व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की स्कूली शिक्षा में एकीकृत करने के लिए एक परिवर्तनकारी अवसर प्रस्तुत करता है, लेकिन इसकी सफलता रणनीतिक कार्यान्वयन, पर्याप्त धन, बुनियादी ढांचे के विकास और मजबूत शिक्षक प्रशिक्षण पर टिका है।

जैसा कि भारत $ 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की इच्छा रखता है, एक व्यापक व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली में निवेश करना केवल एक शैक्षिक अनिवार्यता नहीं है - यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक रणनीति है।

कार्यान्वयन की बाधाओं को संबोधित करके, भारत अपने युवाओं को आवश्यक कौशल के साथ सशक्त बना सकता है, नवाचार और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा दे सकता है जो राष्ट्रीय विकास में योगदान करते हैं।

एक अच्छी तरह से लागू व्यावसायिक कौशल शिक्षा ढांचा छात्रों और सरकार दोनों के लिए एक जीत-जीत का प्रतिनिधित्व करता है, एक कुशल और आत्मनिर्भर कार्यबल के लिए आधारशिला रखता है जो भारत के आर्थिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्राचार्य शैक्षिक स्तंभकार गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

महंगी होती शिक्षा, बचपन पर बोझ और सरकार की चुप्पी शिक्षा का बढ़ता बाजारीकरण

विजय गर्ग

बचपन अतुलित आनंद यानी चंचलता और हंसने-हंसाने का नाम है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, 'चिंता रहित खेलना, खाना और निर्भय स्वच्छंद फिरना..! कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद।' इसलिए बचपन का स्वागत उत्साह एवं भावनाओं से हो। बच्चों के पाठ्यक्रम की चर्चा की जाए तो वह मनोरंजन, यानी हंसने-हंसाने के साथ अधिगम (समझ) हासिल करने वाला होना चाहिए। बरसों से यह बात सुर्खियों में रहती आई है कि गैरसरकारी और निजी स्कूल संचालकों द्वारा बच्चों की पढ़ाई के निमित्त मोटी फीस वसूली जाती है। पाठ्यक्रम के नाम पर भारी-भरकम पुस्तकें बचपन पर थोपी जा रही हैं। पाठ्य सामग्री ऊंची कीमत पर खरीदने के लिए अभिभावकों पर परोक्ष, तो कहीं-कहीं प्रत्यक्ष दबाव बनाया जाता है। शिक्षा खुलेआम बेची जा रही है और वह भी ऊंचे दामों पर। अभिभावक मजबूरी में खरीद रहे है। बच्चों की शिक्षा के नाम पर ऊंचे दाम पर शिक्षा बिकती है, मोटी रकम वसूली जा रही होती है, ऐसे में संबंधित प्रदेश और देश की सरकार का दायित्व उसे संभालने का होना चाहिए। आए दिन ऐसी खबरें प्रमुखता से छपती हैं कि निजी स्कूल ऊंचे दामों की किताबें और मोटी रकम फीस के तौर पर अभिभावकों से मांग कर रहे हैं।

वर्षों से शिक्षाविद इसकी मांग कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम चाहे बच्चों का हो या ऊंची कक्षाओं में एकरूपता होनी चाहिए। कहने का आशय यह है कि सरकारी स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम कुछ और हो, गैर सरकारी निजी स्कूलों के लिए कुछ और। जबकि इसमें एकरूपता परम आवश्यक है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस पर सख्ती दिखाई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद निजी विद्यालय द्वारा फीस वृद्धि नियंत्रित करने के लिए अनुशंसाएं करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। तब राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमेय) अधिनियम, २०१६ एवं नियम २०१७ निर्धारित कर लागू किए गए। इस अधिनियम में प्रत्येक विद्यालय में माता-पिता अध्यापक संगम की स्थापना करने और इस संगम की देखरेख में विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि निजी विद्यालय इस समिति के जरिए फीस वृद्धि करते हैं, लेकिन शासन और विभागीय अधिकारियों के स्तर से सूक्ष्म निगरानी और नियंत्रण नहीं होने के कारण इन समितियों के नाम पर विद्यालय द्वारा लीपापोती कर शुल्क वृद्धि कर लेने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नियम और व्यवस्था के नाम पर महज लीपापोती न होकर आवश्यकता इस बात की है कि शासन का प्रत्येक स्तर पर 'फ्रेंड फिलास्फर गाइड' यानी मित्र-दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार विद्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण हो। ऐसे वातावरण के निर्माण की आवश्यकता है, जिसमें विद्यालय शिक्षा का कार्य एक पुनीत, सामाजिक दायित्व और अपना स्वयं का कार्य मानकर पूर्ण प्रतिबद्धता तथा ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। वर्तमान में इस सिद्धांत के अनुसार काम कम ही हो रहा लगता है। ऐसा लगता है कि निजी स्कूलों को अपना पाठ्यक्रम निर्धारण करने और मनमानी फीस वसूलने का अधिकार दे दिया गया है।

शिक्षा का सार्वजनिकीकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी जरूरी हो सकती है, लेकिन बच्चों को क्या परोसा जा रहा है, उसकी पड़ताल सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वर्तमान में निजी क्षेत्र को सहायक सामग्री के रूप में पाठ्यक्रम लागू करने और बोर्ड के अतिरिक्त सभी तरीके के परीक्षा-पत्र अपने स्तर पर तैयार करने का अधिकार देने से शिक्षा की एकरूपता समाप्त हो रही है, वहीं शिक्षा बेलगाम तरीके से महंगी और बाजार आधारित होती जा रही है।

राज्य और केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के निर्धारित पाठ्यक्रम के साथ-साथ हर विषय के साथ एक सहायक सामग्री की पुस्तक लगाने की छूट देना शिक्षा को महंगी करने की राह तैयार करेगा। जिस प्रकार वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का अधिकार सरकार ने अपने पास नहीं रखा, ठीक उसी प्रकार शिक्षा तंत्र की फीस और पाठ्यक्रम निर्धारण का कार्य सरकार ने बाजार के हवाले कर दिया। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जिस प्रकार केंद्रीय और राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होता है, ऐसे में पाठ्यक्रम और परीक्षा-पत्रों की समानता बनी रहती है। नई शिक्षा नीति में बोर्ड की अवधारणा तो लगभग समाप्त किया जाना है, जिसके परिणाम भविष्य के गर्भ में हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि निजी शिक्षण संस्थानों का पाठ्यक्रम सरकारी पाठ्यक्रम से अलहदा न हो। नर्सरी से आठवीं कक्षा तक पाठ्यक्रम निर्धारण सरकार को करना चाहिए और सहायक शिक्षण सामग्री की छूट पर पाबंदी लगाना चाहिए। इससे निजी शिक्षण संस्थाओं के बेजा पाठ्यक्रम पर लगाम लगेगी। अभिभावकों पर पाठ्यक्रम के नाम पर महंगी किताबों पर अपने आप ही अंकुश लगेगा। उच्च पेशेवर शिक्षा में चिकित्सा, इंजीनियरिंग का एक ही पाठ्यक्रम होता है, एक ही परीक्षा होती है और उसकी फीस भी सरकार निर्धारित करती है। इसी प्रकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी एक पाठ्यक्रम और एक फीस का निर्धारण सरकारी स्तर पर किया जाना चाहिए, तभी मोटी फीस और महंगे पाठ्यक्रम से निजात मिलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष रहे देश के ख्यातनाम वैज्ञानिक और शिक्षाविद प्रोफेसर यश पाल की अध्यक्षता में गठित कमेटी (१९९२) की रपट 'लर्निंग विदाउट बर्डन' में वर्णित अनुशंसाओं को नए सिरे से विश्लेषित कर उस पर अमल की आवश्यकता है।

कहानी: मुझे जवाब दो

विजय गर्ग

इतिहास खुद को दोहराता है. एक दिन उस ने अपने मातापिता को घर से निकाल दिया था, उन्हें बेइज्जत किया था. लेकिन अब जब उस के अपने बच्चे उस के साथ वही सब करने लगे तो तब अपनों के प्यार के लिए उस का मन तड़प रहा था.

'प्रिय अग्रज, ''माफ करना, 'भाई' संबोधन का मन नहीं किया. खून का रिश्ता तो जरूर है हम दोनों में, जो समाज के नियमों के तहत निभाना भी पड़ेगा. लेकिन प्यार का रिश्ता तो उस दिन ही टूट गया था जिस दिन तुम ने और तुम्हारे परिवार ने बीमार, लाचार पिता और अपनी मां को मत्तैर यानी सौतेला कह, बांह पकड़ कर घर से बाहर निकाल दिया था. पैसे का इतना अहंकार कि सगे मातापिता को ठीकरा पकड़ा कर तुम भिखारी बना रहे थे.

''लेकिन तुम सबकुछ नहीं. अगर तुम ने घर से बाहर निकाला तो उन की बांहें पकड़ सहारा देने वाली तुम्हारी बहन के हाथ मौजूद थे. जिन से नाता रखने वाले तुम्हारे मातापिता ने तुम्हारी नजर में अक्षम्य अपराध किया था और यह उसी का दंड तुम ने न्यायाधीश बन दिया था.

''तुम्हीं वह भाई थे जिस ने कभी अपनी इसी बहन को फोन कर मांपिता को भेजने के लिए मिन्नतें की थीं, फरियाद की थी. बस, एक साल भी नहीं रख पाए, तुम्हारे चौकीदार जो नहीं बने वो.

''तुम से तो मैं ने जिंदगी के कितने सही विचार सीखे. कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम बुरी संगत में पड़, ऐशोआराम की जिंदगी जीने के लिए अपने खून के रिश्तों की जड़ें काटने पर तुल जाओगे.

''एक ही शहर में, दो कदम की दूरी पर रहने वाले तुम, आज पत्र लिख अपने मन की शांति के लिए मेरे घर आना चाहते हो. क्यों, क्या अब तुम्हारे परिवार को एतराज नहीं होगा?

''अब समझ आया न. पैसा नहीं, रिश्ते, अपनापन व प्यार अहम होते हैं. क्या पैसा अब तुम्हें मन की शांति नहीं दे सकता? अब खरीद लो मांबाप क्योंकि अपनों को तो तुम ने सौतेला बना दिया था.

''तुम्हीं ने छोटे भाईभावज को लालच दिया था अपने बिजनैस में साझेदारी कराने का लेकिन इस शर्त पर कि मातापिता को बहन के घर से बुला अपने पास रखो, घर अपने नाम करवाओ और इतना तंग किया करो कि वे घर छोड़ कर भाग जाएं. तुम ने उन से यह भी कहा था कि वे बहन से नाता तोड़ लें. इतनी शर्तों के साथ करोड़ों के बिजनैस में छोटे भाई को साझेदारी मिल जाएगी, लेकिन साझेदारी दी क्या?

''हमें क्या फर्क पड़ा. अगर पड़ा तो तुम दोनों नकारे व सफेद खून रखने वाले पुत्रों को पड़ा. पुलिस व समाज में जितनी थूथू और जितना मुंह काला छोटे भाईभावज का हुआ उतना ही तुम्हारा भी क्योंकि तुम भी उतने ही गुनाहगार थे. मत भूलो कि झूठ के पैर नहीं होते और साजिश का कभी न कभी तो परदाफाश होता है.

''ठीक है, तुम कहते हो कि इतना सब होने के बाद भी मांपिताजी ने तुम्हें व छोटे को माफ कर दिया था. सो, अब हम भी कर दें, यह चाहते हो? वो तो मांबाप थे 'नौहां तो मांस अलग नईं कर सकदे सी', (नाखूनों से मांस अलग नहीं कर सकते थे.) पर, हम तुम्हें माफ क्यों करें?

''क्या तुम अपने बीवीबच्चों को घर से बाहर निकाल सकते हो? नहीं न. क्या मांबाप लौटा सकते हो?

''अब तुम भी बुढ़ापे की सीढ़ी पर पैर जमा चुके हो. इतिहास खुद को दोहराता है, यह मत भूलना. अब चूंकि तुम्हारा बेटा बिजनैस संभालने लगा है तो तुम्हारी स्थिति भी कुछकुछ मांपिताजी जैसी होने लगी है. अगर बबूल बोओगे तो आम नहीं लगेंगे. सो, अपने बुरे कृत्यों का दंश व दंड तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा. क्षमा करना, मेरे पास तुम्हारे लिए जगह व समय नहीं है.

''बेरहम नहीं हूं मैं. तुम मुझे मेरे मातापिता लौटा दो, मैं तुम्हें बहन का रिश्ता दे दूंगी, तुम्हें भाई कहूंगी. मुझे पता है उन के आखिरी दिन कैसे कटे. आज भी याद करती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. वो दशरथ की तरह पुत्रवियोग में बिलखतेविलापते, पर तुम राम न बन सके. निर्मोही, निष्ठुर यहां तक कि सौतेला पुत्र भी ऐसा व्यवहार नहीं करता होगा जैसा तुम ने किया.

''तुम लिखते हो, 'बेहद अकेले हो.' फोन पर भी तो ये बातें कर सकते थे पर शायद इतिहास खुद को दोहराता 'तुम उन के फोन की बैटरी निकाल देते थे. खैर, जले पर क्या नमक छिड़कना. जरा बताओ तो, तुम्हें अकेला किस ने बनाया? तुम्हें तो बड़ा शौक था रिश्ते तोड़ने का. अरे, ये तो मांपिताजी के चलते चल रहे थे. तुम तो रिश्ते हमेशा पैसों पर तोलते रहे. बहन, बूआ, बेटी, ननद इन सभी रिश्तों की छीछालेदर करने वाले तुम और तुम्हारी पत्नी व बेटी अब किस बात के लिए शिकायत करती फिर रही हैं. जो रिश्तेनाते अपनापन जैसे शब्द व इन की अहमियत तुम्हारी जिंदगी की किताब में कभी जगह नहीं रखते थे, उन के बारे में अब इतना क्यों तड़पना. अब इन रिश्तों को जोड़ तो नहीं सकते. उस के लिए अब नए समीकरण बनाने होंगे व नई किताब लिखनी होगी. क्या कर पाओगे ये सब?

''ओह, तो तुम्हें अब शिकायत है अपने बेटेबहू से कि वे तुम्हें व तुम्हारी पत्नी को बूढ़ेबुढ़िया कह कर बुलाते हैं. ये शब्द तुम ही लाए थे होस्टल से सौगात में. चलो, कम से कम पीढ़ीदरपीढ़ी यह सम्मानजनक संबोधन तुम्हारे परिवार में चलता रहेगा. बधाई हो, नई शुरुआत के लिए और रिश्तों को छीजने के लिए.

''खैर, छोड़ो इन कड़वी बातों को. मीठा तो तुरंत मुंह में घुल जाता है पर कड़वा स्वाद काफी देर तक रहता है और फिर कुछ खाने का मन भी नहीं करता. सो, अब रोना काहे का. कहां गई तुम्हारी वह मित्रमंडली जिस के सामने तुम मांपिता को लताड़ते थे. क्यों, क्या वे तुम्हारे अकेलेपन के साथी नहीं या फिर आजकल महफिलें नहीं जमा पाते. बेटे को पसंद नहीं होगा यह सब?

सवालों के घेरे में स्वास्थ्य सेवाएं

देश में आज भी पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यही वजह है कि आबादी का बड़ा हिस्सा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए भटकना पड़ता है। देश में अस्पतालों और चिकित्सकों की उपलब्धता जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बहुत कम है। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं, आधारभूत संरचना, चिकित्सकों, दवाइयों, कुशल और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ, कमरे और दूसरी सुविधाओं की कमी है। इन्हीं अभावों के कारण देश में निजी स्वास्थ्य क्षेत्र को विस्तार करने का मौका मिल गया, जिसका गरीब लोगों से कोई वास्ता नहीं। जबकि स्वास्थ्य सेवा किसी 'भी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का एक महत्त्वपूर्ण मापदंड है, क्योंकि बिना स्वस्थ समाज के किसी भी देश का आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास संभव नहीं है।

भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र लगातार सुधार और विस्तार का केंद्र रहा है। हालांकि, अभी भी हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इनके समाधान के लिए सरकार काम कर रही है। अब भी स्वास्थ्य क्षेत्र में स्थिति दयनीय बनी हुई है। यही वजह है कि हर साल करोड़ों भारतीय महंगे होते इलाज के कारण आर्थिक रूप से बर्बादी के कगार पर पहुंच जाते हैं। एक रपट के मुताबिक अस्पतालों के भारी-भरकम बिल भरने की वजह से भारत में हर साल करीब छह करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। ऐसे लोग इलाज के लिए कर्ज लेते हैं। इसका प्रमुख कारण सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक आम लोगों की पहुंच नहीं होना है।

असली भारत गांव में बसता है, मगर गांव के लोगों की सेहत की देखभाल करने वाले चिकित्सा केंद्र आज भी बदतर ही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा विशेषज्ञों की काफी कमी देखी जाती। शहर और गांव के एक ऐसी खाई बन गई है कि इसके नतीजे भविष्य में काफी भयावह हो सकते हैं। भले ही देश' में तरक्की के कितनी भी दावे किए जाएं, पर गांवों में करीब 60 से 70 फीसद चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी होना अपने आप में कई सवाल पैदा करता है। ऐसे में स्वस्थ भारत खुशहाल भारत कैसे बनेगा। यह एक बड़ा सवाल है। निस्संदेह सरकार हर साल स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों रुपए का बजट पेश करती है, लेकिन आज भी देश की स्वास्थ्य सेवाएं सवालों के घेरे में हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति किसी से छिपी नहीं है।

शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं, जिससे मानव संसाधन को बेहतर बनाया जा सकता है। अमर्त्य सेन का कहना है कि उदारीकरण के लिए चाहे जितने भी क्षेत्र खोल दें, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें हर हाल में सरकारी नियंत्रण में होना चाहिए। मगर ऐसी सलाह पर कौन ध्यान देता है? कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, नार्वे, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान और आस्ट्रेलिया जैसे देशों में दुनिया की सबसे अच्छी स्वास्थ्य

सेवाएं दी जा रही हैं। मगर भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में बिना ज्यादा पैसे खर्च किए, अच्छी स्वाथ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। जाहिर है, आबादी लगातार बढ़ने के बावजूद आधारभूत ढांचे में सुधार पर जितना ध्यान देना चाहिए, उतना नहीं दिया गया। यह विडंबना तब है, जब देश में इन समस्याओं से निपटने के लिए सभी जरूरी कार्यक्रम और नीतियां मौजूद हैं, लेकिन इन्हें ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। हालांकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की घोषणा और क्रियान्वयन से यह आस जगी थी कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ।

आश्चर्य है कि भारत अपनी कुल जीडीपी का करीब दो फीसद हिस्सा भी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च नहीं करता, जो 141 करोड़ आबादी वाले देश के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यह ठीक है कि आयुष्मान भारत योजना जैसे सरकारी कार्यक्रमों ने करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। फिर भी, स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी कई समस्याएं हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले महीने राज्यसभा में बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का खर्च सकल घरेलू उत्पाद के 1.84 फीसद तक पहुंच गया है। उन्होंने दावा किया कि यह धीरे-धीरे 2.5 फीसद के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। साफ है, दूसरे विकासशील देशों की बराबरी के लिए हमें काफी कुछ करना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च का वैश्विक स्तर छह फीसद माना गया है। छह फीसद का आंकड़ा भारत कब हासिल करेगा, इसका कोई अनुमान नहीं है। साफ है, स्वास्थ्य शायद भारत के राजनीतिक एजेंडे के प्राथमिक बिंदुओं में नहीं रहा।

अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भी लगातार जोर देते रहे हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किसी एकीकृत कार्ययोजना की सख्त जरूरत है। उनका मानना है कि आर्थिक प्रगति के साथ-साथ सामाजिक प्रगति भी उतनी ही जरूरी है। यदि हम चीन और भारत के आर्थिक विकास की तुलना करें, तो चीन के आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण उसका स्वास्थ्य एवं शिक्षा में निवेश करना रहा है। भारत को भी अपने नागरिकों को विश्व की स्पर्धा में आगे लाने के लिए उन्हें यह उपहार देना होगा। फिक्की के एक सर्वे के मुताबिक 65 फीसद भारतीय बीमार होने पर महंगे इलाज के कारण कर्ज में फंस जाते हैं। इनमें से तीन फीसद तो ऐसे हैं, जो बीमारी पर खर्च की वजह से गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। इतना ही नहीं, बीमारी पर होने वाला 61 फीसद खर्च जेब से दिया जाता है। यानी इसके लिए न तो कोई बीमा होता है और न कोई दूसरी योजना। वहीं हमारा देश हृदय, गुर्दा और श्वास रोगों का घर बनता जा रहा है। मधुमेह के लिए तो उसे विश्व की राजधानी ही कहा जाने लगा है। 'नेशनल हेल्थ सर्वे' में यह बात सामने आई है से 49 वर्ष के पुरुषों में दिल की बीमारी मौत का प्रमुख कारण बन रही है। यह ठीक है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च की जाने वाली राशि का बजट में प्रावधान लगातार बढ़ाया जा रहा है, पर स्वास्थ्य क्षेत्र में जितनी उपलब्धता होनी चाहिए, उतनी अभी नहीं हो पाई है। फिर भी, बीते कुछ वर्षों में भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति की है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त उपलब्ध है। सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी आसान पहुंच हो और कम खर्च में इलाज हो सके। दरअसल, किसी भी देश के लिए उसके नागरिकों का स्वास्थ्य एक बड़ी पूंजी होता है। यदि नागरिक स्वस्थ हैं, तो वहां की सरकार देश की सुरक्षा, शिक्षा समेत अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश और प्रगति पर ध्यान दे सकती है। सही है कि भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम हुआ है, पर अभी बहुत काम होना बाकी है।

-विजय गर्ग

पढ़ाई की कीमत

बचपन अतुलित आनंद यानी चंचलता और हंसने- हंसाने का नाम है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, 'चिंता रहित खेलना, खाना और निर्भय स्वच्छंद फिरना..! कैसे भूला जा सकता है, बचपन का अतुलित आनंद।' इसलिए बचपन का स्वागत उत्साह एवं भावनाओं से हो। बच्चों के पाठ्यक्रम की चर्चा की जाए तो वह मनोरंजन, यानी हंसने-हंसाने के साथ अधिगम (समझ) हासिल करने वाला होना चाहिए। बरसों से यह बात सुर्खियों में रहती आई है कि गैरसरकारी और निजी स्कूल संचालकों द्वारा बच्चों की पढ़ाई के निमित्त मोटी फीस वसूली जाती है। पाठ्यक्रम के नाम पर भारी-भरकम पुस्तकें बचपन पर थोपी जा रही है। पाठ्य सामग्री ऊंची कीमत पर खरीदने के लिए अभिभावकों पर परोक्ष, तो कहीं- कहीं प्रत्यक्ष दबाव बनाया जाता है। शिक्षा खुलेआम बेची जा रही है और वह भी ऊंचे दामों पर। अभिभावक मजबूरी में खरीद रहे है। बच्चों की शिक्षा के नाम पर ऊंचे दाम पर शिक्षा बिकती है, मोटी रकम वसूली जा रही होती है, ऐसे में संबंधित प्रदेश और देश की सरकार का दायित्व उसे संभालने का होना चाहिए। आए दिन ऐसी खबरें प्रमुखता से छपती हैं कि निजी स्कूल ऊंचे दामों की किताबें और मोटी रकम फीस के तौर पर अभिभावकों से मांग कर रहे हैं।

वर्षों से शिक्षाविद इसकी मांग कर रहे हैं। कि पाठ्यक्रम चाहे बच्चों का हो या ऊंची कक्षाओं में एकरूपता होनी चाहिए। कहने का आशय यह है कि सरकारी स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम कुछ और हो, गैर सरकारी निजी स्कूलों के लिए कुछ और। जबकि इसमें एकरूपता परम आवश्यक है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस पर सख्ती दिखाई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद निजी विद्यालय द्वारा फीस वृद्धि नियंत्रित करने के लिए अनुशंसाएं करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। तब राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमेय) अधिनियम, 2016 एवं नियम 2017 निर्धारित कर लागू किए गए। इस अधिनियम में प्रत्येक विद्यालय में माता-पिता अध्यापक संगम की स्थापना करने और इस संगम की देखरेख में विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन करने का प्रावधान किया गया है

हालांकि निजी विद्यालय इस समिति के जरिए फीस वृद्धि करते हैं, लेकिन शासन और विभागीय अधिकारियों के स्तर से सूक्ष्म निगरानी और नियंत्रण नहीं होने के कारण इन समितियों के नाम पर विद्यालय द्वारा लीपापोती कर शुल्क वृद्धि कर लेने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नियम और व्यवस्था के नाम पर महज लीपापोती न होकर आवश्यकता इस बात की है कि शासन का प्रत्येक स्तर पर 'फ्रेंड फिलास्फर गाइड' यानी मित्र - दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार विद्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण हो। ऐसे वातावरण के निर्माण की आवश्यकता है, जिसमें विद्यालय शिक्षा का कार्य एक पुनीत, सामाजिक दायित्व और अपना स्वयं का कार्य मानकर पूर्ण प्रतिबद्धता तथा ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। वर्तमान में इस सिद्धांत के अनुसार काम कम ही हो रहा लगता है। ऐसा लगता है। कि निजी स्कूलों को अपना पाठ्यक्रम निर्धारण करने और मनमानी फीस वसूलने का अधिकार दे दिया गया है।

शिक्षा का सार्वजनिकीकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी जरूरी हो सकती है, लेकिन बच्चों को क्या परोसा जा रहा है, उसकी पड़ताल सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वर्तमान में निजी क्षेत्र को सहायक सामग्री के रूप में पाठ्यक्रम लागू करने और बोर्ड के अतिरिक्त सभी तरीके के परीक्षा - पत्र अपने स्तर पर तैयार करने का अधिकार देने से शिक्षा की एकरूपता समाप्त हो रही है, वहीं शिक्षा बेलगाम तरीके से महंगी और बाजार आधारित होती जा रही है।

राज्य और केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के निर्धारित पाठ्यक्रम के साथ-साथ हर विषय के साथ एक सहायक सामग्री की पुस्तक लगाने की छूट देना शिक्षा को महंगी करने की राह तैयार करेगा। जिस प्रकार वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का अधिकार सरकार ने अपने पास नहीं रखा, ठीक उसी प्रकार शिक्षा तंत्र की फीस और पाठ्यक्रम निर्धारण का कार्य सरकार ने बाजार के हवाले कर दिया। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जिस प्रकार केंद्रीय और राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होता है, ऐसे में पाठ्यक्रम और परीक्षा - पत्रों की समानता बनी रहती है।

नई शिक्षा नीति में बोर्ड की अवधारणा तो लगभग समाप्त किया जाना है, जिसके परिणाम भविष्य के गर्भ में हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि निजी शिक्षण संस्थानों का पाठ्यक्रम सरकारी पाठ्यक्रम से अलहदा न हो। नर्सरी से आठवीं कक्षा तक पाठ्यक्रम निर्धारण सरकार को करना चाहिए और सहायक शिक्षण सामग्री की छूट पर पाबंदी लगाना चाहिए। इससे निजी शिक्षण संस्थाओं के बेजा पाठ्यक्रम पर लगाम लगेगी। अभिभावकों पर पाठ्यक्रम के नाम पर महंगी किताबों पर अपने आप ही अंकुश लगेगा। उच्च पेशेवर शिक्षा में चिकित्सा, इंजीनियरिंग का एक ही पाठ्यक्रम होता है, एक ही परीक्षा होती है और उसकी फीस भी सरकार निर्धारित करती है। इसी प्रकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी एक पाठ्यक्रम और एक फीस का निर्धारण सरकारी स्तर पर किया जाना चाहिए, तभी मोटी फीस और महंगे पाठ्यक्रम से निजात मिलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष रहे देश के ख्यातनाम वैज्ञानिक और शिक्षाविद प्रोफेसर यश पाल की अध्यक्षता में गठित कमेटी (1992) की रपट 'लर्निंग विदाउट बर्डन' में वर्णित अनुशंसाओं को नए सिरे से विश्लेषित कर उस पर अमल की आवश्यकता है।

-विजय गर्ग

जब उपराष्ट्रपति भी पूछें — 'क्या यह न्याय है?'

यह खबर नहीं, एक हृदयविदारक चीख है—भारत के लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की आत्मा को झकझोरने वाली, असहाय करुण पुकार। जब देश के उपराष्ट्रपति को यह सवाल उठाना पड़े कि एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश के आवास से नगदी की बेशर्म और खुलेआम बरामदगी जैसे जघन्य, विश्वासघाती मामले में प्राथमिकी तक दर्ज क्यों नहीं हुई, तो यह महज एक घटना नहीं है। यह हमारी व्यवस्था की उन गहरी, डरावनी और शर्मनाक दरारों का नंगा आईना है, जो भ्रष्टाचार की जड़ों, जवाबदेही की घोर कमी और जनता के विश्वास के क्षरण को उजागर करता है। यह एक ऐसा दंश है, जो हमें न केवल आत्ममंथन के लिए मजबूर करता है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करता है कि क्या हमारी न्यायिक और लोकतांत्रिक संस्थाएं अब भी उस नैतिकता और पारदर्शिता का दम रखती हैं, जिसकी नींव पर यह देश खड़ा है।

सोचिए, अगर यही घटना किसी आम आदमी के घर पर हुई होती तो पुलिस और प्रशासन तुरंत कार्रवाई करते, पुलिस रातोंरात छापा मारती, घर की तलाशी लेती, और कुछ ही घंटों में वह शख्स सलाखों के पीछे होता। मीडिया उसकी जिंदगी के हर कोने को उधेड़ देता, और समाज उसे अपराधी ठहराने में देर न करता। लेकिन जब बात सत्ता और पद के करीब पहुंचने वालों की होती है, तो वही व्यवस्था मौन हो जाती है। न कोई प्राथमिकी, न कोई जांच, न कोई जवाब। यह खामोशी सिर्फ चिंताजनक नहीं, बल्कि खतरनाक है। यह उस सोच को पोषित करती है, जो मानती है कि कुछ लोग कानून से ऊपर हैं, कि कुछ पद इतने ऊंचे हैं कि उन तक न तो सवाल पहुंच सकते हैं, न ही सजा। यह सवाल सिर्फ कानून की किताबों का नहीं, बल्कि उस विश्वास का है, जो हर नागरिक अपनी न्यायपालिका और संविधान में रखता है। यह चुप्पी, यह निष्क्रियता, यह दोहरा मापदंड—क्या यही हमारा लोकतंत्र है? क्या यही वह भारत है, जहां संविधान की प्रस्तावना में समानता और न्याय का वादा किया गया था?

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का यह सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि हर उस नागरिक का है, जो इस व्यवस्था में अपने लिए न्याय की उम्मीद रखता है। उन्होंने पूछा, और ठीक ही पूछा, कि आखिर क्यों एक 'संरक्षित श्रेणी' को अभियोजन से छूट मिले? यह सवाल इसलिए और भी गहरा है, क्योंकि यह देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद से उठा है। यह सवाल उस आम आदमी की आवाज है, जो रोजाना छोटे-छोटे मामलों में व्यवस्था की जटिलताओं से जूझता है, फिर भी उम्मीद करता है कि शायद एक दिन उसे निष्पक्ष न्याय मिलेगा। लेकिन जब न्याय देने वाले पर ही सवाल उठें, और फिर भी कोई कार्रवाई न हो, तो वह उम्मीद धीरे-धीरे मरने लगती है।

यह मामला सिर्फ नगदी का नहीं है। यह उस गहरी खाई का प्रतीक है, जो हमारे समाज में समानता और विशेषाधिकार के बीच खिंच चुकी है। एक तरफ आम नागरिक है, जिसके लिए कानून की तलवार हमेशा तैयार रहती है। दूसरी तरफ वे लोग हैं, जिनके पद और रसूख उन्हें हर बार बचा लेते हैं। यह दोहरा मापदंड न सिर्फ संविधान की भावना के खिलाफ है, बल्कि लोकतंत्र के मूल आधार को भी खोखला करता है। अगर कानून सबके लिए बराबर नहीं है, तो फिर वह कानून नहीं, बल्कि सत्ता का हथियार है। और जब यह धारणा समाज में जड़ें जमाने लगती है, तो लोग व्यवस्था से भरोसा उठाने लगते हैं। वे न्याय को सिर्फ किताबों और भाषणों की बात समझने लगते हैं, क्योंकि हकीकत में उन्हें कुछ और ही दिखता है।

न्यायपालिका हमेशा से लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ रही है। यह वह संस्था है, जो संविधान की रक्षा करती है, जो कमजोर को ताकत देती है, और जो गलत को सजा देती है। लेकिन जब उसी न्यायपालिका की जवाबदेही पर सवाल उठने लगें, तो हम किसके पास जाएं? क्या हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था है, जो न्यायपालिका के भीतर की खामियों को ठीक कर सके? क्या हम सचमुच यह मान सकते हैं कि न्यायपालिका आलोचना से परे है? अगर हम ऐसा करते हैं, तो हम अनजाने में एक ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं, जो धीरे-धीरे अपने ही मूल्यों से दूर होती जा रही है। न्यायपालिका की स्वायत्तता जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसकी पारदर्शिता और जवाबदेही। बिना इनके, वह सिर्फ एक शक्तिशाली संस्था बनकर रह जाएगी, न कि न्याय का मंदिर।

इस घटना में कार्रवाई न होने का तर्क कि न्यायाधीश एक 'संरक्षित श्रेणी' में आते हैं, न सिर्फ हास्यास्पद है, बल्कि खतरनाक भी। यह तर्क संविधान के उस मूल सिद्धांत को चुनौती देता है, जो कहता है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। अगर हम यह मान लें कि कुछ लोग अपनी स्थिति के कारण जांच से बच सकते हैं, तो हम एक ऐसे समाज की नींव रख रहे हैं, जहां शक्ति ही सच बन जाएगी। यह न केवल सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करेगा, बल्कि लोगों के मन में कानून के प्रति जो थोड़ा-बहुत विश्वास बचा है, उसे भी खत्म कर देगा। यहां एक और सवाल उठता है—क्या हमारी व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि वह अपने ही ढांचे की खामियों को नहीं देख पा रही? या फिर यह जानबूझकर की गई चुप्पी है, ताकि कुछ खास लोगों को बचाया जा सके? दोनों ही स्थितियां चिंताजनक हैं। अगर यह कमजोरी है, तो हमें इसे सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। और अगर यह साजिश है, तो यह और भी गंभीर है, क्योंकि तब हमारा लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा।

उपराष्ट्रपति का हस्तक्षेप इस मामले में एक उम्मीद की किरण है। यह दिखाता है कि अभी भी कुछ लोग हैं, जो व्यवस्था की खामियों को सामने लाने और उन पर सवाल उठाने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन यह हस्तक्षेप तभी सार्थक होगा, जब इसके बाद ठोस कार्रवाई हो। हमें एक ऐसी न्याय व्यवस्था चाहिए, जो न सिर्फ निष्पक्ष हो, बल्कि ऐसा दिखे भी। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए, जहां कोई भी—चाहे वह आम नागरिक हो या हाई कोर्ट का न्यायाधीश—कानून से ऊपर न हो। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए, जहां सवाल उठाना अपराध न हो, बल्कि जवाब देना अनिवार्य हो।

-प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

समझदारी: एक पेंडिंग अपडेट जो कभी डाउनलोड नहीं होती

कहते हैं उम्र के साथ समझदारी आती है। लेकिन हमारे यहाँ उम्र सिर्फ़ चश्मे का नंबर, बालों की सफेदी और घुटनों का दर्द लाती है। समझदारी? वो तो बचपन में ही किसी सरकारी योजना की तरह ₹लॉन्चर होकर गायब हो जाती है। जिम्मेदारी और उम्र का रिश्ता भी अजीब है—कभी दोनों गलबहियाँ डालकर चलते हैं, कभी एक-दूसरे से आँखें चुराते हैं। और इस आँख-मिचौली में ज़िंदगी बस तमाशबीन बनी तालियाँ बजाती रहती है।

जरा गुड्डू को देखिए। चौदह साल की उम्र, लेकिन ज़िंदगी का टाइमटेबल किसी ग्लोबल कंपनी के सीईओ को भी मात दे। सुबह साइकिल पर अखबार बाँटता है, मानो हाई-स्पीड डिलीवरी ड्रोन पर सवार हो, दिन में स्कूल की बेंच घिसता है, जहाँ टीचर ₹पढ़ाई करो, जिम्मेदार बनो₹ का प्रवचन देते हैं और रात को माँ का सिर दबाकर सुलाता है, कहेंगे, ₹जिम्मेदारी, ये 24x7 स्टार्टअप का वन-मैन-आर्मी हो, क्योंकि ₹बाबूजी ने तो कब का फोन स्विच ऑफ कर लिया₹। पूछो तो मासूमियत से कहेगा, ₹जिम्मेदारी ने पकड़ लिया, भैया।₹ मानो जिम्मेदारी कोई पुलिसवाला हो, जो बिना वारंट धर दबोच ले। गुड्डू की उम्र में बच्चे ₹पबजी खेलते हैं, वहाँ ये ज़िंदगी का ₹सर्वाइवल मोड₹ खेल रहा है।

अब दूसरी तरफ हैं हमारे प्रदीप चाचाजी। उम्र 60 पार, सरकारी नौकरी से रिटायर्ड, पेंशन की गंगा बह रही है। लेकिन जिम्मेदारी? वो तो उनके लिए ₹अननोन कॉलर₹ है, जिसे वो बार-बार रिजेक्ट कर देते हैं। गैस सिलेंडर बुक करना हो तो बीवी को पुकारते हैं—₹सुनो, वो मोबाइल में कुछ कर दो न।₹ यूपीआई, ओटीपी, ऑनलाइन बिल पेमेंट—ये सब उनके लिए एलियन टेक्नोलॉजी है। लेकिन फेसबुक? वहाँ सुबह 6:30 बजे ₹गुड मॉर्निंग₹ के साथ गुलाब की फोटो और ₹ज़िंदगी दो पल की, जी लो₹ वाला स्टेटस डालने में पीएचडी कर रखी है। व्हाट्सएप पर ₹फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स₹ वाले मैसेज की स्पीड देखकर तो लगता है, चाचाजी 5जी नेटवर्क पर चल रहे हैं। जिम्मेदारी इनके दरवाजे तक दस्तक देती है, पर चाचाजी ₹नॉट होम₹ का बोर्ड लगाकर अखबार फड़फड़ाते हुए चाय की चुस्कियाँ लेते रहते हैं।

यहाँ जिम्मेदारी भी तो ऑनलाइन शॉपिंग की तरह है। किसी को बिना ऑर्डर किए ही थमा दी जाती है, जैसे गुड्डू को। और किसी को बार-बार रिक्वेस्ट करने पर भी ₹आउट ऑफ स्टॉक₹ का मैसेज मिलता है, जैसे चाचाजी को। छोटे बच्चों को देखकर जिम्मेदारी का दिल पसीज जाता है—₹लो, तुम ही संभाल लो ये बोझ, तुम्हारे बाप-दादा तो रील्स बनाने में व्यस्त हैं।₹ और कुछ बुजुर्गों को देखकर वो शर्म से पानी-पानी हो जाती है—₹इतने साल हो गए, अब भी नहीं संभाल सकते? ठीक है, बच्चों को ही दे देते हैं।₹ ये जिम्मेदारी भी न, व्यक्ति देखकर आती है। कुछ को गले का हार बनकर गले पड़ती है, और कुछ के लिए वो ₹रिटर्न पॉलिसी₹ वाला पैकेज है, जिसे वो तुरंत डिलीवरी बॉय को लौटा देते हैं।

हमारे देश में दो ही चीज़ें टाइम से पहले आती हैं—बालों में सफेदी और जिम्मेदारी। बाकी सब तो सरकारी स्कीम की तरह—घोषणा जोर-शोर से, डिलीवरी अगले जन्म में। लोग जिम्मेदारी से ऐसे भागते हैं जैसे रिश्तेदार की शादी में ₹नेग₹ देने से। ₹अरे, अब इस उम्र में क्या।₹ मानो जिम्मेदारी कोई फिटनेस चैलेंज हो और उम्र उनका मेडिकल सर्टिफिकेट। कुछ लोग तो जिम्मेदारी को देखकर वैसे ही मुकर जाते हैं, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर का सामान देखकर—₹ये तो मँगा ही नहीं था।₹

जिम्मेदारी के भी अपने टाइप हैं। कुछ जिम्मेदारियाँ ₹डिजर्व₹ की जाती हैं, जैसे गुड्डू अपनी माँ की देखभाल करता है। कुछ को ₹डेलिगेट₹ कर दिया जाता है, जैसे चाचाजी सारा काम बीवी पर डाल देते हैं। और कुछ तो जिम्मेदारी को कचरे की पेटी में डंप करने के चैंपियन हैं, जैसे वो पड़ोसी, जो मोहल्ले की मीटिंग में बड़े-बड़े वादे करते हैं, मगर सफाई अभियान का वक्त आए तो ₹बुखार चढ़ गया₹ का बहाना मारकर गायब हो जाते हैं।

समाज में जिम्मेदारी का बोझ भी अजीब तरह से बँटता है। बच्चों को स्कूल बैग के साथ-साथ घर का बोझ भी ढोना पड़ता है। जवानों को नौकरी, शादी, बच्चों की परवरिश—सब एक साथ संभालना पड़ता है। और बुजुर्ग? वो तो ₹हमने तो अपना समय देख लिया₹ कहकर पार्क में टहलने निकल लेते हैं। फिर भी दुनिया कहती है, ₹उम्र के साथ समझदारी आती है।₹ अरे भाई, यहाँ उम्र के साथ सिर्फ़ हड्डियों का दर्द, आँखों का धुंधलापन और ₹वो पुरानी बात याद नहीं आ रही₹ वाला बहाना आता है। जिम्मेदारी निभाने की नीयत? वो तो जन्मकुंडली में ही नहीं लिखी होती।

और सबसे मजेदार बात? जिम्मेदारी से भागने वाले लोग दूसरों को ₹जिम्मेदार बनो₹ का प्रवचन देने में सबसे आगे होते हैं। जैसे चाचाजी, जो गैस सिलेंडर बुक करना नहीं जानते, लेकिन मोहल्ले के बच्चों को ₹आजकल की पीढ़ी बेकार है₹ का लेक्चर देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। या वो पिताजी, जो बेटे को ₹कमाओ, घर चलाओ₹ का मंत्र देते हैं, लेकिन बिजली का बिल जमा करने की बात आए तो ₹छोड़ो, तुम्हीं देख लो, हम तो ये ऑनलाइन सिस्टम समझ नहीं आता।₹

जिम्मेदारी और उम्र का ये खेल बड़ा विचित्र है। कुछ लोग इसे बोझ को गर्व से ढोते हैं, जैसे गुड्डू, जो अपनी छोटी सी उम्र में परिवार का सहारा बना है। और कुछ लोग इसे फुटबॉल की तरह ठोकर मारते रहते हैं, जैसे चाचाजी, जिनके लिए ज़िंदगी अब बस चाय की चुस्कियों और फेसबुक स्टेटस तक सिमट गई है। लेकिन सच कहें, जिम्मेदारी कोई उम्र देखकर नहीं आती। वो तो बस मौका देखकर टपक पड़ती है, और फिर आप चाहे चौदह साल के हों या साठ के, आपको उसका सामना करना ही पड़ता है। तो अगली बार जब कोई कहे, ₹उम्र के साथ समझदारी आती है,₹ तो बस मुस्कुरा दीजिए। क्योंकि यहाँ समझदारी नहीं, सिर्फ़ जिम्मेदारी का जाल आता है, जिसमें फँसने या निकलने का हुनर ही असली समझदारी है।

-प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

विश्व लिवर दिवस 19 अप्रैल 2025 - संतुलित भोजन ही ताकतवर औषधि है

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर प्रतिवर्ष करीब करीब प्रत्येक दिवस को किसी न किसी ईवेंट या दिवस के रूप में राष्ट्रीय या वैश्विक स्तरपर समर्पित किया गया है, जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो मानव शरीर, उसके कार्य, व्यवसाय तथा क्रियाओं से लेकर राष्ट्र व स्वास्थ्य के प्रति समर्थित होता है, उस प्रत्येक दिन के संबंध में विस्तृत रूप से छोटे से बड़े करीब करीब हर व्यक्ति के लिए जन जागरण का आवाहन होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे खान-पान और लाइफ स्टाइल का असर हमारी सेहत पर सीधा पड़ता है। गलत खानपान, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और तनाव जैसे कारणों से कई गंभीर बीमारियां जन्म लेती हैं, इनमें से एक आम समस्या है फैटी लिवर, इसमें लिवर पर एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है। शुरू में लोग इसे नजर अंदाज करते हैं पर अगर ये दिक्कत बढ़ जाए तो इसकी वजह से शरीर कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 19 अप्रैल २०२५ को मानव शरीर में मस्तिष्क के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले लीवर का ध्यान रखनें का दिवस है। चूँकि हमारी दिनचर्या और आहार में गड़बड़ी ने लीवर को बहुत क्षति पहुंचाई है तथा लीवर मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है जो विष हरण चयापच्या और पाचन क्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाता है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, विश्व लिवर दिवस 19 अप्रैल २०२५ संतुलित भोजन ही ताकतवर औषधि है। इस आर्टिकल में लिखी गई बातें परामर्श सुझाव मात्र हैं।

साथियों बात अगर हम 19 अप्रैल २०२५ को विश्व लिवर दिवस मनाने की करें तो,यह अपरिहार्य अंग के बारे में जागरूकता पैदा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत में, लिवर रोग का बोझ बहुत अधिक है, लाखों लोग फैटी लिवर और सिरोसिस से पीड़ित हैं, ऐसी स्थितियाँ जो दुखद रूप से हर साल अनगिनत लोगों की जान ले लेती हैं।अस्वास्थ्यकर जीवनशैली की आदतें जैसे अत्यधिक शराब का सेवन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और संतृप्त वसा से भरपूर आहार और शारीरिक गतिविधि की कमी इसके प्रमुख कारण हैं। अब समय आ गया है कि हम इस पर ध्यान दें और सक्रिय कदम उठाएँ। हमारा लीवर हमारे शरीर का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी है, जो हमको बेहतरीन स्थिति में रखने के लिए अथक प्रयास करता है।पाचन,विषहरण, और यहां तक कि पुनर्जीवन के बारे में सोचें - हमारा लीवर यह सब संभालता है। क्या हम जानते हैं कि जब लीवर का काम करना बंद हो जाता है तो क्या होता है? फैटी लीवर रोग, सिरोसिस और यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है,कभी-कभी इसकेपरिणाम अपरिवर्तनीय हो सकते हैं।

साथियों बात अगर हम लीवर के स्वास्थ्य में चार स्तंभों की करें तो, हमारा लीवर हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा काम करने वाले अंगों में से एक है। यह विषाक्त पदार्थों को छानता है, वसा को तोड़ता है, पाचन में मदद करता है और ज़रूरी पोषक तत्वों को संग्रहीत करता है। इसे बेहतरीन स्थिति में रखने के लिए, लीवर के स्वास्थ्य के चार मुख्य स्तंभ हैं: (1) संतुलित पोषण--हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारे लीवर पर पड़ता है। हम एंटी ऑक्सीडेंट, फाइबर और स्वस्थ वसा से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं। पत्तेदार सब्जियां, हल्दी, लहसुन, खट्टे फल और साबुत अनाज लीवर के काम करने में मदद करते हैं। बहुत ज़्यादा चीनी, तले हुए खाद्य पदार्थ और प्रोसेस्ड स्नैक्स का सेवन सीमित करें। (२) नियमित शारीरिक गतिविधि--व्यायाम करने से लीवर में वसा का संचय कम होता है। व्यायाम इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है और वजन नियंत्रण में मदद करता है। हम सप्ताह में 5 बार कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। यह पैदल चलना, योग या शक्ति प्रशिक्षण हो सकता है। (३) विषाक्त पदार्थों और शराब का सेवन सीमित करें--लीवर हमारे द्वारा खाए और पिए जाने वाले हर पदार्थ को फ़िल्टर करता है। शराब और अत्यधिक दवाओं का सेवन आपके लीवर को ओवरलोड और नुकसान पहुंचा सकता है। शराब को कम करने या खत्म करने की कोशिश करें, और दवाओं का उपयोग केवल तभी करें जब ज़रूरत हो और डॉक्टर की सलाह पर ही करें।(4) नियमित जांच और हाइड्रेशन-- नियमित रूप से लिवर फंक्शन टेस्ट करवाने से समस्याओं का जल्दी पता लगाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, दिन भर में खूब पानी पिएं - यह विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे लिवर को हाइड्रेटेड और सक्रिय रखता है।जब सभी चार स्तंभ एक साथ काम करते हैं, तो वे यकृत के स्वास्थ्य और दीर्घकालिक कल्याण के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं।

साथियों बात अगर हम मानवीय किया में लिवर के महत्वपूर्ण स्थान की करें तो, हमारा लीवर हर दिन कड़ी मेहनत करता है, विषाक्त पदार्थों को छानना, हार्मोन को संतुलित करना और पाचन को सहारा देना। लेकिन जिस तरह हमारे फोन को रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे लीवर को भी नियमित रूप से डिटॉक्स की ज़रूरत होती है। हमको महंगे जूस या कठोर क्लीन्ज़र की ज़रूरत नहीं है। ये छह सरल, प्राकृतिक आदतें हमारे लीवर को प्यार महसूस करने और उसके बेहतरीन तरीके से काम करने में मदद कर सकती हैं: (1) हमारे दिन की शुरुआत गर्म नींबू पानी से करें--हमारे लीवर को जगाने का सबसे आसान तरीका है हर सुबह ताजे नींबू के रस के साथ गर्म पानी पीना।

नींबू,विटामिन- सी से भरपूर फल , लीवर को विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और पित्त उत्पादन को शुरू करने के लिए उत्तेजित करता है। यह एक छोटी सी रस्म है जो लीवर के स्वास्थ्य और पाचन के लिए बड़े लाभ देती है। (२) हल्दी का उपयोग खाना पकाने में या टॉनिक के रूप में करें--हल्दी हमारे लीवर के लिए एक स्वर्णिम कवच की तरह है। हल्दी में मौजूद शक्तिशाली यौगिक करक्यूमिन में सूजनरोधी और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होते हैं। हल्दी को करी या दूध में मिलाएँ, या फिर हल्दी की साधारण चाय बनाएँ। नियमित सेवन से लीवर को नुकसान से बचाने में मदद मिलती है, डिटॉक्स में मदद मिलती है और लीवर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित भी किया जा सकता है।हम अपने लीवर की सुरक्षा के लिए हल्दी वाली कॉफी के फायदे भी आज़मा सकते हैं। (३) आंतरायिक उपवास का अभ्यास करें (सावधानी के साथ)--हमारे पाचन तंत्र के लिए ब्रेक लेने से आपका लीवर डिटॉक्सिंग पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और लगातार भोजन को प्रोसेस नहीं कर सकता। आंतरायिक उपवास (जैसे 16:8) लीवर के कार्य को बढ़ाने और लीवर में वसा के संचय को कम करने के लिए सिद्ध हुआ है। बस खाने के समय स्वस्थ भोजन का सेवन करना सुनिश्चित करें। (4) डेंडिलियन चाय के साथ हरियाली अपनाएं--सदियों से डंडेलियन जड़ का इस्तेमाल प्राकृतिक लिवर क्लींजर के रूप में किया जाता रहा है। यह पित्त उत्पादन को प्रेरित करता है, आपके शरीर को वसा को तोड़ने और विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में सहायता करता है। भोजन के बाद डंडेलियन चाय का एक गर्म कप पाचन में मदद कर सकता है और लिवर को धीरे-धीरे डिटॉक्स करने में सहायता कर सकता है। (5) लसीका समर्थन के लिए ड्राई ब्रशिंग--ड्राई ब्रशिंग सिर्फ़ चमकदार त्वचा के लिए ही अच्छी नहीं है। यह आसान आदत रक्त संचार को बढ़ाती है और लसीका तंत्र को उत्तेजित करती है, जो लीवर के साथ समन्वय करके अपशिष्ट को बाहर निकालता है। नहाने से पहले प्राकृतिक ब्रिसल वाले ब्रश से गोलाकार गति में ब्रश करें ताकि बाहर से अंदर तक डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ाया जा सके। (6) चुकंदर को अपने आहार में शामिल करें--चुकंदर में बीटालेन और नाइट्रेट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो लीवर एंजाइम की गतिविधि को बढ़ाते हैं और भारी धातुओं और अपशिष्ट को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। अपने सिस्टम को साफ करने और लीवर की तन्यकता को बढ़ाने के लिए भुने हुए चुकंदर, चुकंदर की स्मूदी या चुकंदर के जूस का सेवन करें।

साथियों बात अगर हम हमारे लीवर के घरेलू उपाय की करें तो, फैटी लिवर के लिए घरेलू उपाय (1) आंवला का सेवन करें- आंवला में विटामिन सी एंटी ऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, जो लिवर को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। रोज डेली 1-२ आंवला कच्चा खाएं या आंवले का रस पीएं, ये लिवर की सूजन को कम करने और उसकी फंक्शनेलिटी बढ़ाने में सहायक है। (२) ग्रीन टी का सेवन ।ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन्स लिवर में फैट के जमाव को कम करने में मदद करते हैं,रोजाना एक कप ग्रीन टी पीने से लिवर की सफाई होती है, ये शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। (३) हल्दी का उपयोग करें-हल्दी में करक्यूमिन कंपाउंड होता है, जो लिवर को डिटॉक्स करता है,एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर रोज सुबह पिएं, ये सूजन को कम करता है और लिवर को हेल्दी रखता है। (4) सेब का सिरका--सेब का सिरका फैट को कम करने और लिवर को डिटॉक्स करने में सहायक होता है,एक गिलास पानी में एक चम्मच सेब का सिरका मिलाकर खाली पेट पिएं. ये वजन घटाने में भी मदद करता है। (5) नींबू पानी का सेवन,नींबू में विटामिन सी होता है, जो लिवर को हेल्दी रखने में मदद करता है,रोजाना सुबह गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पिएं। ये शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। (६) पपीते के बीज का सेवन, पपीते के बीज फैटी लिवर के लिए नैचुरल उपचार हैं ।पपीते के कुछ बीज पीसकर उसका पाउडर बनाएं। इसे एक चम्मच दही में मिलाकर खाएं. इससे हमको बहुद जल्द असर देखने को मिलेगा। वैसे इन घरेलू उपायों को आजमाने से पहले डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

अत: अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि विश्व लिवर दिवस 19 अप्रैल २०२५- संतुलित भोजन ही ताकतवर औषधि है ।हमारी दिनचर्या और आहार में गड़बड़ी ही लीवर को गंभीर क्षति पहुंचा सकती है ।लीवर मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है जो विष हरण,चयापचय और पाचन क्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

व्यंग्य : "डर बिकता है"

विवेक रंजन श्रीवास्तव

हारर फिल्मों में डर का उत्पादन एक फैक्ट्री की तरह होता है—एकदम फॉर्मूला बेस्ड डर, जैसे स्कूल में पीरियड के लिए घंटी बजते ही सारे बच्चे अनुशासन में आ जाते थे, वैसे ही इन फिल्मों में डराने के लिए पत्तों की ₹सरसराहट₹ और बिजली की कड़कड़ होती है। निर्देशक की सोच किसी भूतिया हवेली में जाती है, वहां कैमरा पहुंचते ही पत्ते सरसराने लगते हैं । दरवाजा चूं चरर चूं की आवाज करता है और प्रकाश मद्धिम होता है, मकड़ी के जाले, धूल बोनस में मिलते हैं, पर एक चौकीदार हवेली में जाने किसकी तीमारदारी के लिए सुलभ मिलता है।

भूत का भय भूत से बड़ा होता है। डर ही पैदा करना है , तो सीधे भूत को सामने लाइए, ये पेड़ों में लटकाकर भूत को सजा देने मुझे क्या तुक है?

और बारिश, हर भूतिया कहानी में बारिश होती ही है? क्या भूतों का मौसम विभाग से कोई अनुबंध है? जहां डर की आवश्यकता हो, वहां तुरंत ₹घनघोर घटा₹ , आंधी आ जाती है। बिजली गायब हो जाती है और आती है, व्हाया आसमान , लरजती चमकती कड़कती है, जैसे किसी पुराने बिजली विभाग के कर्मचारी ने आसमान में एक्स्ट्रा ओवरटाइम लगाया हो।

हारर फिल्में एक खास ध्वनि प्रभाव पर जीती हैं।

साउंड इंजीनियर के ट्रेक फिक्स हैं, दरवाजा के पल्ले खोलते ही वह चरमराता है, बैकग्राउंड में पायल के घुंघरू छनकाते सफेद वस्त्रावृत महिला दूर जाती दिखती है ।

इतने पर भी जब समझदार दर्शकों के रोंगटे खड़े नहीं होते तो

किसी चमगादड़ को अचानक उड़ाना पड़ता है साउंड इफेक्ट दर्शक में डर भरने का काम करता है ।आता है । इस मुकाम के आते आते फिल्म समीक्षक दस में से कितने स्टार देने हैं , तय कर चुकते हैं ।

हर हारर फिल्म में एक कहानी श्लोक की तरह दोहराई जाती है। "पचास साल पहले इस हवेली में एक साध्वी की निर्मम हत्या हुई थी... तबसे उसकी आत्मा यहां भटक रही है।"

मतलब पचास साल हो गए, और आत्मा अभी भी निकलने वाला मूड नहीं बना पाई ! इतने सालों में उसे कोई आत्मा विकास केंद्र न मिल पाया।

ये फिल्मी आत्माएं भी पुरानी हवेलियों में ही क्यों भटकती हैं? रेलवे स्टेशन, नए नए खुल रहे एयर कंडीशन मॉल या बिजली विभाग के दफ्तर में क्यों नहीं दिखतीं? शायद वहां डराने से पहले ही उन्हें टिकट या बिजली बिल भरना पड़ता हो।

पुरानी एवरेडी वाली टार्च की रोशनी में जब बुजुर्ग चौकीदार खड़खडाहट की तरफ रोशनी डालता है तो काली बिल्ली नजर आती है ।

भूत भी इतने सभ्य होते हैं कि हमेशा रात का ही इंतजार करते हैं। दिन में अगर कोई डरावना सीन हो जाए तो सेंसर बोर्ड शायद उस भूत की नागरिकता रद्द कर दे। और जब भूत आता है, तो कैमरा जूम इन करता है—तीन बार, तीन एंगल से—मानो भूत की कोई इंस्टाग्राम रील बन रही हो ! कुछ फिल्मों में तो भूत खुद को इतना स्टाइलिश दिखाते हैं कि लगने लगता है जैसे वो कोई ब्यूटी पार्लर से निकलकर सीधे शूट पर आए हों। बाल लहराते हुए , भूरी आंखों में काजल, और चाल में स्लो मोशन—भूत कम, फैशन शो के प्रतिभागी लगते हैं।

नायक या नायिका अकेले किसी कोठरी में जाता है, और वहां दीवार पर खून से लिखा होता है— "भाग जा !" लेकिन वो उल्टा पूछता है, "कौन है?" अरे, लिखा है भाग जा, तो भाग ! पर हॉरर फिल्म का राइटर पंगा लेता ही है।

ओझा या तांत्रिक की एंट्री होती है, मनोरंजन डबल , इस बीच एक गाना सैट हो जाता है। बाबा लोग हमेशा काले कपड़े में आते हैं ।

अग्नि प्रज्ज्वलित की जाती है। आत्मा भी मानो स्क्रिप्ट पढ़कर आई हो, बड़बोले बिना समझे मंत्रों के साथ अग्नि में विलीन होकर मुक्त हो जाती है। दर्शक के सिर से बोझ उतर जाता है, और पारस से रुपए । समय के साथ कुछ फिल्मों ने थोड़ा मॉडर्न टच दिया है। अब भूत व्हाट्सऐप पर भी दिखने लगे हैं। कोई कोई भूत चैट पर "I am watching you" jaisa मेसेज भेजता है। भूत भी डिजिटल हो गए हैं, अब डराने के लिए टिकटॉक ट्रेंड नहीं, इंस्टा फिल्टर यूज़ करते हैं।

बहरहाल डर वह भाव है जो बिकता है, बस कोई हॉरर फिल्म बना सके तो।

हमशक्ल दिवस: जहाँ नकल भी एक अनोखी कला है

समान चेहरों में छिपी असाधारण पहचान का उत्सव

भारत, जहाँ हर चेहरा एक अनकही दास्तान बुनता है और हर दास्तान विविधता के रंगबिरंगे फूल बिखेरती है, वहाँ उत्सव केवल परंपराओं का स्पर्श नहीं, बल्कि रचनात्मकता और मौलिकता का उमंग भरा आलम भी हैं। ऐसा ही एक अनूठा, मनोरंजक और आनंदमयी अवसर है हमशक्ल दिवस, जो हर साल 20 अप्रैल को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन उन विशेष लोगों को समर्पित है जो किसी मशहूर शख्सियत—चाहे वह सिनेमा का जगमगाता सितारा, राजनीति का प्रेरक चेहरा, या खेल का अजेय नायक—से हूबहू मिलते-जुलते हैं। वर्ष 2025 में इस उत्सव की थीम ₹हमशक्लः समानता में विविधता₹ है, जो बाहरी समानता के उत्सव के साथ-साथ व्यक्तित्व की अनूठी छाप, हास्य, और सामाजिक जुड़ाव का एक जीवंत मंच रचती है। यह केवल चेहरों की नकल का जश्न नहीं, बल्कि एक ऐसा रंगारंग पर्व है जो हमें पहचान, मानवीय विविधता, और साझा खुशियों के गहरे अर्थों से जोड़ता है, हँसी, प्रेरणा, और एकता का अनमोल समन्वय रचता है। भारत में यह दिन इसलिए खास है क्योंकि यहाँ हर चेहरा अपनी विशिष्टता के साथ-साथ किसी न किसी की याद दिलाता है, और यही इसकी थीम ₹हमशक्ल₹ को और प्रासंगिक बनाती है।

हमशक्ल दिवस की शुरुआत 1980 के दशक में अमेरिका से हुई, जब पत्रकार जैक एटकिंसन ने एक मजेदार और अनोखे विचार को जन्म दिया। एक हल्के-फुल्के मजाक के रूप में शुरू हुआ यह उत्सव धीरे-धीरे वैश्विक मंच पर चमक उठा और आज भारत में भी जोश और उमंग के साथ गले लगाया जा रहा है। यहाँ सिनेमा, खेल और राजनीति के प्रति लोगों का अटूट जुनून इस दिन को और भी रंगीन और जीवंत बनाता है। सुपरस्टार्स के हमशक्ल—चाहे वे फिल्मों में डुप्लीकेट किरदारों से दर्शकों का दिल जीतें, स्टेज पर शानदार प्रदर्शन से तालियाँ बटोरें, या सोशल मीडिया पर वायरल सनसनी बनें—न केवल मनोरंजन का खजाना हैं, बल्कि सामाजिक संवाद और हँसी का एक अनमोल केंद्र भी बनते हैं। भारत में यह दिन इसलिए और खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ हर चेहरा अपनी अनूठी पहचान के साथ किसी न किसी की याद दिलाता है।

2025 की थीम ₹हमशक्लः समानता में विविधता₹ न केवल बाहरी समानता का उत्सव मनाती है, बल्कि यह भी उजागर करती है कि एक जैसे चेहरों के पीछे कितनी गहरी और रंगबिरंगी विविधता छिपी हो सकती है। यह थीम भारत की सांस्कृतिक आत्मा के तारों को छूती है, जहाँ चेहरों की समानता के बावजूद हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और जीवनशैली एक अनूठी कहानी बुनती है। यह हमें सिखाती है कि हमशक्ल होना महज चेहरे की नकल नहीं, बल्कि एक-दूसरे की विशिष्ट पहचान को समझने, उसका सम्मान करने और उसे गले लगाने का एक सुनहरा अवसर है। साथ ही, यह थीम उन प्रतिभाशाली कलाकारों को भी श्रद्धांजलि देती है, जो वर्षों से सेलिब्रिटी हमशक्ल के रूप में अपनी कला से दर्शकों का मनोरंजन करते आए हैं। यह समाज में हास्य, रचनात्मकता और मौलिकता के रंग बिखेरती है, हमें एकजुटता और प्रेरणा का एक जीवंत मंच प्रदान करती है।

भारत में हमशक्ल दिवस का उल्लास सामाजिक मंचों पर अपनी चरम पराकाष्ठा को छूता है, जहाँ जनमानस अपने प्रिय प्रसिद्ध व्यक्तित्वों—चाहे वे चित्रपट के चमकते सितारे हों, खेल के अपराजेय नायक हों, या राजनीति के प्रभावशाली चेहरे—के रूप-रंग और अंदाज को अपनाकर छोटी-छोटी मनमोहक चलचित्र कथाएँ रचता है। ये रचनाएँ, चित्र और प्रदर्शन रातोंरात लोकप्रियता की बुलंदियों को स्पर्श कर लेते हैं, जो न केवल हँसी और मनोरंजन का खजाना बिखेरते हैं, बल्कि सामाजिक जुड़ाव का एक अनुपम उत्सव भी बन जाते हैं। यह दिवस उन अनुपम व्यक्तियों को एक शानदार मंच प्रदान करता है, जो किसी अन्य के समान दिखने की अपनी अद्भुत विशेषता को गर्व के साथ विश्व के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उनकी यह खूबी केवल बाहरी समानता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक सृजनात्मक कला, एक अनमोल कौशल और व्यक्तित्व की अनूठी अभिव्यक्ति बनकर उभरती है। चाहे वे मंच पर किसी सितारे की हाव-भाव की नकल कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध करें, या सामाजिक मंचों पर अपनी रचनाओं से लाखों दिल जीत लें, ये हमशक्ल कलाकार समाज में हास्य और प्रेरणा का अनमोल प्रकाश फैलाते हैं।

हमशक्ल दिवस केवल हँसी-ठिठोली का उत्सव नहीं, बल्कि समाज को उसका प्रतिबिंब दिखाने वाला एक गहन मंच है। यह प्रश्न उठाता है: क्या हमारी पहचान केवल चेहरे की रेखाओं तक सीमित है? क्या किसी और जैसे दिखना गर्व का विषय है, या यह सृजनात्मक अभिव्यक्ति का रंगमंच है? यह पर्व हमें चिंतन के लिए प्रेरित करता है कि सच्ची समानता चेहरों में नहीं, बल्कि विचारों, मूल्यों और चरित्र की गहराइयों में बसती है। 2025 की थीम ₹हमशक्लः समानता में विविधता₹ इस दर्शन को और प्रखर करती है, जो हमें सिखाती है कि बाहरी समानता के परे हर व्यक्ति की अपनी अनूठी कहानी, अपनी अनमोल विशिष्टता है। यह उत्सव हास्य और प्रेरणा का संगम रचता है, जो हर मन को झंकृत कर देता है।

हमशक्ल दिवस भारत जैसे देश में एक अनुपम महत्त्व रखता है, जहाँ पहचान के प्रश्न हर दिल में गूँजते हैं। यह उत्सव सृजनात्मकता को पंख देता है, हास्य की फुलझड़ियाँ बिखेरता है और सामाजिक एकता के बंधन को और सुदृढ़ करता है। साथ ही, यह हमें स्मरण कराता है कि प्रसिद्धि और छवि के आकर्षण में डूबे रहने के बावजूद, हमें अपनी मौलिकता का आलिंगन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह पर्व उन अद्भुत व्यक्तियों को सम्मानित करता है, जो किसी और के समान दिखते हुए भी अपनी मेहनत, हुनर और सृजनात्मकता से समाज में एक विशिष्ट पहचान रचते हैं, अपने सपनों को साकार करते हैं।

20 अप्रैल, 2025 को जब हम हमशक्ल दिवस का उत्सव मनाएँगे, तो यह केवल चेहरों की समानता का जश्न नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा स्वर्णिम अवसर होगा जो हमें विविधता में निहित एकता की असीम शक्ति का साक्षात्कार कराएगा। यह दिन हमें हँसने, सृजन करने और सबसे बढ़कर, प्रत्येक व्यक्ति की अनूठी पहचान का आदर करने की प्रेरणा देता है। इस उत्सव को एक ऐसे रंगारंग पर्व के रूप में मनाएँ, जो चेहरों की समानता के बहाने हमें यह सिखाए कि सच्ची सुंदरता हमारी सोच, हमारे चरित्र और हमारे कर्मों की गहराई में बसती है। यह उत्सव हर दिल को जोड़े, हर मन को प्रेरित करे और समाज में प्रेम व एकता का संदेश बिखेरे।

-प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

झारखंड के मुख्यमंत्री ने योजनाओं का लिया जायजा, तय समय में जनता को समर्पित हो

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड, झारखंड

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सभी विभागों को वित्तीय वर्ष 2025- 26 में कम से कम तीन ऐसी योजनाओं का चयन करने का निर्देश दिया है, जिसे एक से डेढ़ साल के अंदर राज्य की जनता को समर्पित किया जा सके । ये योजनाएं धरातल पर तय समय सीमा में प्रभावी तरीके से उतरनी चाहिए । योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो उसका त्वरित और पूर्ण समाधान निकालें। मुख्यमंत्री आज झारखंड मंत्रालय में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव,प्रधान सचिव, सचिवों मे के साथ विभिन्न योजनाओं को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जिन योजनाओं का चयन किया जाए, उसमें पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए । योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन योजनाओं के लिए जो भी संसाधन की जरूरत हो, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों द्वारा जिन योजनाओं का चयन किया जाए, वह पूरी तरह पारदर्शी, प्रभावी और असरदायक होनी चाहिए। इसके लिए सकारात्मक और मजबूत कदम उठाए जाएं, ताकि उसका फायदा राज्य की जनता को सहूलियत के साथ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा की योजनाएं औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। कोई भी योजना तभी सार्थक साबित होती है, जब उसका लाभ लोगों को सही समय पर मिलता है । ऐसे में जो भी जरूरी योजनायें संचालित हो, उसे समय से पहले पूरा करने का प्रयास करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम के पूर्व पेयजल और मॉनसून के पहले जल प्रबंधन तथा जाड़े का मौसम शुरू होने के पूर्व कंबल वितरण की व्यवस्था दुरुस्त कर ली जानी चाहिए। वहीं, नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले ही विद्यार्थियों के बीच पठन- पाठन सामग्री और साइकिल का वितरण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कई और जरूरी योजनाएं हैं, जिसको तय समय से पहले पूर्ण करने का प्रयास करें ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को आय, जाति आवासीय, जन्म और मृत्यु जैसे प्रमाण पत्र बनवाने के लिए काफी चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसी शिकायतें लगातार मिलती रहती है। लोगों को कई बार समय पर ऐसे प्रमाण पत्र नहीं मिलने से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की ओर से कई फ्लैगशिप योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान करने की दिशा में हमने प्रयास शुरू कर दिए हैं।

बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार समेत सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव , प्रधान सचिव , सचिव एवं कई अन्य अधिकारी मौजूद थे।

सुभद्रा रथ के तर्ज पर सरायकेला में होगा नये रथ का निर्माण, ओडिशा से आयेगे बढ़ाई

कार्तिक कुमार परिच्छा स्टेट हेड झारखंड

सरायकेला , नये रथ निर्माण को लेकर सरायकेला जगन्नाथ मंदिर मे श्री जगन्नाथ सेवा समिति की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक अध्यक्ष सिद्धार्थ शंकर सिंह देव उर्फ राजा सिंहदेव की अध्यक्षता में आयोजित की गयी । ओडिशा से आये रथ निर्माण बढ़ाई कारीगर /रथोभोई (ओड़िया भाषा) के साथ कुल रू 400000 (चारलाख)धनराशि से रथ निर्माण हेतु एक इकरारनामे हस्ताक्षरित कर पांच समान किस्तों में निर्माण राशि प्रदान करने पर विचार विमर्श के बाद मुहर लगी । ओडिशा के गुरू पदो महाराणा की सात सदस्यीय टीम प्रस्तावित रथ का निर्माण करेगे । अगले अक्षय तृतीया से काम श्री गणेश होगा । जो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथी पूर्व बनकर तैयार हो जायेगा । जिसके बाद विधिवत राजा सरायकेला के निर्देश एवं जगन्नाथ महाप्रभु परंपरा के आज्ञा अनुसार निर्माण किया जायेगा ।जहां स्थानीय विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेगें।

आज कई दशकों बाद सरायकेला जगन्नाथ मंदिर में चीर प्रतिक्षित पुराना रथ को बदले एवं नये रथ निर्माण कार्य को अमली जामा पहनाया गया । ओडिशा के निमापोडा से आये बढ़ाई कारीगर ने बताया कि वे पुरी जगन्नाथ से आदेश लेकर आज आये है , आगे इसका निर्माण कुल सात बढ़ाई सेवक आकर आरंभ करेगें ।

इसका विधिवत पूजा अर्चना अगले 30 अप्रैल बुधवार अक्षय तृतीया के दिन करने के बाद निर्माण कार्यों में सभी जुट जायेंगे । निमापोडा से आये रथ निर्माण कर्ता पुरी बडदांड के मां सुभद्रा के रथ की तरह ही प्रस्तावित रथ को निर्मित करेंगे । आज बढ़ाई सेवक के प्रमुख गुरू पदो महाराणा एवं मंदिर के समिति अध्यक्ष राजा सिंहदेव के साथ इस विषय पर इस बाबत एक इकरारनामा हस्ताक्षरित हुआ है ।

अक्षय तृतीया के दिन मंदिर के मुल संरक्षक राजा सरायकेला प्रताप आदित्य सिंहदेव एवं सरायकेला के विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड चंपाई सोरेन को रथ का आरंभिक पूजन अवसर पर आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया । राजे राजबाड़े के दिनों में यहां 16 चक्का का भव्य रथ होता था , वह जगन्नाथ पुरी के रथ तरह दिखाई पड़ता था । परन्तु बिहार एवं झारखंड सरकार में घोर अवहेलना का शिकार ओडिया भाषा एवं संस्कृति , साहित्य आदि क्षेत्र रहा है । यद्यपि यह एक ओडिशा का ओड़िआ रियासत रहा जिसके देवता जगन्नाथ रहें । स्थानीय पूजा अर्चना , ऐतिहासिक स्थलों की रखरखाव की दिशा में सभी सरकारें निषक्रिय रही है सरायकेला के मामले में । केन्द्र का साफ निर्देश सरायकेला के मंदिरों की संरक्षण पर आजाद भारत में बिहार सरकार को दी गयी थी पर उसके कान में जूं तक नहीं रेंगना आश्चर्य की बात रही बाद में । कालान्तर में स्थानीय लोगों का जगन्नाथ सेवा समिति ने ऐन केन प्रकारेण अपनी आध्यात्मिक अनुष्ठान, मंदिरों का रख रखाव का महत्वपूर्ण योगदान दिया है विगत तीस पैंतीस वर्ष से ।

आजके इस बैठक में अध्यक्ष सिद्धार्थ शंकर सिंहदेव , उपाध्यक्ष सुदीप पट्टनायक, उपाध्यक्ष सानंद आचार्य ,सचिव पार्थ सारथी दाश , कोषाध्यक्ष शंकर सत्पथी , बादल दुवे, चद्र शेखर कर , चित्रा देवी, कोल्हू महापात्र, लिपु मोहान्ती , गणेश सत्पथी , मनोबोध मिश्रा, सुशांत महापात्र तथा कार्तिक कुमार परिच्छा आदि अनेकों गणमान्य जगन्नाथ भगवान के भक्त उपस्थित थे ।

साहित्यकार, कवि और ग़ज़ल राइटर में होनी चाहिए खास बातें

1. भावनात्मक गहराई,,,, साहित्यकार, कवि और ग़ज़ल राइटर को अपने अनुभवों और भावनाओं को गहराई से समझने और व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए।

2. भाषा और शैली,,,, उन्हें अपनी भाषा और शैली को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, जिससे उनके शब्दों में प्रभाव और सौंदर्य बढ़ सके।

3. जीवन के अनुभव,,,,जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उन पर लिखने की क्षमता होनी चाहिए, जैसे कि प्रेम, दर्द, संघर्ष और सफलता।

4. संवेदनशीलता,,,, साहित्यकार, कवि और गजल राइटर को समाज और जीवन की विभिन्न समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उन्हें अपने लेखन में व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए।

5.निरंतर अभ्यास,,, उन्हें अपने लेखन कौशल को विकसित करने के लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए और अपने काम को बेहतर बनाने के लिए आलोचना और प्रतिक्रिया को स्वीकार करना चाहिए।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने लेखन को साझा करना और अपने पाठकों के साथ जुड़ना।

लेखन प्रतियोगिताओं में भाग लेना ।लेखन प्रतियोगिताओं में भाग लेना और अपने काम को दूसरों के साथ साझा करन ।अपनी पुस्तक प्रकाशित करना और उसे पाठकों के बीच पहुंचाना ।साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेना और अपने काम को दूसरों के साथ साझा करना।

पाठकों के साथ जुड़ना और उनकी प्रतिक्रिया को समझना, जिससे अपने लेखन को और बेहतर बनाया जा सके।

डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह

घटिया गुणवत्ता के काम के कारण सड़कें कुछ ही घंटों में बड़े-बड़े गड्ढों से भर जाती हैं

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़शिा

भूबनेश्वर : ऐसी शिकायतें हैं कि खुर्दा जिले में प्रतापद्रपुर-कांटापड़ा संपर्क सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। स्थानीय लोगों, समाजसेवी व खोर्धा वार्ड सदस्य निरंजन भोला ने न्यूज के माध्यम से मुख्यमंत्री को घटना की जानकारी दी, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संजय कुमार त्रिपाठी व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. अरविंद ढाली को भी घटना की जानकारी दी। कांटापाड़ा-प्रतापपुररुद्रपुर संपर्क सड़क की। सड़क पर चलते लोगों को देखकर डर लगता है। हम यह बात सड़क के बीच में नहीं कह रहे हैं, ऊपर से चिकनी और अंदर से खोखली, ऐसा शोर मचाने वाले लोग कहते हैं। लोगों की यातायात सुविधा के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर 2.28 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। घटिया गुणवत्ता के काम के कारण सड़कें कुछ ही घंटों में बड़े-बड़े गड्ढों से भर जाती हैं। अब देखना यह है कि कांटापड़ा को प्रताप रुद्रपुर से जोड़ने वाली आरडी सड़क पर सरकार कब ध्यान देगी और इसकी मरम्मत कब होगी।

कोई किसे कैसे पाए ...!

द्रुम के भ्रम में हलाकान हो रहीं गृहस्थी,
न जाने किस-किसकी मिट रहीं हैं
हस्ती।
अब प्यार, प्यार न रहा सौदागर हो गया,
धन-दौलत के जाल में उलझा खो गया।
कौन कर रहा है कमज़ोर इस प्यार को,
जो तरस जाते हमेशा उनके दीदार को।

द्रुम के भ्रम में हलाकान हो रहीं गृहस्थी,
न जाने किस-किसकी मिट रहीं हैं
हस्ती।
तुम कैसे कर लेती हो इतनी भी हिम्मत,
छीनकर गायब करते हो उसकी कीमत।
इतनी विभत्सता कहाँ से उठा के हो
लाए,
रोम-रोम सिसक रहा कोई किसे कैसे
पाए।

संजय एम तराणेकर

सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खतरनाक मंसूबों से योगी और अखिलेश दोनों को सावधान रहना होगा !

@ कमलेश पाण्डेय/वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक

समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और दलित नेता रामजी लाल सुमन ने मेवाड़ के प्रतापी राजपूत शासक राणा सांगा को गद्दार बताते हुए जो विवादस्पद बयान दिया है, और क्षत्रियों की अखिल भारतीय 'करणी सेना' ने जिस तरह से उसे जातीय नायकों के अपमान का विषय ठहराते हुए श्री सुमन के घर पर धावा बोल दिया था, उस पर जारी प्रशासनिक और सियासी खानापूर्ति से यदि भारत गृहयुद्ध की आग में झुलस जाए तो किसी को हैरत नहीं होना चाहिए | क्योंकि यह सबकुछ पहले अमेरिकी-पाकिस्तानी एजेंडे और अब चीनी-बंगलादेशी एजेंडे के अनुरूप हो रहा है, जिसे भारत के कथित सेक्यूलर दलों के पृष्ठ पोषक अरब देशों का समर्थन प्राप्त है |

समझा जाता है कि जब-जब भारत अपनी सही रणनीति के बल पर विकास की गति को प्राप्त करता है, तब-तब हमारे विघ्न संतोषी कुछ राजनेता विदेशी ताकतों की शह पर यहाँ जातीय और सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं | यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि यहाँ की सियासी बयानबाजियां और उससे जुड़े साक्ष्य इस बात की चुगली करते हैं | ऐसे में सुलगता हुआ सवाल है कि आखिर वोट बैंक की कुत्सित राजनीति में निर्लज्ज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कबतक शांतिप्रिय भारतीय समाज को झुलसाया जाता रहेगा | क्योंकि कभी बादशाहों के इशारे पर, कभी ब्रिटिश नौकरशाहों के तिकड़म पर और आज भारत के अपने ही राजनेताओं की शर्मनाक शतरंजी चालों पर एक समाज को दूसरे समाज से भिड़ाया जाता है और अपना-अपना राजनीतिक उल्लू सीधा किया जाता है |

बता दें कि भारत में वामपंथियों की राजनीति वर्गवादी झड़प के हालात पैदा करके, समाजवादियों की राजनीति जातिवादी संघर्ष के हालात पैदा करके और कांग्रेसियों-राष्ट्रवादियों की राजनीति सांप्रदायिक दंगे के हालत पैदा करके खूब फली-फूली ! लेकिन विकास के पैमाने पर भारत अपने पड़ोसी देश चीन से 1987 में आगे बढ़कर भी बाद के वर्षों में निरंतर पिछड़ता चला गया | यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन जैसे राजनेता एक बार फिर से विवादित बयान देकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं | ऐसे विषैले नेताओं के खिलाफ स्पष्ट कार्रवाई नहीं होने से प्रशासनिक सुचिता और न्यायिक दूरदर्शिता भी अब सवालों के घेरे में है !

आप मानें या न मानें, लेकिन मौजूदा विवाद की राजनीतिक कीमत सपा नेता अखिलेश यादव के मुकाबले भाजपा नेता और उत्तरप्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुछ अधिक अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि वह अभी सता में हैं | जिस तरह से आगरा में उनकी मौजूदगी को लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है, वह राजपूतों के खिलाफ अन्य समाज को भड़काने की गहरी साजिश है, जिसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सतर्क हो जाना चाहिए और करनी सेना की गैरकानूनी हरकतों पर यूपी में अविलंब रोक लगानी चाहिए | वहीं भाजपा को भी इस मसले को जरूरत से ज्यादा तूल देने से बचना चाहिए | क्योंकि यह सारी सुनियोजित बयानबाजी मुस्लिम शासकों के कुकृत्यों से दलित और ओबीसी हिन्दुओं का ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है, जिसे उसे समझना होगा और इसकी मजबूत रणनीतिक काट निकालनी होगी | यदि भाजपा और योगी इस मामले को ज्यादा तूल देते हैं तो लोकसभा चुनाव 2024 की तरह अखिलेश के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक गठजोड़ को मजबूती मिलेगी, वहीं भाजपा के डीपीए यानी दलित, पिछड़ा, अगड़ा गठजोड़ को भी सियासी धक्का लगेगा |

वहीं अखिलेश यादव को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब यूपी में दलित नेत्री मायावती उनकी पार्टी के लिए मजबूत चुनौती बनी हुईं थीं और मुस्लिम वोटर भी बसपा-सपा में लगभग आधा-आधा बंट गए थे तब भी राजपूत समाज उनका मजबूत वोट बैंक रहा था | उन्हें पता होना चाहिए कि यह पूरी राजपूत जाति पहले कांग्रेसियों और फिर समाजवादियों की मजबूत वोट बैंक रही है | यह बात दीगर है कि अब केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबल नेतृत्व के चलते राजपूत मतदाता भी राष्ट्रवादी मिजाज के हो चले हैं | इसलिए पूरी राजपूत जाति को सपा का विरोधी बना देना उनके लिए राजनीतिक नादानी साबित हो सकती है | इससे न केवल बसपा और कांग्रेस को सिर उठाने का मौका मिलेगा, बल्कि सवर्णों में भी उनका इमेज उनके पिता स्व.मुलायम सिंह यादव से ज्यादा खराब हो जाएगा |

ऐसा इसलिए कि हाल में ही सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने बौद्ध मठों के अवशेषों पर मन्दिरों के बने होने और उसे मुद्दा बनाने के जो खतरनाक संकेत दिए हैं, उससे साफ है कि वे अरब देशों और चीनी एजेंडे को देश में लागू करके सवर्ण हिन्दुओं को दलित हिन्दुओं और ओबीसी हिन्दुओं से भिड़ाने की योजना बना रहे हैं, ताकि हिन्दू-मुस्लिम दंगे की जगह जातीय दंगे शुरू हों और समाजवादियों के राजनीतिक आधार पर कोई आंच नहीं आए | भारतीय प्रशासन और न्यायपालिका को सिरफिरे नेताओं के इस खतरनाक इरादे से देश को बचाना होगा, अन्यथा महाभारत तय है |

कहना न होगा कि ये वही विदेशी एजेंट लोग हैं जिन्होंने 1977 में इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में मजबूत हो रहे भारत की गति पर ब्रेक लगवाई थी | तब मोरारजी देसाई पर अमेरिकी सीआईए एजेंट होने के आरोप लगे थे जो बाद में देश के प्रधानमंत्री तक बने | भले ही सरकार चलाने में विफल रहे और बदले गए | फिर इन्हीं जैसे नेता लोगों ने 1989 में राजीव गाँधी के नेतृत्व में मजबूत हो रहे भारत की गति पर ब्रेक लगवाई | और अब 2019 में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत हो रहे भारत की गति में ब्रेक लगवाने के लिए गृह युद्ध के हालात पैदा करने जैसी विषाक्त बयानबाजी कर रहे हैं |

बता दें कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने दो टूक कहा है कि "गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, वरना भारी पड़ेगा | अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो फिर हमें भी यह कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है | और जो लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो यदि मोहल्ले में जाकर ये प्रचार करना शुरू कर दें तो ये मामला बड़ा ही खतरनाक मामला बन सकता है |"

वहीं आगरा में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने करणी सेना को चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी 19 अप्रैल को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, जिसके बाद लड़ाई का मैदान तैयार होगा और दो-दो हाथ होंगे | एक तरफ 10 प्रतिशत लोग हैं और दूसरी तरफ 90 प्रतिशत सामाजिक न्याय की शक्तियां हैं, इसलिए विजय हमारी होगी | इस लड़ाई को कोई माई का लाल नहीं हरा सकता |

उन्होंने करणी सेना को फर्जी सेना कहा और पूछा कि अगर मुसलमान में बाबर का डीएनए है तो तुम्हारे अंदर किसका डीएनए है ये भी बता दो | उन्होंने आगे कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही एक बैठक हुई, जिसमें तोप तलवार हथियार रहे | उन्होंने याद दिलाया कि भरतपुर के राजा रहे सूरजमल की तलवार ने अंग्रेजों के सिर काटे पर कभी किसी गरीब कमजोर पर उनकी तलवार नहीं चली | क्षत्रिय का तो धर्म होता है कि कमजोर की रक्षा करना है और गरीब की मदद करना है |

वहीं वह आगे बोलते नजर आए कि हमने तो तीन सेना सुनी है- थल सेना, वायु सेना और जल सेना, लेकिन ये चौथी सेना कहां से पैदा हो गई है ? करणी सेना के लिए सांसद ने कहा कि हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है | अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है | ये जो करणी सेना के रणबांकुरे हैं वो हिंदुस्तान की सरहद पर चले जाओ और चीन से हमको बचाओ | वरना दुनिया में तुमसे ज्यादा नकली कोई और हो नहीं सकता |

वहीं सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने करनी सेना वालों को ललकारते हुए कहा कि "ये लड़ाई हम लोगों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई लंबी है | ये लड़ाई उन लोगों से है जिन लोगों ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री न रहने पर मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धुलवाया था | ये लड़ाई उन लोगों से है जिन्होंने राजस्थान की विधानसभा में दलित नेता प्रतिपक्ष के मंदिर में चले जाने से मंदिर को गंगाजल से धुलवाया था |

श्री सुमन ने कहा कि, "हम कहते है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता है, वो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है | हम कहना चाहते हैं कि जब-जब इस देश की इज्जत दांव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित किया है कि इस देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिन्दू को उतनी मोहब्बत मुसलमान को भी है | उन्होंने सवाल उठाया कि देश में वक्फ को लेकर कानून बनाया गया, जब किसी धर्म महजब की कमेटी बनती है तो उस कमेटी में उसी धर्म के लोग रहते हैं ? वक्फ में तीन सनातनी रहेंगे, भाई क्यों रहेंगे और बौद्ध मठ का मामला चल रहा है ?

आपको बता दें कि इससे पहले सपा सांसद ने राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था | हालांकि उनके इस बयान को राज्यसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया, लेकिन इसे लेकर करणी सेना में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है | करणी सेना ने बीते शनिवार को राणा सांगा की जयंती पर आगरा में रक्त स्वाभिमान रैली भी की थी | इस दौरान भारी संख्या में लोग खुलेआम सड़कों पर तलवारें लहराते हुए दिखाई दिए थे | इससे साफ है कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने संसदीय सदन में ऐसा बयान दिया जिससे पूरे देश में संग्राम छिड़ गया | सपा सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, हंगामा और बवाल हुआ था |

वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करणी सेना के आगरा में प्रदर्शन और धमकी देने पर कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। हम आगरा जाएंगे। हमें एनएसजी हटने का कोई मलाल नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था जीरो है। उद्योगपति डरे हुए हैं। वह सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं। वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी सिर्फ एक सपना है। अखिलेश यादव ने आगरा में करणी सेना के प्रदर्शन और सपा नेताओं को धमकी देने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जो डरपोक हैं, वह एनएसजी रखे हैं। मुझे एनएसजी वापस हटने कोई मलाल नहीं। हम लोग महाराजाओं के खिलाफ नहीं है। राजा की कोई जाति नहीं होती है। हम आगरा जाएंगे। हम डरने वाले नहीं है। दिल्ली वाले लखनऊ वालों को चकमा देने में लगे हैं। अब चलाचली की बेला है तो डंडे की बात कर रहे हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि सोशल मीडिया पर कुछ न लिखें।

वहीं उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन का बचाव करते हुए कहा है कि रामजी लाल सुमन ने भी इतिहास का वो पन्ना पलट दिया, जहां कुछ ऐसा लिखा था | श्री सुमन समाजवादी पार्टी से मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं | जब उनकी टिप्पणी पर विवाद होना शुरू हुआ, तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका बचाव किया | उन्होंने कहा कि, "रामजी लाल सुमन ने जो कहा वह इसलिए कहा क्योंकि हर कोई इतिहास के पन्ने पलट रहा है | बीजेपी के नेता औरंगज़ेब पर बहस करना चाहते हैं, तो रामजी लाल सुमन ने भी इतिहास का वो पन्ना पलट दिया, जहां कुछ ऐसा लिखा था |"

इसके बाद जब एक दिन रामजी लाल सुमन के आवास पर करनी सेना की अगुवाई में तोड़फोड़ हुई, तब भी अखिलेश यादव ने बीजेपी को इसके लिए घेरा और कहा कि, "भाजपा ने हमेशा अपने राजनीतिक फायदे और नफरत फैलाने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटा है | इसलिए समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आवास के बाहर हुई घटना निंदनीय है |" अखिलेश यादव ने कहा कि, "रामजी लाल सुमन दलित सांसद हैं और उनके पास काफी अनुभव है | उनके आवास पर तब हमला हुआ जब खुद मुख्यमंत्री ज़िले में थे | इसका मतलब यह हुआ कि यह हमला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति से हुआ | ज़ीरो टोलरेंस की बात करने वालों का टोलरेंस ही ज़ीरो हो गया है |"

वहीं रामजी लाल सुमन के आवास पर हुई तोड़फोड़ की निंदा समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी की है | उन्होंने कहा है कि, "अगर हम उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो यहां सड़कों पर बम फट रहे हैं, यहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, यह सब सरकार की ज़िम्मेदारी है | अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है | आप समाज और युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं ? जिस तरह का उपद्रव पूरे उत्तर प्रदेश में मचाया जा रहा है, उस पर सरकार को सख़्त कार्रवाई करनी चाहिए. कहीं न कहीं यह सरकार के द्वारा कराई गई हरकत है |"

इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राणा सांगा विवाद पर राजनीति थमने का नाम ही नहीं ले रही है | राणा सांगा पर बयान देने के बाद बुधवार (26 मार्च 2025) को प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर जमकर हंगामा हुआ | करणी सेना के कार्यकर्ता भारी संख्या में रामजी लाल सुमन के घर के बाहर इकट्ठा हुए और उनके घर में घुसने की कोशिश की | उनके आवास पर हुए हंगामे के दौरान पुलिस और करणी सेना के बीच झड़प भी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए |

इस तोडफोड़ के बाद करणी सेना के नेता महिपाल मकराना ने कहा, "अभी तो यह एक ट्रेलर है | ऐसे व्यक्तियों को मुंहतोड़ जवाब हमें बहुत पहले देना चाहिए था | जिसमें हम बहुत लेट हो गए | अगर रामजी लाल सुमन की सदस्यता रद्द नहीं की गई, तो एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा |"

बता दें कि ये विवाद सांसद रामजी लाल सुमन की उस एक टिप्पणी के बाद शुरू हुआ जिसमें गत 21 मार्च 2025 को उन्होंने राज्यसभा में राणा सांगा पर एक विवादित टिप्पणी की थी और राणा सांगा को गद्दार तक बता डाला था | उनकी इस टिप्पणी के बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उनके ख़िलाफ़ उत्तरप्रदेश के अलावा राजस्थान और मध्यप्रदेश में भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है | बता दें कि उस दिन राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर बहस चल रही थी, जब रामजी लाल सुमन ने इसमें हिस्सा लिया और इस तरह का एक विवादित बयान दिया, जिससे यह सारा विवाद शुरू हुआ |

उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मुग़ल सम्राट बाबर को भारत में आमंत्रित किया था | उन्होंने कहा कि, "ये तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वे तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते हैं, सूफी-संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं |"

इससे आगे उन्होंने सवाल उठाए कि बाबर को भारत में कौन लाया था और कहा कि, "इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो | ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए |" उन्होंने आगे कहा कि, "हम लोग बाबर की तो आलोचना करते हैं लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते हैं |"

इसके बाद जब विवाद शुरू हो गया, तब एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में रामजी लाल ने अपने इस बयान पर सफाई भी दी थी | उन्होंने कहा कि, "उस दिन संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज के दौरान मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था | मेरा मक़सद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था | मेरा बयान न तो किसी जाति के ख़िलाफ़ था, न किसी वर्ग के ख़िलाफ़ था और न ही किसी धर्म के ख़िलाफ़ था |"

हालांकि वह अभी भी अपने इस बयान पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि वह अपने इस जीवन में तो माफ़ी नहीं मांगेंगे | एक अन्य न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि, "जहां तक माफ़ी का सवाल है, तो इस जन्म में तो मैं माफ़ी मांगूंगा नहीं | माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है | लोगों को सही बातें सुनने की आदत डालनी चाहिए |"

यही वजह है कि रामजी लाल सुमन की इस टिप्पणी के बाद तुरंत बीजेपी ने इसकी निंदा करनी शुरू कर दी | बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने उनके इस बयान पर अपना विरोध जताया | केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि, "भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी भी बाबर और राणा सांगा दोनों की तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे | राणा सांगा ने लोगों में स्वतंत्रता की अलख जलाई थी | उन्होंने भारत को तो गुलाम होने से बचाया ही था, साथ ही भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया था | कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे दिल वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन इन चर्चाओं की कोई गुंजाइश नहीं है |"

वहीं राजस्थान की उप-मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी रामजी लाल सुमन की टिप्पणी की आलोचना की है | उन्होंने कहा कि, "संसद में उन सांसद का बयान ग़लत था और उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था | उनको इतिहास की कोई जानकारी ही नहीं है | राणा सांगा ने मेवाड़ और राजस्थान के लिए बहुत कुछ किया है | विपक्ष बिना किसी रिसर्च और जानकारी के महाराणा प्रताप और राणा सांगा के ख़िलाफ़ ऐसे बयान देता है | उन्होंने मातृभूमि के लिए इतने युद्ध लड़े हैं | ऐसे व्यक्तित्वों के लिए ऐसे ओछी टिप्पणी करना उचित नहीं है |"

वहीं बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने भी रामजी लाल सुमन की टिप्पणी की आलोचना की और कहा कि, "ये एक फैशन बन गया है | चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष में कोई और...ये सब खुद को खबरों में बनाए रखने या लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहते हैं |" उन्होंने आगे कहा कि "जिस तरह से देश के महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि वे मानसिक रूप से अस्थिर हो गए हैं | वे देश के इतिहास को गलत बता रहे हैं | मुस्लिम आक्रमणकारियों को जिन्होंने धर्मांतरण किया और मंदिरों को नष्ट किया, अब उनका महिमामंडन किया जा रहा है |"

यही वजह है कि रामजी लाल सुमन की इन टिप्पणियों के बाद अब कानूनी कार्रवाई का दौर भी शुरू हो गया है | इस बारे में आर्य संस्कृति कंजर्वेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट अजय प्रताप सिंह ने सुमन और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के ख़िलाफ़ सिविल सूट (दीवानी मुकदमा) दायर किया है और कहा है कि, "पिछले कुछ दिनों से हमें अख़बारों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि रामजी लाल सुमन लगातार राणा सांगा को गद्दार कह रहे हैं | वह लोगों में झूठी बातें फैला रहे हैं | इस संबंध में मैंने सिविल मुक़दमा दायर किया है, जिसमें मैंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन को नामजद किया है |"

समझिए आखिर कौन हैं रामजी लाल सुमन, जिनके सियासी मंसूबे हिन्दुओं के लिए बहुत ही खतरनाक हैं ?

विवादास्पद टिप्पणी करने वाले राजनेता रामजी लाल सुमन उत्तर प्रदेश की अलग-अलग सीटों से चार बार लोकसभा सांसद भी रहे हैं | फिलवक्त वह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं | पिछले साल राज्यसभा में उनकी नियुक्ति ने अखिलेश यादव के 'पीडीए' फॉर्मूला को मजबूती दी थी | क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलितों तक पार्टी की पहुंच को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव का यह एक रणनीतिक कदम था | बता दें कि रामजी लाल सुमन का राजनीतिक करियर बहुत लंबा और विविधतापूर्ण रहा है | उन्होंने पहली बार 1977 में कांग्रेस विरोधी जनता पार्टी के टिकट पर फिरोज़ाबाद लोकसभा सीट से संसद का रास्ता तय किया | इसके बाद उन्होंने इस सीट से जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ा और 1989 में भी यहां से सांसद चुने गए | फिर उन्होंने जनता दल के विभाजन से बनी यूपी की समाजवादी पार्टी की ओर रुख़ किया और चुनाव लड़ते हुए फिरोज़ाबाद लोकसभा सीट से ही 1999 और 2004 में सांसद चुने गए | इसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें हाथरस लोकसभा सीट से 2014 और 2019 में चुनाव लड़ाया, लेकिन वह जीतने में नाकाम रहे | यही वजह है कि अब उनके तेवर तल्ख हैं और बीजेपी के समर्थकों के खिलाफ ज्यादा मुखर हैं | जबकि वह 1990-91 में चंद्रशेखर सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे | इसके अलावा, पिछले साल उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल करने के लिए राज्यसभा में एक निजी विधेयक भी पेश किया था, जिससे समझा जा सकता है कि वह दलित-मुस्लिम गठजोड़ और ओबीसी-मुस्लिम समीकरण जिसे एम-वाई समीकरण भी समझा जाता है, के बीच एक नया सम्बन्ध सेतु बनकर उभरे हैं |

जानिए आखिर कौन थे राणा सांगा, जिन्हें राजपूत समाज अपना गौरव मानता है ?

बता दें कि राणा सांगा मेवाड़ के बहादुर शासक थे | उन्होंने खानवा में मुग़लों के ख़िलाफ़ युद्ध लड़ा था | दरअसल मेवाड़ के राजपूत शासक रहे संग्राम सिंह को ही लोकप्रिय तौर पर राणा सांगा के नाम से जाना जाता है | उनके पिता का नाम राजा रायमल और माता का नाम रानी रतन कंवर था | वे उनके तीसरे बेटे थे | उनके पैदा होने की असली तारीख़ के बारे में तो किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वह वर्ष 1482 में पैदा हुए थे | ऐसा बताया जाता है कि हालात को देखते हुए सत्ता पर काबिज़ होने के लिए उन्हें अपने बड़े भाइयों- कंवर पृथ्वीराज और जगमल से ही युद्ध करना पड़ा था, जिसके बाद वर्ष 1509 में वे मेवाड़ की गद्दी को हासिल करने में कामयाब हुए | हालाँकि जब वह अपने उत्कर्ष के चरम पर थे, तब उनका साम्राज्य मौजूदा राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था | वहीं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के साथ-साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाक़ों पर भी उनका शासन था | चूँकि राणा सांगा की तारीफ़ ख़ुद मुगल सम्राट बाबर ने भी की थी | इसलिए उनकी शूरवीरता असंदिग्ध है | वहीं आमतौर पर उन्हें राजपूतों को एकजुट करने वाले एक दूरदर्शी राजा के रूप में भी देखा जाता है | ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा ने खानवा के मैदान पर बाबर के ख़िलाफ़ युद्ध के अलावा कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा | हालांकि उन्होंने दिल्ली सल्तनत के दौरान लोधी सम्राज्य के कुछ इलाक़ों छापा मारा, जिसमें वह कामयाब भी हुए थे |

देखिए सरकारी किताबों में क्या लिखा है राणा सांगा और उनके समकालीन मुसलमान शासकों के बारे में

राजस्थान की 10वीं कक्षा की इतिहास की किताब के अनुसार, क्षत्रिय राजा राणा सांगा ने 1517 में खतौली की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था | इसके तत्काल बाद सांगा की सेना ने लोदी की सेना को बाड़ी (धौलपुर) की लड़ाई में भी पराजित किया था | वहीं नेशनल स्कूल ऑफ़ ओपन स्कूलिंग के पाठ्यक्रम के मुताबिक़, लोदी शासन में पंजाब के बड़े हिस्से का गवर्नर (अफ़ग़ान) दौलत ख़ां लोदी का इब्राहिम लोदी से संघर्ष बढ़ रहा था | इसलिए राणा सांगा भी मौके का फायदा उठाकर उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने कोशिश में जुटे हुए थे | इसी के सिलेबस के अनुसार, इन दोनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने को कहा था | शायद राणा सांगा और दौलत खां लोदी के आमंत्रण ने ही क्रूर मुस्लिम शासक बाबर की प्रशासनिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाया होगा | इसी के एक अन्य पाठ्यक्रम में स्पष्ट लिखा है कि बाबर ने भिड़ा (1519-20), सियालकोट (1520), लाहौर (1524) पर कब्ज़ा कर लिया और अंत में 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना का पानीपत के मैदान में सामना हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी | वहीं राजस्थान की 10वीं कक्षा की इतिहास की किताब के अनुसार, राणा सांगा का निधन 30 जनवरी 1528 को दौसा में हुआ था | मंडलगढ़ में उनका एक स्मारक आज भी मौजूद है |

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023